कल्पमेधा

जैसे एक फूल बहुत प्यारा और सुंदर है, पर खुशबू नहीं है। ठीक वैसे ही किसी की कही हुई अच्छी बातें व्यर्थ हैं, अगर वह उनको अमल में नहीं लाता।
– महात्मा बुद्ध

मौसम का कहर

उत्तर प्रदेश में आंधी-तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से जैसे हालात पैदा हुए, उसने एक बार फिर यही दर्शाया कि मौसम की मार से बचाव के लिए एहतियात बरतने से लेकर सटीक पूर्वानुमान को लेकर तकनीकी स्तर पर अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। राज्य के कई इलाकों में बुधवार की शाम को तेज आंधी-तूफान, बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि एक तरह से कहर बरपा रही थी और आम लोग उसके सामने लाचार थे। कई जगहों पर तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई, कितनी ही जगहों पर भारी पेड़ उखड़ कर वाहनों पर गिर गए और सड़कों के किनारे लगे बोर्ड उड़ कर तेज रफ्तार से जमीन पर गिरे। करीब चौबीस घंटों के दौरान करीब सौ लोगों की जान चली गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। कई जिलों में दो हजार से ज्यादा गांवों में बिजली गुल हो गई। कुदरत की इस कहर के बाद मौसम विभाग ने राज्य के अड़तीस जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की आशंका के मद्देनजर पीली चेतावनी जारी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूर्वानुमानों के बावजूद कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जिसमें तूफान या बिजली गिरने की घटनाएं आम लोगों पर कहर बन कर टूटती हैं।

जाहिर है, मौसम की अपनी गति होती है और प्रकृति में उथल-पुथल के नतीजे में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष अचानक मौसम का रुख बिगड़ने की आशंका के बावजूद आम लोग इससे बचाव के लिए एहतियात नहीं बरत पाते। इसका खमियाजा यह सामने आता है कि जिन हालात में कुछ लोगों की जान बच सकती थी, उसमें नाहक ही कइयों की जान चली जाती है। राज्य में मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवात के ढांचे और दक्षिण राजस्थान से आ रही हवाओं के प्रभाव से वहां कई जगहों पर अस्सी से सौ किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलीं। नतीजतन, बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ। कई जगहों पर न केवल घरों की छत उड़ गई, बल्कि लोगों के लिए पांव टिकाना भी मुश्किल था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे मौसम में बचाव को लेकर जरूरी प्रशिक्षण के अभाव का नुकसान आम लोगों को किस स्तर पर उठाना पड़ता है।

संभव है कि पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के साथ-साथ मौसम साफ होने लगे और उसके बाद तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो, लेकिन इसके साथ यह भी सच्चाई है कि साल के इन महीनों में कई बार तेज रफ्तार में चलने वाला तूफान और ओलावृष्टि कई स्तर पर आम लोगों के लिए व्यापक क्षति और खतरे का वाहक बनते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हर बार यह देखा जाता है कि एक ओर तूफान में पेड़ या घर गिरने जैसी घटनाओं की वजह से कई लोग मारे जाते हैं, तो दूसरी ओर घर से लेकर फसलों तक को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा, इस बात का अध्ययन किए जाने की जरूरत है कि हाल के वर्षों में बिजली गिरने की घटनाओं में तेज इजाफा क्यों हुआ है, क्योंकि अकेले इस कारण से भी देश भर में काफी संख्या में लोगों की जान जा रही है। मौसम में तेज उतार-चढ़ाव को रोकना भले ही संभव न हो, लेकिन उससे बचाव के कुछ मामूली उपाय करके जानमाल के नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है।

अशांत मणिपुर

मणिपुर तीन साल से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब ढाई सौ ज्यादा लोग हिंसा में जान गंवा चुके हैं। हजारों लोगों के विस्थापन से राज्य का सामाजिक ताना-बाना टूट-सा गया है। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद आखिर क्या वजह है कि उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग सका है। बीते बुधवार को उग्रवादियों ने एक बार फिर हमला कर तीन लोगों की हत्या कर दी। कांगपोकपी जिले में अंधाधुंध गोलीबारी में चार नागरिक भी घायल हो गए। इस घटना से नाराज नागरिकों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को बंद कर दिया। गौरतलब है कि यह मार्ग मणिपुर को न केवल नगालैंड से, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी जोड़ता है। इस समय राज्य में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है, वह बेहद चिंताजनक है। एक बार फिर हुई हिंसा से साबित होता है कि सुरक्षा एजंसियां सशस्त्र समूहों को नियंत्रित कर पाने में विफल रही हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप का भी कोई असर नहीं दिखता। समझौते भी औपचारिक बन कर रह गए हैं।

दरअसल, मणिपुर में शांति बहाली का कोई भी प्रयास इसलिए भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि परस्पर विरोधी समूहों को कायदे से अब तक संवाद की मेज पर नहीं लाया जा सका है और न ही शायद इसकी जरूरत महसूस की गई। यही वजह है कि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे सशस्त्र समूहों में एक दूसरे के प्रति संदेह और अविश्वास खत्म नहीं हो रहा। यह निराशाजनक ही है कि जब भी राज्य में थोड़ी बहुत स्थिति सुधरती दिखाई देती है, कोई न कोई उग्रवादी हमला राज्य को हिंसा की आग में झोंक देता है। सरकार अगर अलग-अलग समुदायों के प्रतिनिधियों को संवाद के लिए राजी करती, तो शायद उनके बीच भरोसा कायम होता। मगर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों के भीतर इस मसले पर कोई संजीदगी नहीं दिखती। आज राज्य में शांति प्रबंधन की नहीं, बल्कि उसे स्थापित करने के लिए सक्रिय होने की जरूरत है। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों को मिल कर काम करना होगा, अन्यथा मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के घातक नतीजे सामने आ सकते हैं।

परीक्षाओं की जटिलता और चुनौतियां

नीट जैसी महत्त्वपूर्ण परीक्षा का रद्द होना चिंता का विषय है। मगर आलोचनाओं के बावजूद राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के काम की जटिलता और उसकी चुनौतियों को भी समझने की जरूरत है।

एम जगदीश कुमार

भारत में प्रवेश परीक्षा केवल एक परीक्षा भर नहीं होती, बल्कि यह महीनों या अक्सर वर्षों की अनुशासित तैयारी की परिणति होती है। जब ऐसी परीक्षा बाधित हो जाती है, जैसा कि नीट 2026 के संदर्भ में सामने आया है, तो यह निस्संदेह चिंता का विषय है। पर्चाफोड़ संबंधी आशंकाएं निर्मूल नहीं हैं। मगर इसके कारण परीक्षा रद्द होने से ईमानदारी से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और उनका साथ देने वाले अभिभावकों के न केवल सपने टूटे, बल्कि उनकी सारी मेहनत पर भी पानी फिर गया। उनके लिए यह अनिश्चितता चिंताजनक है। इस मुद्दे पर किसी भी तरह का मार्गदर्शन उनके प्रति सहानुभूति की भावना से होना चाहिए। इसके बाद जो आलोचना सामने आई है, वह समझ में आती है। फिर भी, यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) को जो कार्य करना होता है, उसके पैमाने और जटिलता को भी समझा जाए।

हर वर्ष एनटीए परीक्षाओं की एक विस्तृत शृंखला आयोजित करता है- जेईई (मेन), नीट (यूजी) और सीयूईटी (यूजी) जैसे स्नातक प्रवेश से लेकर सीयूईटी (पीजी) और सीमैट जैसे स्नातकोत्तर परीक्षण तथा यूजीसी-नेट जैसी पात्रता परीक्षा तक। इन परीक्षाओं में हर वर्ष लगभग 80 लाख अभ्यर्थी शामिल होते हैं, जो कभी-कभी एक करोड़ से अधिक तक पहुंच जाते हैं। कई अभ्यर्थी एक से अधिक परीक्षा में बैठते हैं, जिससे संचालन संबंधी जटिलता और बढ़ जाती है। विषयों की विविधता, अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि, परीक्षा प्रारूपों और समय-सीमाओं की भिन्नता इस पूरी प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बना देती है।

इन परीक्षाओं का प्रबंधन बड़े पैमाने का 'लाजिस्टिक' और सुरक्षा संचालन भी है। इसमें हजारों केंद्रों का समन्वय, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित साज-संभाल करना, अभ्यर्थियों की पहचान का सत्यापन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का संचालन, शिकायतों का निपटान और सघन समय-सीमा में परिणाम तैयार करना शामिल है। ऐसी जटिल व्यवस्था को निरंतरता के साथ संचालित करना राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है। इसे समझने और गंभीरता से भी लेने की जरूरत है।

इसी संदर्भ में नीट 2026 की स्थिति को राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी के व्यापक रिकार्ड के साथ भी देखा जाना चाहिए। इसकी स्थापना के बाद से पर्चाफोड़ संबंधी चिंताओं के कारण पूरी परीक्षा रद्द होने की घटनाएं बहुत कम रही हैं, जिनमें यूजीसी-नेट जून 2024 का मामला और वर्तमान प्रकरण अपवाद हैं। यूजीसी-नेट के मामले में परीक्षा को संभावित गड़बड़ी के संदेह में रद्द किया गया और दोबारा आयोजित किया गया। इसी प्रकार, नीट (यूजी) 2024 में व्यापक आरोपों के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में परीक्षा रद्द करने की सिफारिश नहीं की और यह कहा कि किसी तंत्रगत उल्लंघन का पर्याप्त प्रमाण सामने नहीं आया।

विगत वर्षों के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी ने प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में कई ठोस काम किए हैं, जैसे पहचान सत्यापन को बेहतर बनाना, संचालन संबंधी नियमों को सख्त करना और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करना। गौरतलब है कि लाखों अभ्यर्थी परीक्षाएं देते हैं, उत्तर कुंजी देखते हैं, आपत्तियां उठाते हैं और निर्धारित समय-सीमा के भीतर परिणाम प्राप्त करते हैं। यह दर्शाता है कि यह व्यवस्था विशिष्ट पैमाने पर

काम करते हुए लगातार विकसित और अनुकूलित हो रही है।

हालांकि, नीट का अनुभव यह भी दर्शाता है कि एक ही दिन एक देशव्यापी परीक्षा को कागज-कलम स्वरूप में आयोजित करना जोखिम से कम नहीं है। बाईस लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्रों की तैयारी, छपाई, भंडारण

> **नीट का अनुभव यह भी दर्शाता है कि एक ही दिन, एक ही देशव्यापी परीक्षा को कागज-कलम स्वरूप में आयोजित करना जोखिम से कम नहीं है। बाईस लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नपत्रों की तैयारी, छपाई, भंडारण और उनके परिवहन की प्रक्रिया व्यापक है। इस पैमाने पर एक छोटी-सी चूक भी एक बड़ा प्रभाव डाल सकती है और सार्वजनिक विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। जब इतना कुछ एक ही दिन पर निर्भर हो जाता है, तो व्यवस्था स्वाभाविक रूप से नाजुक हो जाती है। इसलिए नीट 2026 से जो सबक मिलता है, वह यह है कि एकल बिंदु पर निर्भरता को कम किया जाए।**

और उनके परिवहन की प्रक्रिया व्यापक है और हर चरण संभावित कमजोरियों को जन्म देता है। ऐसे में एक छोटी-सी चूक भी बड़ा प्रभाव डाल सकती है और सार्वजनिक विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। जैसा कि पिछले दिनों देखा गया। जब इतना कुछ एक ही दिन पर निर्भर हो जाता है, तो व्यवस्था स्वाभाविक रूप से नाजुक हो जाती है। इसलिए नीट 2026 से जो सबक मिलता है, वह यह है कि एकल बिंदु पर निर्भरता को कम किया जाए। यह अब जरूरी हो गया है।

हालांकि इसका परखा हुआ एक विकल्प पहले से मौजूद है। एनटीए ने जेईई (मेन) और सीयूईटी जैसी बड़ी परीक्षाओं को कंप्यूटर-आधारित मोड में अनेक दिनों और सत्रों में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। यह तरीका भौतिक रूप से प्रश्नपत्रों को लाने-ले जाने की चिंता को काफी हद तक कम कर देता है। इस लिहाज से देखें, तो प्रश्नपत्रों की बड़े पैमाने पर छपाई और परिवहन समाप्त होने से एक बड़े जोखिम को समाप्त किया जा सकता है। इस पर अमल होना चाहिए।

बहु-सत्रीय परीक्षा प्रणाली लचीलापन भी प्रदान करती है। यदि किसी विशेष सत्र में व्यवधान आता है, तो उसे स्थानीय स्तर पर दुरुस्त किया जा सकता है, वह भी पूरे परीक्षा चक्र को प्रभावित किए बिना। लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ी राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में यह क्षमता अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। निस्संदेह, कंप्यूटर-आधारित परीक्षा अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है, परंतु अनुभव बताता है कि इन्हें प्रबंधित किया जा सकता है और इससे संपूर्ण प्रणाली अधिक सुदृढ़ बनती है।

डा के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने एक स्पष्ट और संतुलित मार्गदर्शन किया है। समिति के प्रमुख सुझावों में बड़े पैमाने की परीक्षाओं के लिए बहु-सत्रीय प्रणाली और पारदर्शी सामान्यीकरण पद्धति का उपयोग शामिल है। साथ ही, कंप्यूटर-सहायता प्राप्त सुरक्षित कागज-कलम परीक्षा (सीपीपीटी) का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रूप से केंद्रों तक भेज कर वहीं मुद्रित किया जाए, जिससे उनके साज-संभाल और परिवहन से जुड़े जोखिम कम हों तथा पर्चाफोड़ जैसी घटनाएं न हों। इन सभी सुझावों को मिला कर देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि नीट को बहु-सत्रीय कंप्यूटर-आधारित प्रणाली की ओर चरणबद्ध तरीके से ले जाना अब आवश्यक है। ऐसी व्यवस्था में पूरी परीक्षा रद्द किए बिना सभी अड़चनों का समाधान संभव होगा। इससे निरंतरता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। विद्यार्थियों का भी भरोसा बढ़ेगा।

इन सबके अलावा एक चिंता सत्रों के बीच निष्पक्षता की भी है। बहु-सत्रीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्र में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन इसे सामान्यीकरण के माध्यम से संतुलित किया जाता है। यह सांख्यिकीय पद्धति सुनिश्चित करती है कि किसी भी छात्र को उसके सत्र के कारण लाभ या हानि न हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी पहले से ही जेईई (मेन) और सीयूईटी जैसी परीक्षाओं में इस पद्धति का सफल उपयोग कर रही है।

वास्तव में, सामान्यीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जो 'सत्रीय लाभ' से छात्रों की रक्षा करती है और विभिन्न सत्रों के अंकों को एक समान आधार पर लाती है। इसकी मूल शर्त पारदर्शिता है। इसमें यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाती है। विद्यार्थियों की इतनी बड़ी संख्या वाले देश में एक सशक्त राष्ट्रीय परीक्षा संस्था की आवश्यकता अनिवार्य है। इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी को व्यापक आलोचना के माध्यम से कमजोर करने के बजाय ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि नीट के लिए अधिक सुदृढ़ और लचीले तौर-तरीके अपनाए जाएं और ऐसी रूपरेखा तैयार की जाए जो भारत के पैमाने के अनुरूप हो।

धैर्य की शक्ति

मेघा राठी

अक्सर हम बचपन से एक वाक्य सुनते आए हैं 'विपरीत परिस्थितियों से डरो नहीं, उनसे लड़ो।' यह वाक्य सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगता है और कई बार लोगों को कठिन समय में हिम्मत भी देता है। अगर गहराई से देखा जाए, तो हर परिस्थिति से 'लड़ना' हमेशा सही तरीका नहीं होता। कई बार परिस्थितियों से लड़ने की जगह उन्हें समझना अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम केवल लड़ने की मानसिकता के साथ किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा ध्यान समस्या के मूल कारण को समझने के बजाय सिर्फ उससे किसी तरह बाहर निकलने पर केंद्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ही असंतुलित अवस्था में होते हैं। तनाव, घबराहट और असुरक्षा की भावना हमारे निर्णय को प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप हम जो भी कदम उठाते हैं, वे कई बार जल्दबाजी में उठाए गए होते हैं। ऐसे प्रयास न केवल समस्या का समाधान नहीं करते, बल्कि कई बार हमें और अधिक उलझन में डाल देते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम विपरीत परिस्थितियों को केवल संघर्ष का मैदान न मानें, बल्कि उन्हें समझने और सीखने का अवसर भी समझें।

दुनिया मेरे आगे

विपरीत परिस्थितियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन उनका स्वरूप और प्रभाव हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए आर्थिक कठिनाई सबसे बड़ी समस्या हो सकती है, तो किसी के लिए संबंधों में तनाव या मानसिक दबाव। यही कारण है कि एक ही सलाह सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं हो सकती। हम अक्सर लोगों को सामान्य रूप से यह कह देते हैं कि 'घबराओ मत, मजबूत बनो, परिस्थितियों से लड़ो।' मगर यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर व्यक्ति की मानसिक क्षमता और संवेदनशीलता अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति स्वभाव से अत्यंत संवेदनशील होता है। ऐसी स्थिति में जब वह किसी कठिन दौर से गुजर रहा होता है, तो उसका मन पहले ही बहुत अधिक दबाव में होता है। अगर ऐसे व्यक्ति को केवल यह कह दिया जाए कि 'शांत रहो' या 'मजबूत बनो', तो यह सलाह उसके लिए पर्याप्त नहीं होती। कई बार वह और अधिक असहाय महसूस करने लगता है। वास्तव में ऐसे समय में उसे समझने, सुनने और सहारा देने की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि उसे समझा जा रहा है और उसका साथ दिया जा रहा है, तब उसके भीतर स्वयं ही शांति और संतुलन लौटने लगता है।

> **जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्तियां क्या हैं और हमारी सीमाएं कहां हैं। जब हम समस्याओं को समझने की दृष्टि विकसित करते हैं, तब हम केवल उनसे बचने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं।**

विपरीत परिस्थितियों से निकलने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि पहले हम उस स्थिति को पूरी तरह समझने का प्रयास करें। समस्या क्या है, उसका कारण क्या है और उसका प्रभाव किन-किन पहलुओं पर पड़ रहा है। इन सभी बातों पर शांत मन से विचार करना आवश्यक होता है। जब हम थोड़ी देर रुककर स्थिति को देखते हैं, तब कई बार हमें ऐसे पहलू दिखाई देते हैं, जिन्हें जल्दबाजी में हम अनदेखा कर देते हैं। इसके साथ ही अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। जब मन अत्यधिक विचलित होता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले स्वयं को थोड़ा समय देना चाहिए, ताकि मन शांत हो सके। यह शांति हमें स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता देती है। जब मन स्थिर होता है, तब हम तर्क और विवेक के साथ सोच पाते हैं।

इसके बाद समाधान की दिशा में छोटे-छोटे और सोच-समझकर कदम उठाना अधिक उपयोगी होता है। यह आवश्यक नहीं कि हर समस्या का समाधान तुरंत मिल जाए। कई बार समाधान धीरे-धीरे सामने आता है, लेकिन हम अगर धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रास्ते स्वयं बनने लगते हैं। छोटे कदम हमें न केवल समस्या से बाहर निकलने में मदद करते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, अगर हम केवल संघर्ष की भावना से प्रेरित होकर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, तो कई बार वे निर्णय तर्कहीन साबित होते हैं। ऐसे निर्णय क्षणिक राहत तो दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से वे नई समस्याएं पैदा कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम किसी भी कठिन परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ी देर ठहरें और सोचें।

वास्तव में जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें बहुत कुछ सिखाती भी हैं। वे हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देती हैं। हम यह समझ पाते हैं कि हमारी वास्तविक शक्तियां क्या हैं और हमारी सीमाएं कहां हैं। जब हम समस्याओं को समझने की दृष्टि विकसित करते हैं, तब हम केवल उनसे बचने या उनसे लड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण का एक और महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमारे भीतर मानसिक और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखता है। जब हम हर समस्या को युद्ध की तरह नहीं देखते, तब हमारे भीतर अनावश्यक तनाव भी कम होता है। हम अधिक संतुलित और परिपक्व तरीके से जीवन की चुनौतियों का सामना कर पाते हैं।

यह कहा जा सकता है कि विपरीत परिस्थितियों में केवल 'लड़ना' ही समाधान नहीं है। कई बार समझ, धैर्य और संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं। जब हम परिस्थितियों को गहराई से समझते हैं और फिर सोच-समझकर कदम उठाते हैं, तब समाधान अधिक स्थायी और प्रभावी होता है।

इस प्रकार, विपरीत परिस्थितियों में 'समझकर समाधान करना' ही सबसे टिकाऊ और सुरक्षित मार्ग है। यही दृष्टिकोण हमें कठिन समय में भी स्थिर, संतुलित और सशक्त बनाए रखता है। जीवन में आने वाली चुनौतियां तब बोझ नहीं रह जातीं, बल्कि हमारे अनुभव और परिपक्वता का आधार बन जाती हैं।

भोजन और सावधानी

'सेहत से खिलवाड़' (संपादकीय, 9 मई) पढ़ा। आज के समय में फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, लेकिन यह भी सच है कि खेती में कीटनाशक, रसायन तथा फलों को जल्दी पकाने वाले कृत्रिम पदार्थों का उपयोग बढ़ गया है। इससे शरीर में धीरे-धीरे विषैले तत्त्व जमा हो जाते हैं, जो एलर्जी, पाचन समस्या, हार्मोन असंतुलन और दीर्घ काल में गंभीर बीमारियों का कारण बन जाते हैं। इसलिए केवल 'फल सब्जियां खाइए' कहना पर्याप्त नहीं, बल्कि 'सावधानी से चुन कर खाइए' कहना जरूरी हो गया है। समाधान के लिए सबसे पहले मौसमी और स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देना जरूरी है, क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम समय में बाजार में पहुंचते हैं और उनमें रसायन कम हो सकते हैं। इसके अलावा सब्जियों और फलों को नमक वाले पानी या हल्के बेकिंग सोडा या सिरके वाले पानी में भिगो कर और अच्छी तरह धोना ठीक रहता है। जहां तक संभव हो, विश्वसनीय स्रोत से खरीदी गई उपज का प्रयोग करना चाहिए। भोजन में विविधता रखना चाहिए, ताकि एक ही प्रकार के हानिकारक रसायन के लंबे समय तक उपयोग का विपरीत असर शरीर पर नहीं पड़े।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

बंद होते रास्ते

ईरान पश्चिम एशिया की रणनीतिक राजनीति का महत्त्वपूर्ण केंद्र है। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलमार्ग से होकर विश्व के बड़े हिस्से का तेल यहां से जाता है। यदि यहां युद्ध या तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ता है, तो पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होगी। ईरानी पक्ष द्वारा भेजे गए 14 सूत्री शांति प्रस्ताव को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा खारिज करना कूटनीतिक रास्तों के बंद होने का संकेत है। इस घटनाक्रम ने न केवल युद्ध के लंबा खिंचने की आशंका बढ़ा दी है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी अस्थिर कर दिया है। ईरान के प्रस्ताव में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति, मुआवजे और होर्मुज मार्ग पर संप्रभुता जैसी मांगें शामिल थीं। ट्रंप द्वारा इसे पूरी तरह अस्वीकार्य कहना यह दर्शाता है कि अमेरिका ईरान पर अधिकतम सैन्य और आर्थिक दबाव बनाए रखने की रणनीति पर अडिग है। इस तनाव का सबसे तात्कालिक असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा है।

– युगल किशोर राही, छपरा

भरोसे की बात

छह दशक पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने खाद्य संकट के दौर में देश की जनता से सप्ताह में एक दिन भोजन का परित्याग करने की अपील की थी। मगर जनता से आग्रह करने से पहले उन्होंने इस पहल को अपने घर में लागू कर के देखा कि उनका परिवार इस परित्याग को सह पाएगा या नहीं। आज मौजूदा प्रधानमंत्री देश की जनता से सोना न खरीदने, पेट्रोल, खाद्य तेल, उर्वरक और विदेश दौरों पर खर्च को कम करने की अपील कर रहे है। अगर देश संकट के दौर में है, तो पूरी जनता उनके साथ है। मगर यहां देखना होगा कि यह अपील सिर्फ आम आदमी के लिए है या फिर सरकार के बढ़ते खर्चे पर भी इसका कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि आज सरकार छोटा-सा कार्यक्रम आयोजित करने में लाखों रुपए फूंक देती है। वहीं एक छोटी रैली हजारों लीटर पेट्रोल को धुएं में बदल देती है। बहरहाल, जनता सरकार के साथ खड़ी हो सकती है, लेकिन सरकार को भी जनता के साथ होने का विश्वास दिलाना होगा।

– दिनेश, सिंगरौली

जिम्मेदारी किसकी

देशभर में नीट-यूजी की परीक्षा निरस्त होने से न केवल विद्यार्थियों में आक्रोश है, बल्कि इस परीक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह विद्यार्थियों के लिए न केवल मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाने वाली बात है, बल्कि उनके कीमती समय और महीनों की तैयारी पर पानी फेरने जैसा भी है। सरकार कड़ी सुरक्षा के बीच इस परीक्षा का आयोजन करती है, पर स्वयं प्रश्नपत्रों को लीक होने से बचाने में विफल है। यह विद्यार्थियों की उम्मीद टूटने के साथ उनके समय और श्रम का नुकसान भी है। सरकार को प्रश्नपत्रों को कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए और परचे किसी भी सूरत में बाहर निकलने से रोकने के लिए पुख्ता प्रबंध करना चाहिए। इसके लिए विश्वसनीय कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान ही समाधान है। तभी हम युवाओं के सपने बिखरने से बचा सकते हैं।

– अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

दैनिक जागरण

भावनाओं के संतुलन से ही जीवन में स्थिरता संभव है

समय रहते चेतें

इस तथ्य पर हैरानी नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोत कच्चे तेल के साथ-साथ खाद्य तेलों के आयात में भी अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों के सेवन में कमी लाने की भी अपील की। उनका यह कहना सही है कि इससे सेहत सुधारने के साथ विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायता मिलेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत अपनी जरूरत भर का तिलहन क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? यह सामान्य बात नहीं कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 58 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। पिछले वर्ष खाद्य तेल आयात बिल करीब 20 अरब डालर का था। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि कृषि प्रधान देश होने और आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी पर बल देने के बाद भी देश में तिलहन फसलों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, जितना अपेक्षित है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके चलते उनके उत्पादन में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिली है, लेकिन इसी के साथ खाद्य तेल की मांग और खपत भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, उनके खानपान में तेलों की खपत बढ़ रही है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। अपने देश की समस्या यह है कि जब संकट सामने आ खड़ा होता है, तब उससे बचने के उपायों पर ध्यान दिया जाता है। खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का सघन अभियान तो बहुत पहले चलाया जाना चाहिए था और उसकी लगातार समीक्षा भी की जानी चाहिए थी।

बात केवल खाद्य तेलों की ही नहीं है, भारत को बड़ी मात्रा में दालों का भी आयात करना पड़ता है। इसमें भी विदेशी मुद्रा की खपत होती है। कहना कठिन है कि दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गईं, उनके कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए? जो भी हो, यह सही समय है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य आयातित वस्तुओं में कमी लाने के ठोस एवं दीर्घकालिक उपाय करे। यह सही है कि भारत में कच्चे तेल के अपेक्षित भंडार नहीं, इसलिए उसका आयात करना ही होगा, लेकिन आखिर हर तरह के ईवी वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए कोई आकर्षक प्रोत्साहन योजना क्यों नहीं लाई जा पा रही है और उनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार द्रुत गति से क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी तरह क्या कारण है कि किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है कि छोटे-बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम के कारण बड़े पैमाने पर पेट्रोल एवं डीजल की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?

ईंधन खपत में कमी

उत्तराखंड ने भी ईंधन बचत में अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश सरकार ने भी ईंधन अनुशासन को अपनी प्राथमिकता में सम्मिलित किया है। कोरोना संकट काल के बाद पश्चिम एशिया संकट और रूस-यूक्रेन के चलते इस प्रकार की आपात परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इनसे ही निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान में योगदान देते हुए मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के वाहन फ्लीट में वाहनों की संख्या आधी कर दी गई है। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे रहने से भी वाहनों का उपयोग कुछ हद तक सीमित हो सकेगा।

इसी प्रकार विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों से मात्र एक वाहन को ही उपयोग में लाने को कहा गया है। एक बड़ा कदम सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उठाया जाएगा। इसके अंतर्गत ईवी नीति लाई जाएगी। इससे पेट्रोल और डीजल की खपत को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। दरअसल, उत्तराखंड में वाहनों की संख्या में हर वर्ष वृद्धि हो रही है। इस कारण ईंधन खपत बढ़कर 1800 मिलियन लीटर प्रति वर्ष तक पहुंच गई है। प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद हो रही है। सरकारी तंत्र ने ईंधन बचत के लिए कदम उठाकर आमजन को भी राह दिखाई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ईंधन बचत के इस अभियान में आमजन की भागीदारी भी बढ़ेगी। विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वाहनों का उपयोग जितना बढ़ेगा, सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव उतना ही कम होगा।

> ईंधन अनुशासन इस समय में राष्ट्र की सर्वोच्च आवश्यकता बन गया है। ऐसे समय में प्रदेश को भी समुचित योगदान देना चाहिए

कमजोर पड़ती क्षेत्रीयता की राजनीति

विकास सारस्वत

हालिया विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति का कमजोर पड़ना दर्शाता है कि राष्ट्रवादी विचारों का विस्तार हो रहा है

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद असम और बंगाल में प्रचंड बहुमत वाली सरकारों ने कमान संभाल ली है तो पुडुचेरी में चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। त्रिशंकु विधानसभा वाले तमिलनाडु में भी विजय सरकार का आगाज हो चुका है। गत दिवस केरलम के मुख्यमंत्री का चयन भी हो गया। चुनाव परिणाम की बात करें तो असम, केरलम और पुडुचेरी में नतीजे आशा के अनुरूप ही रहे। असम में भाजपा के सामने कांग्रेस इस कदर साफ हुई, जैसे ब्रह्मपुत्र के सैलाब में नदी के बीच बालू से बने द्वीप बह जाते हैं। राज्य में कांग्रेस केवल निचले असम की मुस्लिम बहुल सीटों तक ही सिमट कर रह गई है। जबकि उत्तर असम के असमिया बहुल जिलों में उसका सूपड़ा पूरी तरह साफ हो गया, जहां कभी पार्टी का अच्छा प्रभाव होता था। यह परिणाम पूरी तरह अपेक्षित भी था। राज्य में न केवल भाजपा सरकार द्वारा किया गया विकास साफ-साफ दिखाई देता है, बल्कि पार्टी असमिया अस्मिता और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति संवेदनशील भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की निजी लोकप्रियता भी पार्टी के लिए कारगर साबित रही। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की स्थिति पर चुनाव से पहले ही एक असमिया बुद्धिजीवी ने टिप्पणी की थी कि "भंग नौकात निदिबा भोरी" यानी टूटी नौका में आखिर कौन बैठता है?

केरलम के नतीजों में भी आश्चर्य सिर्फ इतना है कि यह परिवर्तन दस वर्ष बाद हुआ है, अन्यथा यहां हर पांच साल बाद मार्क्सवादी नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के बीच ही बारी-बारी से सत्ता बदलती रही है। यहां के नतीजों में महत्वपूर्ण बात यह रही कि यूडीएफ ने कोझीकोड, तिरुअनंतपुरम और कोल्लम जैसे वामपंथ के गढ़ भी ढहा दिए। मुस्लिम लीग के साथ हुए गठजोड़ ने कांग्रेस को विशेषकर उत्तरी केरलम में मदद पहुंचाई। इस गठबंधन से कांग्रेस को करीब छह प्रतिशत मतों का लाभ मिला। हालांकि यह परिणाम भी अनपेक्षित नहीं थे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूडीएफ को राज्य में 20 में से 18 सीटें मिली थीं। इसी तरह पुडुचेरी ने भी उसी परिपाटी का पालन किया है, जिसमें केंद्र पर निर्भरता होने के कारण केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव का झुकाव स्वाभाविक रूप से उस दल या गठबंधन की तरफ होता है, जिसकी केंद्र में सत्ता होती है।

जो दो नतीजे सर्वाधिक चौंकाने वाले रहे, वे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आए। तमिलनाडु के नतीजे इस मायने में ऐतिहासिक हैं कि 50 वर्ष बाद द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूम रही सत्ता पर विराम लगा। सत्ताधारी द्रमुक को इन चुनावों में गहरा झटका लगा। बड़ा सवाल यही है कि इसे कितना व्यापक परिवर्तन माना जाए, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से तमिलनाडु की राजनीति में फिर से विजय के रूप में एक सिने स्टार का उदय हुआ। वहीं सर्वाधिक चर्चा में रहे राज्य बंगाल में सत्ता परिवर्तन के मायने शायद सबसे अधिक महत्व रखते हैं। बंगाल में लंबे समय बाद पूरी तरह हिंसा मुक्त चुनाव हुए। चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कड़े कदमों ने भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया। इसके चलते हुए रिकार्ड मतदान ने भय और भ्रष्टाचार के सहारे बनाई गई सत्ता को उखाड़ फेंका। स्पष्ट है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया। बंगाल के नतीजों में एक बड़ी बात यह भी रही कि आम बंगाली मतदाताओं ने कुछ बांग्ला बुद्धिजीवियों द्वारा संस्कृति और क्षेत्रीयता के नाम पर निर्मित श्रेष्ठता और विशिष्टता के भाव से ऊपर उठकर भारतीयता को महत्व दिया।

अवधेश राजपूत

निजी अनुभव से कहूं तो कभी सीबीआइ तो कभी ईडी और केंद्रीय बलों के ममता विरोध से खिन्न, परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध बंगाली मतदाताओं में एक प्रबल भाव था कि आखिर वे भी मूलतः हैं तो भारतीय ही। स्कूलों के उन्नयन के लिए लाई गई पीएमश्री और आयुष्मान जैसी योजनाओं का विरोध समझ से परे था। खस्ताहाल उद्योग और व्यापार, रोजगार की कमी और महिला सुरक्षा के अभाव ने बंगाली अस्मिता कार्ड नहीं चलने दिया। राजकीय सीमाओं से परे राज्यों के नतीजों के कुछ व्यापक निहितार्थ भी हैं। जैसे कि एक पहलू पार्टी पोषित भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा रहा। तमिलनाडु और बंगाल दोनों ही राज्यों में एक ऐसी राजकीय व्यवस्था देखने को मिली, जहां पार्टी काडर को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ने के संस्थागत प्रयास हुए। बंगाल में नौकरियों के एवज में भ्रष्टाचार के अलावा निजी निर्माण से लेकर बिजली लाइन खिंचवाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को कट मनी देनी पड़ती थी। सरकारी योजनाओं में भी यह व्यवस्था इतनी संस्थागत हो चली थी कि गरीब लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शुरू की गई समब्याथि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 2,000 में से 200 स्थानीय कार्यकर्ताओं को देने की खबरें बहुत आम थीं। तमिलनाडु की बात करें तो मंत्रियों में एन. नेहरू, आइ. पेरियसामी और वीएस बालाजी पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए।

दूसरा महत्वपूर्ण निहितार्थ यह कि हिंदू विरोध की राजनीति सिमटती जा रही है। जहां द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन और के. पोन्मुड़ी ने सनातन को मिटाने की बात कही, वहीं ममता बनर्जी ने काफिर जैसे इस्लामपरस्त शब्दों द्वारा मुस्लिम वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। ममता की जय श्रीराम के आह्वान से खीझ कैमरों के सामने भी स्पष्ट दिखी। जनता ने मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध की राजनीति को सिरे से नकारा है। तीसरा निहितार्थ सीमावर्ती राज्यों असम और बंगाल में घुसपैठ से जुड़ा है। चौथा, देश में सर्वाधिक क्षेत्रीयता का भाव लिए हुए तमिलनाडु और बंगाल में मतदाताओं ने भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को नकारा है। कुल मिलाकर ये नतीजे दर्शाते हैं कि देश की राजनीति में क्षेत्रीयता की राजनीति कमजोर पड़ रही है और राष्ट्रवादी विचार का विस्तार हो रहा है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

विकास के नए युग में पूर्वोत्तर

लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

पूर्वोत्तर की सामरिक स्थिति, संसाधन और ऊर्जावान जनसंख्या विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर रहा है। विविध जनजातीय परंपराएं, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, अद्वितीय लोक-संस्कृति और अपार संभावनाओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहा। किंतु बीते एक दशक के दौरान पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। असम सहित समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संपर्क, शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। दशकों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र संपर्क, आधारभूत संरचना की कमी तथा देश के अन्य हिस्सों से अलगाव जैसी चुनौतियों से जूझता रहा, किंतु क्षेत्र के सामरिक महत्व और अपार संभावनाओं को पहचानते हुए मोदी सरकार ने इसके विकास के लिए सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इस परिवर्तन के केंद्र में 'एक्ट ईस्ट नीति' रही है, जिसने पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पुनर्परिभाषित किया है।

'एक्ट ईस्ट नीति' ने पड़ोसी देशों के साथ भौतिक और आर्थिक संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती प्रदान की है। राजमार्गों, रेलमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्गों और हवाई संपर्क जैसी प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में तीव्र गति से प्रगति हुई है। पुलों के निर्माण और सीमा व्यापार अवसंरचना के विकास से लाजिस्टिक्स में सुधार हुआ है तथा क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर रेल संपर्क और उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विस्तार जैसी पहलों ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक निकट ला दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के लिए संसाधनों के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। विभिन्न मंत्रालयों को अपने सकल बजटीय समर्थन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमुख योजनाएं दूरदराज के इलाकों तक पहुंची हैं। क्षेत्र में डिजिटल संपर्क को भी व्यापक बढ़ावा मिला है। इससे समावेशन को बढ़ावा मिला है तथा असमानता में कमी आई है। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार शांति और स्थिरता पर दिया गया विशेष बल रहा है।

बेहतर होते बुनियादी ढांचे से प्रगति को लगे पंख। फाइल

सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित कर लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान और उग्रवादी समूहों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक शांति समझौतों और निरंतर संवाद ने अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार किया है, जिससे निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश के माध्यम से आधुनिक तकनीकों, बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप और उद्यमिता को नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग प्रदान कर क्षेत्र के युवाओं की नवाचार क्षमता को नई दिशा दी जा रही है। सरकार ने आधारभूत संरचना सुधार, पर्यटन स्थलों के प्रचार और यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इस क्षेत्र को देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक और सुलभ बनाया है।

यद्यपि आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास महत्वपूर्ण हैं, किंतु पूर्वोत्तर की वास्तविक शक्ति उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में निहित है। गुवाहाटी में बिहू, झुमुर और बागुरुंबा नृत्य के भव्य आयोजनों द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड स्थापित करना केवल क्षेत्र की जीवंत परंपराओं का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इसने पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों के बीच भावनात्मक एकता को और अधिक मजबूत बनाया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जोरहाट में महान आहोम सेनापति वीर लासित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और देशभक्ति की भावना को समर्पित एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। बटद्रवा थान सांस्कृतिक परिसर के विकास तथा महत्वाकांक्षी कामाख्या कारिडोर परियोजना जैसी पहलें असम और पूर्वोत्तर में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति दे रही हैं। साथ ही चराइदेव के मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होना असम की ऐतिहासिक विरासत की वैश्विक पहचान है। 'लखपति दीदी', जिसे क्षेत्र में 'लखपति बाइदेउ' के नाम से जाना जाता है, समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर वास्तव में 'अष्ट लक्ष्मी' के रूप में उभरा है। अलगाव से एकीकरण और उपेक्षा से सशक्तीकरण तक की यह यात्रा प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है। यह सिद्ध करती है कि दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास किस प्रकार एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं

(लेखक असम के राज्यपाल हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

निंदा से करें परहेज

जिस प्रकार व्यसन इंसान के सोच और जीवन दोनों को प्रभावित करता है, उसी प्रकार निंदा भी मनुष्य के चरित्र को कमजोर बना देती है। धीरे-धीरे यह उसके व्यक्तित्व को भीतर से खोखला करने लगती है। निंदा करने वाला व्यक्ति खुद को चतुर समझता है, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति हमेशा उसे संदेह की नजर से देखता है, क्योंकि जो व्यक्ति आज किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वह कल उसकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। बाहर से भले ही लोग उसकी बातों पर मुस्कुरा दें, लेकिन भीतर ही भीतर उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है।

मानव जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। जो शब्द हम भेजते हैं, वही शब्द लौटकर आता है। यदि हम दूसरों के लिए कटुता, ईर्ष्या और नकारात्मकता भेजेंगे, तो वही माहौल हमारे आसपास भी बनेगा। इसके विपरीत यदि हम प्रेम, सम्मान और प्रेरणा की बातें करेंगे, तो समाज में सकारात्मकता बढ़ेगी। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारे संस्कार और सोच का परिचय भी देते हैं। आज के समय में बहुत से लोग दूसरों की गलतियां खोजने में लगे रहते हैं।

हम दूसरों की बुराई करके खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश में अपना ही स्तर खुद गिरा लेते हैं। वास्तविक महानता दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है, जो दूसरों की कमियों पर चर्चा करने के बजाय उनके गुणों को देखने का प्रयास करे। निंदा से रिश्ते टूटते हैं, विश्वास समाप्त होता है और मन में कड़वाहट पैदा होती है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। मधुर वाणी, अच्छे विचार और सम्मानपूर्ण व्यवहार ही मनुष्य को सच्चा सम्मान दिलाते हैं।

समराज चौहान

तेजाब पीड़ितों को मिलता न्याय

रंजना मिश्रा

> एक लोकतंत्र की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने नागरिकों के दर्द को कितनी गहराई से समझता है

एसिड अटैक या तेजाब हमले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन पीड़ितों को जबरन तेजाब पिलाया गया है और जिनके शरीर के आंतरिक अंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वे भी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत पूर्ण संरक्षण, सरकारी सहायता और मुआवजे के उतने ही अधिकारी हैं, जितने कि चेहरे या बाहरी शरीर पर तेजाब के हमले का दंश झेलने वाले पीड़ित। इस असहनीय और आजीवन चलने वाली पीड़ा के बावजूद ऐसे पीड़ितों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखने और उन्हें सरकारी सहायता देने में व्यवस्थागत बाधाएं आती थीं। चूंकि उनके घाव बाहर से दिखाई नहीं देते थे, इसलिए मेडिकल बोर्ड और प्रशासनिक तंत्र उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी करते थे। उन पर दोहरी मार थी। एक तरफ अपराधी द्वारा दिया गया दर्द और दूसरी तरफ उस तंत्र की संवेदनहीनता जिसे उनकी रक्षा करनी चाहिए थी।

यह फैसला दिव्यांगता की परिभाषा को अधिक व्यापक और यथार्थवादी बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है। अब ऐसे पीड़ितों को भी दिव्यांगता कानून के तहत मुफ्त और प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा, नौकरियों में आरक्षण, मासिक पेंशन और पुनर्वास की वे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी, जो एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। यह आदेश राज्य सरकारों और प्रशासन के लिए भी एक स्पष्ट निर्देश है कि वे अपनी नीतियां बनाते समय या उन्हें लागू करते समय तकनीकी पचड़ों में उलझने के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं। हालांकि असली चुनौती इस फैसले के जमीनी क्रियान्वयन में है। भारत में अदालतों के प्रगतिशील आदेश अक्सर नौकरशाही की लालफीताशाही में उलझ कर रह जाते हैं। अब यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि मेडिकल बोर्ड और प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी इस नए दृष्टिकोण के प्रति पूरी तरह संवेदनशील हों।

तेजाब से जली हुई आंतों और भोजन नली की मेडिकल रिपोर्ट को उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जितनी गंभीरता से किसी झुलसे हुए चेहरे को लिया जाता है। इन पीड़ितों को अपना हक, प्रमाण पत्र और मुआवजा पाने के लिए सरकारी दफ्तरों के धक्के न खाने पड़ें, इसके लिए एक सुगम और पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाना नितांत आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला उन अदृश्य घावों पर एक कानूनी मरहम की तरह है, जिन्हें समाज और व्यवस्था ने लंबे समय तक अनदेखा किया। वास्तव में एक सभ्य समाज और एक मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे पीड़ित और हाशिए पर खड़े नागरिकों के दर्द को कितनी गहराई से समझता है और उनके आंसू पोंछने के लिए कितने ईमानदार प्रयास करता है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जिम्मेदार शासन आवश्यक

'पहले सरकारी तंत्र बरते किफायत' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव शुक्ला ने सरकारी फिजूलखर्ची और मुफ्त योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वास्तव में समस्या केवल योजनाओं की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें शासन विकास से अधिक दिखावे पर केंद्रित होता जा रहा है। सरकारी विज्ञापन, भव्य आयोजन, अनावश्यक यात्राएं और स्वागत संस्कृति पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। चुनावी राजनीति ने मुफ्त सुविधाओं को एक आसान हथियार बना दिया है। जनता को तात्कालिक राहत तो मिलती है, पर दीर्घकाल में यही योजनाएं सरकारी कर्ज, कर वृद्धि और आर्थिक असंतुलन का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि योजनाओं की सफलता का आकलन वास्तविक सुधार से नहीं, बल्कि प्रचार और भीड़ से किया जाने लगा है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर पड़ती है। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सरकारी सहायता और निर्भरता के बीच की रेखा धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर देने के बजाय केवल राहत आधारित राजनीति की जाएगी, तो आत्मनिर्भर समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। लोकतंत्र में कल्याणकारी योजनाएं आवश्यक हैं, लेकिन उनका उद्देश्य नागरिकों को सक्षम बनाना होना चाहिए, स्थायी आश्रित नहीं। समाधान स्पष्ट है-सरकारी खर्च का सामाजिक आडिट अनिवार्य हो, गैरजरूरी सुविधाओं और प्रचार व्यय पर सीमा तय हो तथा बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा, कृषि, स्थानीय उद्योग और रोजगार सृजन पर लगाया जाए। आर्थिक अनुशासन की शुरुआत सत्ता से होगी, तभी जनता में विश्वास पैदा होगा।

awanishg30@gmail.com

मेलबाक्स

मेहनत छात्रों की, गलती व्यवस्था की

नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए वर्षों तक मेहनत करने वाले छात्रों को पेपर लीक की खबर से मानसिक आघात पहुंचा है। प्रश्नों का लीक होना बेहद गंभीर मामला है। एनटीए की ओर से बार-बार यह दावा किया जा रहा था कि प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन वास्तविकता में सुरक्षा व्यवस्था की खामियां सामने आ गई हैं। अब परीक्षा दोबारा होने की संभावना के कारण प्रवेश प्रक्रिया में देरी होगी, शैक्षणिक सत्र देर से शुरू होगा और इसका सीधा असर छात्रों पर पड़ेगा। परीक्षा से पहले प्रशासन ने सख्त और पारदर्शी व्यवस्था होने का दावा किया था। इसके बावजूद पेपर लीक होने से एनटीए की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि हर वर्ष पेपर लीक की घटनाएं होती रहें, तो यह व्यवस्था में गंभीर खामियों को दर्शाता है। मेडिकल शिक्षा का सपना पूरा करने के लिए कई छात्र दो-दो वर्षों तक तैयारी करते हैं। निजी कोचिंग और रेजिडेंशियल क्लासेस पर अभिभावक लाखों रुपये खर्च करते हैं। ऐसे में पेपर लीक और परिणामों में गड़बड़ी जैसी घटनाएं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती हैं।

दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

टूटता भरोसा

जब एक छात्र वर्षों तक दिन-रात मेहनत करता है और परीक्षा से पहले ही प्रश्न बाजार में बिकने लगते हैं, तब सिर्फ एक परीक्षा नहीं, भरोसा टूटता है, परिवारों की उम्मीदें टूटती हैं और देश की प्रतिभा हताश होती है। समस्या केवल तकनीकी नहीं, बल्कि नैतिक और प्रशासनिक दोनों है। जब तक पेपर लीक कराने वालों को राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक लालच और कमजोर कानूनों का सहारा मिलता रहेगा, तब तक हर नई परीक्षा युवाओं के लिए डर का कारण बनी रहेगी। अब समय केवल जांच और निंदा का नहीं, बल्कि कठोर और दिखाई देने वाली कार्रवाई का है। पेपर लीक को साधारण अपराध नहीं, युवाओं के भविष्य के खिलाफ अपराध माना जाना चाहिए। दोषियों की संपत्ति जब्त हो, उम्रभर सरकारी भर्ती से प्रतिबंध लगे और त्वरित विशेष अदालतों में सुनवाई हो।

आयुष्मान पाण्डेय, सीतापुर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

चार हजार नौकरियों की छंटनी करेगी सिस्को

नई दिल्ली: वैश्विक टेक्नोलाजी कंपनी सिस्को ने दुनियाभर में चार हजार 4,000 नौकरियों की कटौती की घोषणा की है। यह कदम एक पुनर्गठन प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और तेजी से बढ़ने वाले दूसरे टेक्नोलाजी क्षेत्रों पर अध्यान और मजबूत करना है। कंपनी के सीईओ चक राबिन्स ने एक मेमो में बताया कि इस छंटनी से पांच प्रतिशत से भी कम कर्मचारी प्रभावित होंगे। (आइएएनएस)

अपने आटोमोबाइल कारोबार को फिर से खड़ा करने की योजना के तहत 2028 से हम भारतीय बाजार के लिए खासतौर पर तैयार किए गए माडल पेश करना शुरू करेंगे।

– तोशिहिरो मिबे, वैश्विक सीईओ, होंडा मोटर कंपनी

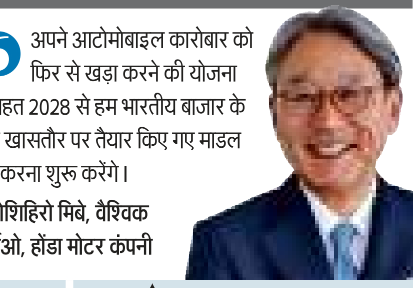

सेंसेक्स	निफ्टी	सोना (प्रति दस ग्राम)	चांदी (प्रति किलो ग्राम)	डालर	क्रूड (प्रति बैरल)
75,398.72 ▲ 789.74	23,689.60 ▲ 277	₹ 1,66,000 ▲ ₹ 650	₹ 2,96,600 ▼ ₹ 900	₹ 95.64 ▼ ₹ 0.02	$ 106.48

एक नजर में

जियो प्लेटफार्म्स के एमडी बनाए गए आकाश अंबानी

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की डिजिटल सेवा कंपनी जियो प्लेटफार्म्स ने आकाश अंबानी को अपना प्रबंध निदेशक (एमडी) बनाया है। कंपनी ने यह नियुक्ति अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) से पहले की है। कंपनी आइपीओ के मसौदा दस्तावेज मई के अंत या जून में जमा कर सकती है। आकाश अंबानी की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए की गई है जो नौ अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। आकाश 2022 में रिलायंस जियो इन्फोकाम के चेयरमैन बने थे। (प्रेट्र)

ज्यादा आय के बावजूद टाटा मोटर्स का लाभ घटा

मुंबई: बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2026) में ज्यादा आय के बावजूद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) का शुद्ध लाभ 31.29 प्रतिशत घटा है। कंपनी ने बताया कि बीती तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 5,878 करोड़ रुपये रहा है, जो जनवरी-मार्च 2025 के दौरान 8,556 करोड़ रुपये था। बीती तिमाही में कंपनी का संचालन राजस्व सात प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वर्ष समान तिमाही में 98,377 करोड़ रुपये रहा था। (प्रेट्र)

स्वाच-एपी ने पेश किया घड़ियों का नया कलेक्शन

नई दिल्ली: स्विट्जरलैंड की घड़ी निर्माता स्वाच ने आडेमर्स पिगुएट (एपी) के साथ मिलकर घड़ियों का नया कलेक्शन पेश किया है। रायल पाप नाम के इस कलेक्शन में पाकेट वाच के कुल आठ माडल शामिल हैं। कंपनी ने बताया कि इन नए माडल की 16 मई 2026 से स्वैच के चुनिंदा स्टोर्स से बिक्री शुरू हो जाएगी। इस घड़ी के साथ तीन अलग-अलग लंबाई के लेनयार्ड दिए जाएंगे, जिससे इसके गले, कलाई पर जेब में, हैंडबैग के साथ क अन्य तरीके से पहन सकते हैं। साथ ही एक छोटा सा हटाया जा सकने वाला स्टैंड भी है, जिसकी मदद से इसको डेस्क वाच में बदला जा सकता है। (वि.)

चीनी के निर्यात पर सितंबर तक लगाया प्रतिबंध

घरेलू कीमतों में वृद्धि की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से लगाई रोक

- चीनी के चालू सीजन में चीनी का उत्पादन 280 लाख टन से कम रहने का अनुमान
- जिन सौदों का शिपमेंट नहीं हुआ, उन पर भी लागू होगा यह ताजा प्रतिबंध
- जुलाई से सितंबर के दौरान चीनी की कीमतों में होती है सबसे अधिक वृद्धि

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार महंगाई में वृद्धि को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए चीनी के निर्यात पर अगले 30 सितंबर तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। वाणिज्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 13 मई से यह प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। यह प्रतिबंध उन पूर्व सौदों पर भी लागू होगा, जिनका शिपमेंट नहीं हुआ है।

चीनी के चालू सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी का उत्पादन 280 लाख टन से कम रहने का अनुमान है। जबकि घरेलू स्तर पर चीनी की खपत 280 लाख टन से अधिक की है। चीनी की कीमत में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इस बढ़ोतरी पर रोक लगाने के लिए ही चीनी के निर्यात पर सितंबर तक के लिए रोक लगाई गई है। अप्रैल की खुदरा महंगाई दर में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले तीन प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी रही। वहीं गुरुवार को जारी थोक महंगाई दर आठ प्रतिशत से ऊपर चली गई है। चीनी का सीजन एक अक्टूबर से शुरू होता है। चीनी के स्टाक की कमी रहने पर जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान चीनी की कीमत अधिक बढ़ती है। अक्टूबर से चीनी मिल उत्पादन शुरू कर देती हैं, जिससे बाजार में नई चीनी की आवक शुरू हो जाती है। इस साल मानसून पर अल नीनो का प्रभाव बताया जा रहा है।

बारिश की कमी से गन्ने के उत्पादन में कमी होने पर चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा कि निर्यात प्रतिबंध से घरेलू कीमतों में किसी भी तेज बढ़ोतरी को रोकने में मदद मिलेगी।

2022-23 में भी निर्यात पर लगाया था प्रतिबंध

चीनी मिलर्स का कहना है कि इस साल अक्टूबर में चीनी सीजन के आरंभ होने के समय 40-45 लाख टन चीनी का स्टाक रहेगा जबकि यह स्टाक 70-80 लाख टन तक का होता है। वर्ष 2022-23 में भी सरकार ने चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत की तरफ से चीनी के निर्यात पर रोक लगाने से वैश्विक स्तर पर भी चीनी के दाम बढ़ेंगे। ब्राजील के साथ भारत चीनी का बड़ा निर्यातक देश हैं।

पहले हो चुके निर्यात सौदों को पूरा करने की मिले मंजूरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: चीनी मिलों के संगठन ने सरकार से अपील की कि वह पहले से हो चुके निर्यात सौदों को पूरा करने की इजाजत दे। इंडियन शुगर एंड बायो-एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि इस अचानक रोक से उन मिलों के मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, जिन्होंने विदेशी खरीदारों के साथ किसी भी कीमत पर सौदा पूरने का वादा कर रखा है। संगठन के महानिदेशक दीपक बल्लानी ने कहा, "पहले से हो चुके सौदों को पूरा करने की इजाजत देने से ट्रेड सेटलमेंट को सही तरीके से करने में मदद मिल सकती है।

चीनी कंपनियों के शेयर गिरे

कंपनी	गिरावट (% में)
धामपुर शुगर मिल्स	6.66
द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज	5.88
डालमिया भारत शुगर	5.86
बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल्स	5.22
उत्तम शुगर मिल्स	5.08
मवाना शुगर्स	4.18
राजश्री शुगर्स	4.02
श्री रेणुका शुगर्स	2.41

लगातार दूसरे दिन बढ़े शेयर, सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा

- दूरसंचार, फार्मा और निजी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिली मजबूती
- रिकार्ड निचले स्तर तक गिरने के बाद दो पैसे बढ़कर 95.64 पर बंद हुआ रुपया

मुंबई, प्रेट्र: घरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच गुरुवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही। दूरसंचार, फार्मा और निजी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूती मिली। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 789.74 अंक की बढ़त के साथ 75,398.72 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स ने सत्र की मजबूत शुरुआत की, लेकिन जल्द ही यह नकारात्मक क्षेत्र में चला गया। हालांकि, दूरसंचार और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी लौटने से यह एक समय 1,000 अंक से अधिक चढ़कर 75,681.88 अंक के स्तर तक पहुंच गया था। वहीं, एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी भी 277 अंक चढ़कर 23,689.60 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में भारती एयरटेल में सर्वाधिक पांच प्रतिशत की तेजी आई। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, आइटीसी और एसबीआइ बढ़कर बंद हुए। वहीं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और मारुति सुजुकी के शेयरों में गिरावट रही। वहीं, रुपया इंट्रा-डे में निचले स्तर तक गिरने के बाद डालर के मुकाबले दो पैसे बढ़कर 95.64 पर बंद हुआ

दो दिनों में 6.82 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति: पिछले दो कारोबारी सत्रों में निवेशकों की संपत्ति में 6.82 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ। अब बीएसई का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 4.83 ट्रिलियन डालर हो गया है।

आरबीआइ ने दिल्ली की 67 एनबीएफसी के पंजीकरण रद किए

नई दिल्ली, एएनआइ: आरबीआइ ने 150 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का सर्टिफिकेट आफ रजिस्ट्रेशन (सीओआर) रद कर दिया। इसमें से लगभग 67 एनबीएफसी दिल्ली में पंजीकृत थीं,, जबकि लगभग 75 कंपनियां बंगाल- खासकर कोलकाता और आस-पास के इलाकों में पंजीकृत थीं। ये कंपनियां अब एनबीएफसी के तौर पर काम नहीं कर सकती हैं।

जिन कंपनियों का पंजीकरण रद किया गया है, उसमें कई छोटी और मध्यम आकार की वित्त और निवेश से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में पंजीकृत एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन भी रद किया गया है। एनबीएफसी ऐसे वित्तीय संस्थान होते हैं, जो बैंकों की तरह लोन, निवेश व दूसरी वित्तीय सेवाएं देते हैं। हालांकि, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है।

एक साल में एअर इंडिया को 26,700 करोड़ का नुकसान

विभिन्न हवाई मार्गों पर प्रतिबंध और दूसरी मुश्किलों से जूझ रही कंपनी, इस दौरान समूह का राजस्व 79,150 करोड़ रुपये रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: विभिन्न हवाई मार्गों पर प्रतिबंध और दूसरी मुश्किलों से जूझ रही एअर इंडिया को पिछले वित्त वर्ष में 26,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ। जबकि कंपनी का राजस्व 79,150 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा। ये आंकड़े एअर इंडिया समूह के हैं, जिसमें एअर इंडिया और एअर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है। सिंगापुर एयरलाइंस समूह ने गुरुवार को जारी अपनी 2025-26 की सालाना वित्तीय रिपोर्ट में यह जानकारी दी है। सिंगापुर एयरलाइंस समूह का शुद्ध लाभ मार्च 2026 में खत्म हुए वित्त वर्ष में 57 प्रतिशत घटकर लगभग 8,900 करोड़ रुपये रह गया। इसकी मुख्य वजह विस्तारा के विलय से जुड़े पिछले साल के एक बार के लाभ का नहीं होना और एअर इंडिया का घाटा था।

सिंगापुर एयरलाइंस के मुताबिक, एअर इंडिया को सप्लाई चेन की दिक्कतों, विभिन्न हवाई मार्गों पर पाबंदियों और जेट फ्यूल की बढ़ी हुई कीमतों जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक दिन पहले यानी बुधवार को ही एअर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण हवाई क्षेत्र की पाबंदियों और जेट ईंधन (एटीएफ) कीमतों के आसमान पर पहुंचने को आधार बनाते हुए जून से अगस्त 2026 तक हर हफ्ते अपनी 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती का एलान किया है। साथ ही दिल्ली-शिकागो सहित सात मार्गों पर उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित करने की बात कही है।

अग्रिम मंजूरी योजना में 100 किलो तक सोने का आयात

नई दिल्ली, प्रेट्र: कीमती धातुओं के आयात शुल्क में भारी बढ़ोतरी करने के एक दिन बाद गुरुवार को सरकार ने अग्रिम मंजूरी योजना के तहत सोना आयात की सीमा 100 किलोग्राम तक तय कर दी। इस योजना के तहत ज्वेलरी निर्यातकों को कच्चा माल या इनपुट सामग्री बिना किसी शुल्क आयात करने की अनुमति मिलती है।

इसके अलावा सरकार ने सोना आयात के लिए अग्रिम मंजूरी जारी करने व उसकी निगरानी की शर्तों को और सख्त कर दिया है। इससे पहले योजना के तहत सोना आयात पर कोई सीमा नहीं थी। योजना के तहत उन इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति होती है, जिनका इस्तेमाल निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में किया जाता है। सरकार ने बुधवार को ही सोना और चांदी के आयात पर शुल्क को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया है।

42 महीने के उच्चस्तर पर थोक महंगाई

- ईंधन, बिजली और क्रूड पेट्रोलियम की कीमतों में वृद्धि से अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति 8.3 प्रतिशत पर पहुंची
- पिछले महीने क्रूड पेट्रोलियम की महंगाई 88.06 प्रतिशत रही, यह अक्टूबर 2021 के बाद सबसे अधिक

नई दिल्ली, प्रेट्र: अप्रैल में थोक महंगाई सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई। पश्चिम एशिया संकट से ईंधन, बिजली और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में तेज वृद्धि के चलते थोक महंगाई में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित महंगाई दर मार्च में 3.88 प्रतिशत थी। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज के अनुसार, थोक मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि इस सीरीज में अब तक की सबसे अधिक रही है।

ईंधन और बिजली में थोक मूमहंगाई अप्रैल में 42 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 24.71 प्रतिशत पर पहुंच गई, जो मार्च में 1.05 प्रतिशत थी। क्रूड पेट्रोलियम की महंगाई अप्रैल में 88.06 प्रतिशत रही और यह अक्टूबर 2021 के बाद सबसे ज्यादा है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी ने भारत में क्रूड पेट्रोलियम के आयात में रुकावट डाली है। साथ ही, दुनियाभर में क्रूड की कीमतों में तेज बढ़ोतरी ने ईंधन आयात को महंगा कर दिया है।

ईंधन और बिजली श्रेणी में, एलपीजी में महंगाई दर अप्रैल में 10.92 प्रतिशत रही। पेट्रोल में महंगाई दर 32.40 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 2.50 प्रतिशत थी। डीजल में महंगाई दर अप्रैल में 25.19 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 3.26 प्रतिशत थी।

पांच रुपये महंगे हो सकते हैं पेट्रोल-डीजल

बार्कलेज के अनुसार, मई में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में जल्द पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं। साथ ही ऐसा लगता है कि मौद्रिक नीति समिति आपूर्ति झटके से बढ़ी महंगाई को नजरअंदाज करेगी और 2026 के बाकी समय में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

अंतरराष्ट्रीय

न्यूज गैलरी

ब्रिटिश पीएम की बढ़ीं मुश्किलें, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा

लंदन: ब्रिटेन में स्थानीय चुनावों में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी की हार के बाद प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर मुश्किल में घिर गए हैं। उनके इस्तीफे की बढ़ती मांग गुरुवार को उस समय खुली बगावत में तब्दील हो गई, जब स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने पद से इस्तीफा दे दिया। वह लेबर पार्टी के अगले नेता के रूप में प्रबल दावेदार हो सकते हैं। स्टार्मर की लेबर पार्टी के कई सांसदों और मंत्रियों ने इस्तीफे की मांग की है। हालांकि वह इस्तीफे की मांग को ठुकरा चुके हैं। स्ट्रीटिंग कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले वरिष्ठ मंत्री बन गए हैं। (एपी)

बलूचिस्तान में फिर तीन युवकों को गायब किए जाने का आरोप

बलूचिस्तान : बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के मामलों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां सवालों के घेरे में हैं। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और कराची में तीन युवकों को देर रात छापेमारी के दौरान उठाए जाने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके परिवारों में भारी चिंता और गुस्सा है। रिपोर्ट के अनुसार, केच जिले से 18 वर्षीय उमर बलोच को नौ मई की रात उसके घर से उठाया गया। एक अन्य मामले में केच जिले के होशाब निवासी 27 वर्षीय डेंटल सर्जन डा जहीर को क्वेटा से हिरासत में लेने का आरोप है। कराची के लियारी इलाके में रहने वाले 25 वर्षीय ताहिर को भी सीटीडी अधिकारियों द्वारा घर से उठाए जाने का आरोप लगाया गया है। (एएनआइ)

मालदीव में स्कूबा डाइविंग के दौरान पांच इतालवियों की मौत

रोम: इटली के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि मालदीव में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में पांच इतालवी नागरिकों की मौत हो गई। यह घटना वावु एटोल में हुई, जहां समूह पानी के नीचे 50 मीटर की गहराई में स्थित गुफाओं का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जांच चल रही है। श्रीलंका में इतालवी दूतावास पीड़ितों के परिवारों से संपर्क करने और कांसुलर सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है। (रायटर)

होर्मुज से 30 जहाज गुजरे, तेल की कीमतों में आई गिरावट : ईरान

- ब्रेंट क्रूड आयल फ्यूचर्स के दाम दो डालर की कमी
- ट्रंप व चिनफिंग दोनों ने इस बात पर सहमति जताई कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखा जाना चाहिए

होर्मुज स्ट्रेट से पारगमन करते जहाज और नावें। फाइल

लंदन, रायटर : ईरान ने कहा है कि पिछले कुछ घंटों में 30 जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरे हैं और इसके बाद गुरुवार को तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान ने कुछ चीनी जहाजों के लिए आवागमन की अनुमति देना शुरू कर दिया है। इस बीच, व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि होर्मुज स्ट्रेट को ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए खोला जाना चाहिए।

ब्रेंट क्रूड आयल फ्यूचर के दामों में गिरावट देखी गई। ब्रेंट क्रूड आयल फ्यूचर्स के प्रति बैरल दाम 107.13 अमेरिकी डालर के पहले के उच्च स्तर से गिरकर 105.03 डालर प्रति बैरल पर आ गए।

अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज अधिकांशतः बंद रहा है। अब होर्मुज से केवल वही जहाज गुजर पा रहे हैं जिन्हें ईरानी अधिकारी हरी झंडी दे रहे हैं।

ड्रोन हमले में ओमान के पास भारतीय जहाज डूबा, भारत ने कहा- ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं

- 'हाजी अली' पर 13 मई की सुबह हुआ हमला, आग लगने के बाद डूब गया
- ओमान कोस्ट गार्ड ने सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया

नई दिल्ली, प्रेट्र : पश्चिम एशिया में जारी तनातनी के बीच होर्मुज स्ट्रेट से सटे ओमान तट के पास एक हमले में भारतीय झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया। 'हाजी अली' नाम का यह जहाज 13 मई की सुबह साढ़े तीन बजे के करीब जब ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजर रहा था तो उस पर ड्रोन या मिसाइल जैसा हथियार से हमला किया गया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और वह अस्थिर होकर डूब गया। हालांकि, ओमान कोस्टगार्ड ने जहाज पर सवार सभी 14 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया।

अभी यह नहीं पता चल पाया है कि जहाज पर हमले को किसने अंजाम दिया। इस बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ऐसे हमलों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यह जहाज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सालया पोर्ट में पंजीकृत था और सोमालिया से शारजाह जा रहा था।

भारत के लिए एलपीजी ला रहे दो और टैंकर होर्मुज से निकले

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत आ रहे दो एलपीजी टैंकरों ने सुरक्षित रूप से होर्मुज स्ट्रेट पार किया। बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी टैंकर 'सिमी' ने 13 मई व 'एनवी सनसाइन' ने गुरुवार को होर्मुज पार किया। इन जहाजों के होर्मुज से निकलने के साथ ही अमेरिका-इजरायल व ईरान जंग के चलते बंद इस शिपिंग चैनल को पार करने वाले भारतीय जहाजों की कुल संख्या 13 हो गई है। 'सिमी' 19,965 टन एलपीजी लेकर आ रहा है। इस जहाज के 16 मई को कांडला बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा 'एनवी सनसाइन' पर 46,427 टन एलपीजी है और इसके 18 मई को न्यू मंगलोर पहुंचने की उम्मीद है।

गौतम अदाणी के खिलाफ जल्द मामला वापस ले सकते हैं अमेरिकी अधिकारी

नई दिल्ली, आइएएनएस : गौतम अदाणी और उनके समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को जल्द ही समाप्त करने की तैयारी में हैं। एक साल से अधिक समय से लंबित इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग इसी सप्ताह आरोपों को वापस लेने की घोषणा कर सकता है।

अमेरिकी न्याय विभाग के साथ-साथ प्रतिभूति और विनिमय आयोग भी नवंबर 2024 में शुरू किए गए नागरिक धोखाधड़ी के मामले को सुलझाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह पूरा मामला सौर ऊर्जा अनुबंधों को सुरक्षित करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर 25 करोड़ डालर से अधिक की रिश्वत देने और अमेरिकी निवेशकों से इसे छिपाने के आरोपों से संबंधित था।

रूस का यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला

1,560 ड्रोन और 100 मिसाइलें दागीं, 11 मरे, दर्जनों घायल

- यूक्रेन ने चीन और अमेरिका से हमले रुकवाने का किया अनुरोध

यूक्रेन में गुरुवार को रूसी हवाई हमले के दौरान भीषण विस्फोट से कीव के आसमान में दिखा ऐसा भयावह दृश्य। रायटर

कीव, रायटर : रूस ने यूक्रेन पर चार वर्ष से चल रहे युद्ध का सबसे बड़ा हवाई हमला किया है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई प्रमुख शहरों पर बुधवार-गुरुवार को 1,560 से ज्यादा ड्रोन और करीब 100 मिसाइलें दागीं। इन हमलों में कीव में पांच लोग और अन्य स्थानों पर छह लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए हैं। हमलों से नागरिक सुविधाओं को भी भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने अमेरिका और चीन से रूसी हमलों को रुकवाने का अनुरोध किया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि इनमें से ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें आकाश में ही नष्ट कर दिए गए लेकिन बाकी ने यूक्रेनी शहरों को भारी नुकसान पहुंचाया। नष्ट किए गए ड्रोन और मिसाइलों के टुकड़ों से भी भवनों और नागरिक सुविधाओं को नुकसान हुआ है। जेलेंस्की ने कहा, इस हमले से जल्द युद्ध खत्म होने की संभावना पर विश्वास नहीं होता है। विदित हो कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने की संभावना जताई थी। जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए सहयोगी देशों से ज्यादा सहायता और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है।

जेलेंस्की ने बताया है कि कीव के 20 स्थानों पर रूस के हमले हुए हैं। इन हमलों में पांच लोग मारे गए और दो बच्चों समेत 40 घायल हुए हैं। ड्रोन हमले में एक नौ मंजिला भवन ध्वस्त हो गया है। राहतकर्मी कंक्रीट की परतें हटाकर उनके नीचे दबे लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसलिए हमले में मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। गृह मंत्री इहोर क्लीमेंको ने 10 लोगों के लापता होने की जानकारी दी है। जेलेंस्की ने बताया है कि ताजा रूसी हमलों में यूक्रेन में 180 ठिकानों को नुकसान हुआ है। इनमें 50 से ज्यादा आवासीय भवन हैं। हमलों से कीव की पानी-बिजली की आपूर्ति बाधित हुई है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव में हमले से तीन बच्चों समेत 28 लोग घायल हुए हैं। ऊर्जा संयंत्रों पर हुए हमलों से देश के 11 प्रांतों की बिजली आपूर्ति में बाधा आई है।

ईरान मुद्दे पर ट्रंप और रूबियो के सुर अलग, चीन की भूमिका को लेकर बढ़ा असमंजस

- ट्रंप बोले- ईरान से निपटने में चीन समेत किसी देश की मदद की जरूरत नहीं
- रूबियो ने कहा, ईरान युद्ध संकट सुलझाने में चीन की बड़ी भूमिका चाहता है अमेरिका

वाशिंगटन, एएनआइ: ईरान युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के संकट को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बयानों में स्पष्ट विरोधाभास दिखा है। जहां ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को ईरान से निपटने में चीन समेत किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, वहीं रूबियो ने बीजिंग से अधिक सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाने की अपील की है। एयर फोर्स वन में फाक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में रूबियो ने कहा कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि वह संयुक्त राष्ट्र में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव का समर्थन करे और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव कम कराने में भूमिका निभाए।

उन्होंने कहा कि इस संकट का असर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री यातायात पर पड़ रहा है। रूबियो ने कहा कि चीन के कई जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं और चीन की अर्थव्यवस्था इस समुद्री मार्ग पर काफी निर्भर है। उनके अनुसार, यदि संकट लंबा खिंचता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और चीनी निर्यात पर भी गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव डालकर उसे पीछे हटने के लिए राजी करे। इसके विपरीत, ट्रंप ने व्हाइट हाउस से चीन रवाना होने से पहले कहा कि अमेरिका को ईरान मामले में किसी मदद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, हम किसी न किसी तरह जीतेंगे, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से या दूसरे तरीके से।' ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उनकी बातचीत में ईरान प्रमुख मुद्दा नहीं होगा।

रूबियो ने चीन को अमेरिका की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बताते हुए कहा कि दोनों देशों के हित कई मामलों में टकराते हैं, लेकिन वैश्विक शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संबंधों का प्रबंधन जरूरी है।

डोनाल्ड ट्रंप

मार्को रूबियो

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

अमेरिका-चीन से उम्मीद

अमेरिका-चीन की शिखर वार्ता पर दुनिया की निगाह है और वहां से आ रही खबरों पर दुनिया में मिली-जुली प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन में हैं और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। हर मुलाकात से कुछ खास बातें छनकर सामने आ पा रही हैं। आश्चर्य नहीं, दोनों नेताओं के बीच वार्ता की खबरें चीन से कम और अमेरिका से ज्यादा आ रही हैं। मोटे तौर पर दोनों देश व्यापार समझौता करना चाहते हैं, जिसके लिए दक्षिण कोरिया में दोनों के बीच बातचीत पहले से चल रही थी। यह व्यापार समझौता पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। यहां यह ध्यान रखने की बात है कि दुनिया में टैरिफ को लेकर जो युद्ध अमेरिका ने छेड़ा, उसका पहला निशाना चीन ही था। चीन के प्रति ट्रंप शिकायतों से भरे हुए थे, लेकिन दुनिया में अर्थव्यवस्था आधारित भू-राजनीति ने ट्रंप को चीन के प्रति नरम होने के लिए मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका की मजबूरी का फायदा चीन नहीं उठाए, ऐसा हो नहीं सकता। ट्रंप अगर अपनी इच्छाओं को लेकर मुखर हैं, तो शी जिनपिंग को भी अपने देशहित में किसी भी हद तक जाने में कोई संकोच नहीं है।

आश्चर्य नहीं, मौका देखकर चीन ने कुछ बातें बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। ट्रंप के चीन दौरे में एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि बीजिंग अब अमेरिका के सामने लक्ष्मण रेखा खींचने लगा है। वह चाहता है कि अमेरिका ताइवान पर कुछ न बोले, मानवाधिकार और लोकतंत्र का नाम न ले, अपने हिसाब से व्यापार करने के चीन के अधिकार का सम्मान करे। अच्छे रिश्तों के लिए चीन द्वारा अमेरिका के सामने रखी गई शर्तों पर ट्रंप सार्वजनिक रूप से खामोश रहना ही पसंद करेंगे। ये ऐसे अहम मुद्दे हैं, जिन पर अमेरिकी रुख समय और देश के मुताबिक बदलता रहता है। आज चीन ऐसी अहमियत या दर्जा मांग रहा है, जैसा अमेरिका ने आज तक किसी देश को नहीं दिया है। दुनिया में कुछ भी करने-बोलने को अमेरिका अपना अधिकार मानता आया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने अमेरिका के इस अधिकार को चुनौती दी है। कोई दोराय नहीं, अगर ट्रंप चीन से सहमत हो गए, तो विश्व व्यवस्था बदल जाएगी। वैसे, अगर ट्रंप प्रशासन चीन की इस मांग पर चुप भी रह गया, तब भी शी जिनपिंग के लिए यह 'हां' के बराबर होगा। यहां एक और बात गौर करने की है। ट्रंप के चीन जाने का एक मकसद उसे अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार करने से रोकना भी है। हालांकि, इस पर चीन को मना पाना नामुमकिन ही लगता है।

पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता पश्चिम एशिया में जारी तनाव है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इस समस्या का कोई हल निकलेगा।

बहरहाल, आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी चिंता पश्चिम एशिया में जारी तनाव है। ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात से सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि इस समस्या का हल निकले। होर्मुज मार्ग फिर खुल जाए। चीन अगर चाहे, तो ईरान को समझौते के लिए प्रेरित कर सकता है, पर यहां ट्रंप की आक्रामकता को कम करना भी जरूरी है। वह एक ही वाक्य में ईरान को युद्ध-विराम के लिए पुचकारते हैं और धमकाते भी हैं। ट्रंप की इस शैली ने दुनिया को आर्थिक तबाही के मुहाने पर पहुंचा दिया है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं दुनिया आर्थिक मंदी के भंवर में न फंस जाए। यहां चीन की भी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों है कि दुनिया में कहीं भी युद्ध होता है, तब चीन किसी न किसी पक्ष के साथ एक आपूर्तिकर्ता के रूप में मजबूती से खड़ा दिखता है? बेहतर होगा, अमेरिका और चीन दुनिया में समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा बनें। ठीक वैसा ही व्यवहार करें, जैसा ये स्वयं अपने साथ चाहते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 15 मई, 1951

शेख अब्दुल्ला का स्पष्टीकरण

संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा काश्मीर के संबंध में नियुक्त श्री ग्राहम जब यहां आने की तैयारी कर रहे हैं, काश्मीर के लोकनेता और मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर के संबंध में ऐसा स्पष्टीकरण किया है, जिसके बाद शंका की कोई वजह नहीं रह जाती। बम्बई के एक विद्यार्थी-समूह की जिज्ञासा-निवारण करते हुए शेख साहब ने बताया है कि राज्य के लोग अपनी प्रतिनिधि-संस्था नेशनल कान्फ्रेंस के द्वारा 1947 में ही काश्मीर के भारत में शामिल होने का फैसला कर चुके थे और उसी की अन्तिम रूप से पुष्टि करने के लिए अब विधान-सभा आयोजित की जा रही है। पाकिस्तान द्वारा लोकमत के आग्रह पर उनका कहना है कि यदि वह सचमुच लोकमत चाहता है तो उसे काश्मीर से चले जाना चाहिए, क्योंकि लोकमत तभी लिया जा सकता है जब सारा प्रदेश महाराजा की वैध सरकार को पुनः प्राप्त हो जाये, क्योंकि 1947 में-जब काश्मीर ने भारत में मिलने का फैसला किया- एकमात्र महाराजा को ही इस या उस उपनिवेश में मिलने का फैसला करने का अधिकार था। उपस्थित सरकार का स्थान 'तटस्थ सरकार' द्वारा लेने की बात को 'वाहियात' बताते हुए शेख साहब ने ठीक ही कहा है कि तटस्थ सरकार का अर्थ क्या है? अगर चुनाव के लिए ऐसी सरकार पर जोर दिया जाये, तो क्या पश्चिमी पंजाब में चुनाव के पहले मौजूदा सरकार को भंग क्यों नहीं किया गया और ब्रिटेन व अमरीका में चुनाव से पहले एटली व ट्रूमन की सरकारों को भंग क्यों नहीं किया गया?

एक बात यह भी कही जाती है कि भारत-पाकिस्तान के झगड़े की हालत में काश्मीर को स्वतंत्र क्यों न रखा जाये? कुछ स्वयं शेख साहब के उद्गारों से भी यह आशंका करते रहे हैं कि वह काश्मीर को स्वतंत्र बना लेना चाहते हैं। शेख साहब ने इस बार इस बारे में भी असंदिग्ध स्पष्टीकरण किया है। उनका कहना है कि आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में काश्मीर को स्वतंत्र रखने का विचार एक असंभव और अव्यावहारिक विचार है। प्रथम तो रूस और अमरीका के सिवा आज वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र है ही कौन, फिर काश्मीर ऐसे छोटे से राज्य के लिए स्वतंत्र रहना कहां संभव, जो विभिन्न उद्देश्यों वाले पांच राष्ट्रों से घिरा हुआ है? ऐसी स्थिति में स्वतंत्र रहने का विचार, शेख साहब के हिसाब से, आत्महत्या से अधिक नहीं है।

सोने की खरीद में संयम जरूरी

यहां स्कैन करें

सौम्य कांति घोष | सदस्य, 16वां वित्त आयोग

साल 2024 में घरेलू आपूर्ति का लगभग 86 फीसदी सोना आयात किया गया था, जिससे बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी। अभी विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण बहुत जरूरी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने के लिए लोगों से सोने की खरीद से बचने, घर से काम करके ईंधन की खपत कम करने और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं को टालने जैसे उपाय अपनाने की अपील की है। उन्होंने यह आह्वान मौजूदा वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई अस्थिरता को देखते हुए किया है। इस पर चर्चा करने से पहले हमें उन संकेतकों पर नजर डालनी चाहिए, जिनसे पता चलता है कि बीते वर्षों में भारत की आर्थिक सेहत कैसी रही?

आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024, 25 और 26 (साल 2025-26) में भारतीय अर्थव्यवस्था ने करीब 7.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। इस दौरान महंगाई दर औसतन चार फीसदी, बैंकों का औसत शुद्ध लाभ 3.8 लाख करोड़ रुपये, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात की औसत वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत, बेरोजगारी दर 3.1 फीसदी और विदेशी मुद्रा भंडार 691 अरब डॉलर रहे हैं। इस काल-खंड में कुल आयात में पेट्रोलियम और सोने का हिस्सा लगभग 33 फीसदी रहा।

इस व्यापक आर्थिक मजबूती के विपरीत, अप्रैल 2025 से अब तक डॉलर के मुकाबले रुपये में 11.2 फीसदी की गिरावट आई है, जबकि दक्षिण-पूर्व एशियाई मुद्राओं में औसतन 5.3 फीसदी की वृद्धि देखी गई है। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की मुद्राओं में तो औसतन 13.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में डॉलर सूचकांक में 5.6 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, एक तथ्य यह भी है कि इस दौरान निवेश पूंजी (पोर्टफोलियो कैपिटल) बाहर जाती रही, जो 1991 के बाद सबसे अधिक है। इस वर्ष जनवरी से अब तक 21.3 अरब डॉलर की राशि बाहर जा चुकी है। साफ है, रुपये के मूल्य में अभी जो गिरावट दिख रही है, उसकी वजह भारत की आर्थिक नीति नहीं है। आरबीआई ने भी अपने हालिया बयान में इसका जिक्र किया है। फिर रुपये में इस गिरावट की वजह क्या है?

एक संभावित कारण यह है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काफी समय तक रुपये को 'शॉक-एब्जॉर्बर' (झटका सहने वाले औजार) के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसका शुरू-शुरू में तो फायदा मिला था, लेकिन एक समय के बाद निर्यात पर इसका असर खत्म हो गया और आयात भी बढ़ने लगा। चूंकि रुपया शॉक-एब्जॉर्बर के रूप में काम कर रहा था, इसलिए बाजार भी इसमें शामिल हो गया। बाजार के खिलाड़ी डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने का दावा कर रहे थे, लिहाजा लगता है कि वह 'सेल्फ-फुलफिलिंग प्रोफेसी' (ऐसी परिस्थिति के बारे में भविष्यवाणी, जो इंसानी व्यवहार में बदलाव के कारण सच हो जाए) सच हो गई, जबकि व्यापक आर्थिक कारक (मैक्रो-फंडामेंटल्स) कुछ और संकेत दे रहे थे। भले ही रुपये की कीमत में गिरावट भारत की 'मैक्रो-फंडामेंटल्स' की सीमाओं से परे है, पर हमें मौजूद विकल्पों पर गौर करना ही चाहिए।

सैद्धांतिक रूप से देखें, तो भुगतान संतुलन के मुद्दे को सुलझाने और भारत के आर्थिक कारकों के अनुकूल रुपये की कीमत बनाए रखने के लिए एक व्यापक नीति की जरूरत है। डॉलर के मूल्य में हर एक रुपये की बढ़ोतरी होने पर, भारत की जीडीपी में लगभग 60 अरब डॉलर की गिरावट हो सकती है।

अब आइए, प्रधानमंत्री के सुझावों को समझते हैं। सबसे पहले सोने की बात। भारत हरेक साल लगभग 750-800 टन सोना आयात करता है। घरेलू बाजार में स्थानीय सोने की आपूर्ति बेहद कम है। 2024 में घरेलू आपूर्ति का 86 फीसदी सोना आयात किया गया था, जिसके कारण बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी। हालांकि, ओडिशा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश में सोने की नई खानों की खोज से आयात पर दबाव कम हो सकता है, जो हमारे चालू खाता में संतुलन के लिए जरूरी है, किंतु इसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए, आयात कम करने के लिए सोने की खरीद में संयम बरतना बुरा फैसला नहीं है।

केंद्र सरकार ने अब सोने सहित कीमती धातुओं के आयात पर सीमा शुल्क छह फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। अब एक दशक पूर्व घोषित स्वर्ण मुद्रीकरण नीति को भी विस्तार देना चाहिए। आरबीआई की 1992 की सिफारिश के अनुसार सोने पर एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए। इस नीति में व्यापार, अति-शुद्ध कीमती धातुओं के आयात, आभूषण निर्यात, निवेश आदि शामिल किए जाने चाहिए। सोने की कीमतों में वृद्धि का सकारात्मक पक्ष यह है कि 'गोल्ड लोन' में भी उछाल आया है। वित्त वर्ष 2025-2026 के अंत तक यह करीब 7.5 लाख करोड़ रुपये का था। इस तरह के कर्ज विशेषकर छोटे व सीमांत किसानों, बटाईदारों और खेती-बाड़ी के कामों में लगे लोगों के लिए अल्पकालिक कृषि ऋण के प्रमुख स्रोत होते हैं।

अब बाहर जाने वाले पैसों की चर्चा। वित्त वर्ष 2022-26 के दौरान, 'लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम' (एलआरएस) के तहत भारतीयों ने लगभग 136 अरब डॉलर रकम विदेश भेजे, जिसका 77 फीसदी हिस्सा अचल संपत्ति की खरीद, कर्ज/इक्विटी में निवेश, उपहार और विदेश यात्रा खर्च के रूप में बाहर गया। वित्त वर्ष 2013 में रिजर्व बैंक ने एलआरएस की सीमा को दो लाख डॉलर से घटाकर 75,000 डॉलर कर दिया था। अब इस सीमा का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए।

इसी तरह, एनआरआई बॉन्ड पर भी विचार-विमर्श होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्कीम लाने की मौजूदा लागत काफी ज्यादा हो सकती है। विदेशी निवेशकों के लिए भी कर ढांचे पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिसमें 2023 के बाद बदलाव आया है। निस्संदेह, युआन-आधारित लेन-देन में आए उछाल ने भी गिरते रुपये की चर्चा करने वालों का ध्यान खींचा होगा, लेकिन तथ्य कुछ और संकेत देते हैं। आंकड़ों की मानें, तो मार्च 2026 तक लगभग 97.6 प्रतिशत स्पॉट युआन लेन-देन डॉलर में निपटाए गए थे, यानी युआन से जुड़े अधिकतर विदेशी मुद्रा स्पॉट मार्केट लेन-देन अब भी मुख्य रूप से डॉलर में ही हो रहे हैं।

इन सबको देखते हुए 'ब्रिक्स पे' की तरह 'ब्रिक्स प्लस मुद्रा' विकसित करना जरूरी है। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि 'ग्लोबल साउथ' के व्यापार में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी 40 फीसदी से अधिक है। जाहिर है, अब ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है, जिसका नेतृत्व ब्रिक्स प्लस करे और जो वैश्विक मुद्रा बाजार के व्यवहार को उसी तरह आमूल-चूल बदल सके, जिस तरह 'ब्रेटन वुड्स प्रणाली' ने बदला था।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

जोशीमठ में भूमि धंसाव को रोकने की कवायद

यहां स्कैन करें

वीरेंद्र कुमार पैन्यूली | पर्यावरणविद् व सामाजिक कार्यकर्ता

बारिश का समय आने को है और पर्यावरण को लेकर चिंता बहुत बढ़ गई है। ऐसे में, जोशीमठ की नींव को मजबूत करने की कवायद सबका ध्यान खींच रही है। इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर को बचाना जरूरी है।

उत्तराखंड के हिमालय में 1,875 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लगभग 25 हजार की आबादी वाला जोशीमठ सामरिक, धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण नगर है। भारत-चीन सीमा के पास स्थित यह नगर बदरीनाथ धाम, श्री गुरुद्वारा हेमकुण्ड साहिब, औली स्कीइंग स्थल, फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क तक पहुंचने का प्रमुख पड़ाव है। ज्योतिर्मठ के नाम से भी चर्चित यह नगर आदि गुरु शंकराचार्य की तपःस्थली है। यह बदरीनाथ भगवान की शीतकालीन गद्दी स्थल है। बारहमासी तीर्थ यात्रा में भी जोशीमठ की महत्ता है।

लोग भूले नहीं हैं, दिसंबर 2022 में जोशीमठ में कैसे असामान्य भूधंसाव दिखने लगा था, वह दुनिया भर में एक बड़ी खबर थी। सैटेलाइट डाटा के आधार पर बताया गया था कि 2018 से 31 दिसंबर, 2022 के बीच जोशीमठ में प्रतिवर्ष करीब 10 सेंटीमीटर भूधंसाव हुआ है। वहां चौदह बेहद जोखिम भरे इलाके चिह्नित किए गए थे। उस समय सरकार ने जोशीमठ व राज्य के अन्य शहरों की भी भूमि क्षमता का अध्ययन कराने को कहा था। हालांकि, यह काम अभी तक नहीं हुआ है। निगरानी का भी अभाव देखा जा रहा था। तीन साल बीतने के बाद अब जोशीमठ के स्थिरीकरण का काम हो रहा है। वैसे, जोशीमठ का अगले तीन साल में, यानी 2027 तक स्थिरीकरण का भरोसा अप्रैल 2024 में राज्य के तत्कालीन आपदा प्रबंधन सचिव ने जोशीमठ की जनता को दिया था। जाहिर है, स्थिरीकरण का यह काम भू-वैज्ञानिकों का सहयोग लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए।

इस महत्वपूर्ण नगर में भू-धंसाव को रोकने का कोई भी ठोस प्रयास स्वागतयोग्य है, लेकिन लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है।

जीएसआई ने जोशीमठ में 81 दरारों को चिह्नित किया था। इनमें से 42 तो जनवरी 2023 के भूधंसाव के थे। कुछ जगह जल-रिसाव को भी कारण बताया गया था। भूविज्ञानियों के अनुसार, जोशीमठ नगर अतिशय तीखी ढलानों पर बसा है। 1970 के दशक से भूधंसाव को चिह्नित किया जा रहा था। साल 1976 में ही तत्कालीन गढ़वाल मंडलायुक्त की समिति ने यहां निर्माण नियंत्रण का सुझाव दिया था। उस समिति ने ही बताया था, जोशीमठ किसी ठोस चट्टान पर आधारित नहीं है। इस क्षेत्र में भारी निर्माण पर रोक की सलाह के बावजूद नगर के नीचे 12 किलोमीटर लंबी सुरंग की परियोजना को 2005 में पर्यावरणीय मंजूरी भी दे दी गई थी। दुर्भाग्य से यह सुरंग साल 2009 में क्षतिग्रस्त हो गई।

'जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति' का कहना है कि एक तरफ, एनटीपीसी की सुरंग ने जमीन को भीतर से खोखला कर दिया है, तो वहीं बाइपास सड़क के लिए जोशीमठ की जड़ पर खुदाई पूरे शहर को नीचे से हिला रही है। जो भी हो, अप्रैल 2024 के आश्वासन के दो साल बाद अब अप्रैल 2026 में स्थिरीकरण के कार्य की आधिकारिक शुरुआत हुई है। यहां समिति को भरोसे में लेकर चलने की जरूरत है। यहां के लोग जानना चाहते हैं कि स्थिरीकरण के जो प्रयास हो रहे हैं, वे कितनी सुरक्षा देंगे और कितने स्थायी होंगे?

यहां भूधंसाव को रोकने का कोई भी ठोस व स्थायी प्रयास स्वागतयोग्य है, लेकिन लोगों को विश्वास में लेना जरूरी है। जो क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील हैं, वहां पहले काम करने की जरूरत है। 'वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी' को भी साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सितंबर 2023 में ही जोशीमठ पर अपनी वैज्ञानिक रिपोर्ट में इस संस्थान ने जो चेतावनी दी थी, उसके प्रति संवेदशील होना जरूरी है। बीते तीन वर्षों में जोशीमठ में क्या बदलाव हुए हैं, इसका गहन अध्ययन जरूरी है। नई समस्या है, यहां भूधंसाव ही नहीं, अब भूफिसलाव भी हो रहा है। इससे सतही और भूमिगत अस्थिरता आ जाती है।

चिंता जताई जा रही है कि जब जोशीमठ की गहराइयों में 80 मीटर तक भी ठोस चट्टान का अता-पता नहीं है, जिसकी भूमि अलकनंदा नदी की ओर खिसक रही है, उसमें दस-बारह मीटर पर रॉक बोल्टिंग्स से स्थिरता कैसे लाई जा सकेगी? जोशीमठ पर पूरे देश की नजर है। इस पुराने नगर को अगर बचाया और फिर बसाया जाता है, तो यह पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

ईश्वर ढूंढ़ने निकले हो

दुनिया के दूसरे हिस्सों में ऐसा विश्वास किया जाता होगा कि मनुष्य का सृजन करने वाला ईश्वर है, लेकिन हमारी संस्कृति में देवताओं का सृजन इंसान ने किया। मानव को उच्चतम अवस्था तक पहुंचाने में सहायक के रूप में यहां अनेक देवता सृजित किए गए। उनमें से कुछ देवता आकर्षक हैं, कुछ डराने वाले हैं, कुछ प्रेम-स्वरूप हैं, तो कुछ उग्रमूर्ति हैं। इनमें से हरेक रूप का मानव के विकास के लिए उपयोग किया गया।

तब क्या ईश्वर केवल काल्पनिक पात्र हैं? क्या हमें उनके बारे में चिंता नहीं करनी है? एक छोटा सा बीज माटी के अंदर गिरने पर विशाल वृक्ष के रूप में बढ़ जाता है, कैसे? इस बीज से इसी तरह का पेड़ उगेगा। इन विधि-विधानों का नियामक कौन है? आपसे परे जो शक्ति है, उसे ईश्वर न कहें, तो फिर क्या कह सकते हैं? कुछ शताब्दी पहले आपकी संपूर्ण शक्ति को जगाकर बाहर निकाल लाने के अनेक अनुष्ठान देश में हुए थे। बाद में वे सब विकृत होकर प्रार्थना और मनौतियों के रूप में बदल गए। मंदिर नामक संस्थान ईश्वर से मांगें पेश करने का दरबार नहीं है। मंदिर दरअसल एक शक्ति-केंद्र है। वहां शक्ति को स्थापित करने के लिए रचा गया रूप ही ईश्वर है।

जब कोई बाधा आती है, आप पहले अपनी शारीरिक शक्ति से उसे हटाना चाहते हैं। जब वह संभव नहीं होता, तब उसका सामना करने की दिशा में चिंतन करते हैं। जब शरीर और मन, दोनों मिलकर क्रियाशील होते हैं, तो क्षमता बढ़ जाती है। इनके साथ संवेदना को मिलाने पर आपकी बुद्धि एक अनोखे आयाम में पहुंच जाती है। यदि आप अपनी आंतरिक शक्ति का इनके साथ संयोजन करके दृढ़ बनाएंगे, तो परिणाम अद्भुत निकलेंगे। आपके अंदर उसी शक्ति का विकास करने के लिए मंदिर नामक शक्ति-केंद्रों की स्थापना की गई। ज्ञानी-पुरुषों ने अपनी शक्ति का लाभ दूसरों को मिले, इस उद्देश्य से निवेश के रूप में मंदिरों का निर्माण किया। दुर्भाग्य से बाद की पीढ़ियों ने उस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता गंवा दी। फिर भी, मन में छल-कपट के बिना सौ फीसदी निष्ठा के साथ मंदिरों में जाएंगे, तो वह शक्ति काम करेगी।

यदि आपके अंदर यह जानने की इच्छा जाग उठे कि ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं, तो आप किससे पूछकर जानेंगे? अपनी इस खोज को, तलाश को खुद अपने से शुरू कीजिए। यदि यह बात सही है कि असीम परमेश्वर सब जगह व्याप्त है, तो आपके अंदर भी उसका वजूद होना जरूरी है। है न? साकार रूप में उसे ढूंढ़ना छोड़कर पहले देवत्व को अपने अंदर ढूंढ़कर देखिए। यदि अपने अंदर ईश्वर की सत्ता का अनुभव हो जाए, तो फिर आप मान सकते हैं कि वह यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है।

देवत्व को अपने अंदर ढूंढ़कर देखिए। यदि अपने अंदर ईश्वर की सत्ता का अनुभव हो जाए, तो फिर आप मान सकते हैं कि वह यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

वैश्विक चुनौतियों के दौर में ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता व संसाधनों का संतुलित उपयोग हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लें, तो मजबूत भविष्य की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।

अनुलोम-विलोम

यात्रा में अभद्रता

एक खतरनाक प्रवृत्ति की शुरुआत

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हवाई यात्रा के दौरान हुई कथित अभद्रता और घेराव की घटना केवल राजनीतिक विवाद नहीं है। यह लोकतांत्रिक मर्यादा, महिला सम्मान, नागरिक अधिकार और सार्वजनिक जीवन में आचरण के स्तर पर गंभीर प्रश्न भी खड़े करती है। यदि किसी जन-प्रतिनिधि, विशेषकर एक महिला सांसद, को वैचारिक मतभेद, राजनीतिक विचार या किसी रिपोर्ट के कारण सार्वजनिक तौर पर अपमानित किया जाता है, तो वह केवल व्यक्तिगत गरिमा पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की आत्मा पर भी आघात है।

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में असहमति व्यक्त करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन असहमति और आक्रामकता के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। इसे कतई पार नहीं करना चाहिए। जब किसी महिला को घेरकर, दबाव बनाकर या भय का वातावरण बनाकर अपनी बात मनवाने या विरोध दर्ज कराने का प्रयास किया जाता है, तो यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा नहीं, बल्कि भीड़तंत्र की प्रवृत्ति का संकेत है।

यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि राजनीतिक मतभेद का अर्थ व्यक्तिगत अपमान नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति, वह भी महिला की गरिमा उसके राजनीतिक विचारों से बड़ी होती है और संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा व सुरक्षा का अधिकार देता है। संसद सदस्य होने के नाते महुआ मोइत्रा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि जनता की निर्वाचित प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके साथ हुई किसी भी तरह की अभद्रता लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान से भी जुड़ जाती है। विपक्षी नेताओं द्वारा इस घटना की निंदा करना स्वाभाविक है, क्योंकि यह मुद्दा किसी एक दल का नहीं, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक जीवन में सम्मानजनक व्यवहार का भी है। यदि ऐसे मामलों में कठोर संदेश नहीं दिया गया, तो भविष्य में यह प्रवृत्ति सामान्य होती जाएगी और राजनीतिक असहमति के नाम पर किसी को कहीं भी अपमानित करने की कोशिश की जा सकती है।

लिहाजा इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की पहचान की जाए और कानून के अनुसार कार्रवाई हो, ताकि यह संदेश जाए कि भारत में किसी भी महिला, चाहे वह आम नागरिक हो या जन-प्रतिनिधि के सम्मान और उसकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र की शक्ति संवाद, सहिष्णुता और परस्पर सम्मान में है, भय, अपमान और भीड़ के दबाव में नहीं।

वीरेंद्र कुमार जाटव, टिप्पणीकार

अपना ही बोया हुआ काट रहीं महुआ

तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने वीडियो पोस्ट करके बताया कि हवाई यात्रा के दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई और लोगों ने नारेबाजी की। इस घटना के खिलाफ एक 'खास इकोसिस्टम' छाती भी पीट रहा है, लेकिन ऐसे लोग उस वक्त कहां थे, जब खुद को कॉमेडियन बताने वाले कुणाल कामरा ने वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ हवाई जहाज में बदसलूकी की थी। कुणाल कामरा को तो इन लोगों ने हीरो बना दिया था। इससे पता चलता है कि ये लोग किस तरह दोहरा चरित्र जीते हैं।

जब महिला पत्रकारों के पीछे भीड़ जा-जाकर उन्हें डराने का प्रयास करती है, तब यही लोग कहते हैं कि 'गोदी मीडिया' के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। जब खुद उनके साथ ये सब होता है, तो वे झुंड में छाती पीटने लगते हैं। इनके लिए कुछ भी तभी गलत है, जब इनके साथ हो। यह दोहरा रवैया नहीं चलेगा।

प्रदीप ताम्हणकर, टिप्पणीकार

सांसद महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ, पहले उसे समझिए। उनका कहना है कि दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में उनके साथ बदसलूकी हुई। उन्हें कुछ यात्रियों ने घेर लिया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। महुआ मोइत्रा के अनुसार, यह घटना उस समय हुई, जब वह रक्षा मामलों की संसद की स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रही थीं। सांसद द्वारा साझा किए गए वीडियो में कुछ लोग कथित तौर पर 'चोर-चोर' और 'जय श्री राम' के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। ऊपरी तौर पर निश्चय ही ऐसी घटना गलत लगती है, लेकिन इसे यदि गहराई में देखें, तो आप समझ जाएंगे कि लोग 'नाराज' क्यों हैं? दरअसल, राजनीति सार्वजनिक जीवन से जुड़ा कर्म है, इसलिए राजनेता से अपेक्षा की जाती है कि वह संयम नहीं खोएंगे और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, जिनसे आम जनमानस को कष्ट हो। तृणमूल सांसद राजनीति की इस बुनियादी अवधारणा को ही भूल बैठी हैं। उनके पिछले कुछ बयानों को देखकर आप समझ सकते हैं कि वह कैसे किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए बहुसंख्यकों के खिलाफ बोलती रही हैं। ऐसे में, लोग उनसे नाराज होंगे ही। इन जैसे तृणमूल नेताओं के कारण ही तो पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हारी है। किंतु इन्हें फिर भी समझ नहीं आ रहा है। इसलिए दोष लोगों में देखने के बजाय महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं को अपनी कमियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अगर उन्होंने ईमानदारी से आत्म-चिंतन किया, तो उन्हें फिर से लोगों का प्रेम मिलेगा। किंतु ऐसा होगा, इस पर संदेह है।

दीपक वत्स, टिप्पणीकार

अपनी आंखों को संक्रमण से बचाएं

आंखों का संक्रमण केवल वायरस या बैक्टीरिया की देन नहीं रहा है। आधुनिक जीवनशैली, डिजिटल थकान और लगातार बढ़ते प्रदूषण से भी आंखों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि, समय रहते सही उपचार से आंखों को ज्यादातर संक्रमण से बचाया जा सकता है। आंखों के मामले में लापरवाही न करें, बता रही हैं अंशु सिंह

आंखों के संक्रमण के मामलों में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस सबसे ऊपर है। शुष्क मौसम, बढ़ता प्रदूषण एवं पराबैंगनी किरणें एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस समेत अन्य संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, बढ़ते प्रदूषण की वजह से कंजंक्टिवाइटिस के मामलों में 20 फीसदी और एलर्जी से जुड़ी आंखों की समस्याओं में 60 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

दिल्ली स्थित एम्स की पूर्व नेत्र विशेषज्ञ डॉ. उषा भटनागर बताती हैं, 'प्रदूषण और निर्माण कार्य आंखों की पुतलियों पर मौजूद संवेदनशील परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे संक्रमण का फैलाव बढ़ता है। गर्मियों व मानसून में वायरल कंजंक्टिवाइटिस का अधिक प्रकोप देखा जाता है। लंबे समय तक काम करने और स्क्रीन के संपर्क में रहने से आंखों की इम्युनिटी कम हो रही है, जिससे आंखों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। घरों में इस्तेमाल होने वाले क्लीनर, कॉस्मेटिक्स एवं स्विमिंग पूल के कीटाणुनाशकों में पाए जाने वाले रसायन भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं।

कैसे होता है आंखों का संक्रमण ?

आंखें शरीर का सबसे नाजुक अंग होती हैं। रेटिना तक रोशनी पहुंचे और हम ढंग से देख सकें, इसके लिए आंखें अपनी सतह को बाहरी तत्वों से बचाए रखते हुए उन्हें पारदर्शी बनाए रखती हैं। गंगाराम अस्पताल की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ इकेदा लाल बताती हैं, 'आंख की सतह पर एक खास तरह का 'माइक्रोबायोम' मौजूद होता है, जो रोग पैदा करने वाले जीवों की बढ़त को नियंत्रित करता है। सामान्य स्थितियों में पलकें, आंसुओं की परत और रोगाणु-रोधी तत्व जैसी आंख की सुरक्षा दीवारें, आंख को बाहरी खतरों से बचाती हैं। विभिन्न कारणों से जब ये सुरक्षा-प्रणालियां कमजोर पड़ जाती हैं, तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।

आंखों में संक्रमण तब होता है, जब हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट आंख के किसी भी हिस्से में प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति के तौलिये, रूमाल, तकिये या कॉस्मेटिक्स जैसी निजी चीजों का आपस में इस्तेमाल करने से इंफेक्शन फैलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा, बार-बार आंखों को छूने या रगड़ने से भी इंफेक्शन फैलता है।

संक्रमण के आम लक्षण : आंखों में लालिमा, जलन, खुजली, दर्द, सूजन, आंखों में रेत सा महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, चिपचपा द्रव्य निकलना और रोशनी के प्रति संवदेनशील होने जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं।

कंजंक्टिवाइटिस सबसे आम संक्रमण

यह आंखों का सबसे आम संक्रमण है, जो मुख्यतः एडेनोवायरस, बैक्टीरिया या एलर्जी के कारण हो सकता है। यह कंजंक्टिवा का एक संक्रमण है। कंजंक्टिवा यानी वह पतली झिल्ली, जो आंख के सफेद हिस्से और पलकों के अंदरूनी भाग को ढकती है। इसमें आंखों में लालिमा, सूजन और चिपचिपा स्राव होता है। बैक्टीरियल इंफेक्शन आमतौर पर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप या दूसरी दवाओं से ठीक हो जाते हैं, जबकि वायरल संक्रमण 7 से 10 दिनों में खुद-ब-खुद ठीक हो जाता है। दर्द की स्थिति में हल्की गर्म सेंक भी फायदा पहुंचाती है। एलर्जी को एंटीहिस्टामिंस दवाओं से काबू करते हैं। भीड़ वाली जगहों पर यह संक्रमण तेजी से फैलता है।

आंखों में बसने लगे रोग

1 एंडोफ्थैल्माइटिस
यह आंख के अंदरूनी ऊतकों में होने वाली गंभीर सूजन है। बैक्टीरिया संक्रमण, सर्जरी (जैसे मोतियाबिंद) या गहरी चोट के बाद ऐसा हो सकता है। इसमें अचानक आंशिक या पूरी तरह से आंखों की रोशनी जा सकती है। आंखों में तेज दर्द होता है और रोशनी के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। इसके लिए एंटीबायोटिक व सूजनरोधी कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं। कुछ मामलों में विट्रेक्टॉमी सर्जरी भी की जाती है। डॉक्टर से तुरंत मिलें।

2 स्टाई
जब पलक की तेल ग्रंथियों या बालों की जड़ में बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, तो पलक के किनारे लाल गांठ बन जाती है। यह मुहांसे जैसी दिखती है, इसमें दर्द, खुजली और इरिटेशन होती है। अक्सर एक सप्ताह में यह संक्रमण ठीक हो जाता है। कुछ-कुछ अंतराल पर गर्म सेंक और एंटीबायोटिक मलहम से भी आराम मिलता है। इसे कभी भी खुद से फोड़ना नहीं चाहिए।

3 केराटाइटिस
यह कॉर्निया (आंख की सामने वाली पारदर्शी परत) का संक्रमण है, जो बैक्टीरिया, वायरस या गंदे कॉन्टैक्ट लेंस या चोट के कारण हो सकता है। इसमें तेज दर्द, सूजन, धुंधलापन, लालिमा और अत्यधिक आंसू जैसे लक्षण दिखते हैं। इसके लिए एंटीबैक्टीरियल, एंटी-फंगल एवं कोर्टिकोस्टेरॉइड आई ड्राप्स देते हैं। गंभीर मामलों में एंटीबायोटिक्स टैबलेट भी दी जाती हैं।

4 यूवेइटिस
आंख की मध्य परत यूविया में होने वाली इस सूजन का कारण फंगल इंफेक्शन है। इसके अलावा ऑटोइम्यून बीमारियां या चोट भी इसका कारण है। इससे अचानक आंखें लाल, दर्द और धुंधली दृष्टि हो सकती है। यह संक्रामक नहीं है, लेकिन इसकी अनदेखी करना रोशनी को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर मुख्य रूप से स्टेरॉएड ड्रॉप्स या ओरल दवाओं का उपयोग करते हैं।

5 कॉर्नियल अल्सर
कॉर्निया पर होने वाला यह घाव एक गंभीर स्थिति है। इसमें कॉर्निया पर एक घाव जैसा छाला हो जाता है। बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या किसी भी चोट के कारण ऐसा हो सकता है। समय पर इलाज न मिलने पर रोशनी जा सकती है।

ध्यान रखें, आंखों के ज्यादातर संक्रमण ठीक किए जा सकते हैं, बशर्ते आप डॉक्टर से मिलने और सही उपचार की अनदेखी न करें।

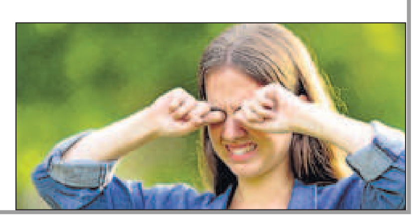

एक्सपर्ट की राय

डॉक्टर से पूछे बिना आंखों में कोई भी दवा न डालें

आंखों में संक्रमण के दौरान सूजन की समस्या आमतौर पर देखी जाती है। यह संकेत है कि आंखें किसी बाहरी संक्रमण से लड़ रही हैं। फंगस के कारण ऑक्युलर हिस्टोप्लास्मोसिस सिंड्रोम यानी कोरियोरेटिनाइटिस होता है। यह आंख की भीतरी पिछली सतह पर स्थित रेटिना की रक्त आपूर्ति पर हमला करता है। इन दिनों 'फोटोकेराटाइटिस' के मामले भी बढ़े हैं। इस इंफेक्शन की पहचान रोशनी के प्रति संवेदनशीलता और आंखों में 'रेत जैसा' महसूस होने से होती है। बैक्टीरियल इंफेक्शन का इलाज एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स से किया जाता है। वहीं वायरल इंफेक्शन में ठंडी पट्टी और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स दिए जाते हैं। खाने की दवाएं भी दी जा सकती हैं। हल्के संक्रमण, कुछ एहतियात के बाद ठीक हो जाते हैं, पर कुछ के लिए डॉक्टर से मिलना जरूरी है। कोई भी दवा बिना सलाह खुद से न डालें।

–**डॉ. इकेदा लाल**, कंसल्टेंट नेत्र विशेषज्ञ, सर गंगाराम हॉस्पिटल एवं मेडिकल निदेशक, दिल्ली आई सेंटर

ड्राई आई से बचाएगा 20-20-20 का नियम

घंटों मोबाइल व कंप्यूटर का इस्तेमाल, एसी की सूखी हवा और प्रदूषण की देन है ड्राई आई समस्या। इसमें आंखों की नमी कम हो जाती है। इस कारण दर्द, जलन के साथ आंखें लाल हो जाती हैं। इससे बचने के लिए हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेकर आंखों की मांसपेशियों को आराम देने के लिए 20 फीट दूर देखें। आंखें समय-समय पर झपकाते रहें। खानपान में विटामिन ए, सी एवं ई व ओमेगा-3 युक्त चीजें खाएं। गाजर एवं नींबू-पुदीना मिक्स पानी का सेवन भी राहत देता है।

सफाई और सावधानी जरूरी

- सार्वजनिक जगहों पर अनावश्यक चीजें छूने से बचें। बार-बार चेहरा व आंखें छूने से बचें। बाहर से घर आने पर साबुन व साफ पानी से हाथ धोएं।
- दूसरों का तौलिया, मेकअप का सामान, कॉन्टैक्ट लेंस, एक्सपायर्ड दवाएं इस्तेमाल न करें।
- बाहर निकलने पर धूप का चश्मा पहनें। इससे आंखों को धूल व प्रदूषण से बचाया जा सकता है।
- स्वीमिंग करते समय सुरक्षा वाले गॉगल्स पहनें।
- कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से पहले उन्हें साफ करें।
- लक्षण दिखने के एक या दो दिन के भीतर डॉक्टर से मिलें। आंखों की दवा डॉक्टर से पूछ कर ही लें।

देखभाल

हाइपरटेंशन की चेतावनी समझिए

बीते दशक में 30 से 40 की उम्र के लोगों में हाईबीपी के मामले 25% तक बढ़ गए हैं। युवाओं का दिल बड़ी उम्र के लोगों की तरह काम कर रहा है और कम उम्र में धमनियां अपना लचीलापन खो रही हैं। इसे 'अर्ली वैस्कुलर एजिंग' भी कहते हैं। रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतें, किस तरह आपके बीपी ग्राफ पर असर डाल सकती हैं, आइए जानें–

क्या है हाइपरटेंशन?

सामान्य रेंज
120/80 एमएम/एचजी

हाइपरटेंशन
140/90 एमएम/एचजी या उससे अधिक।

- **प्रभाव :** हाइपरटेंशन में धमनियों में खून का दबाव लगातार बढ़ा रहता है। दिल, दिमाग व किडनी के अलावा आंखों व याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है।

लक्षण

सिरदर्द (खासकर सुबह), चक्कर आना, थकान, गुस्सा, सीने में जकड़न, बार-बार सिरदर्द, थकावट या चिड़चिड़ापन, नाक से खून आना, मोटापा।

कुछ खास स्थितियां

- **मॉर्निंग सर्ज :** सुबह अचानक बीपी बढ़ जाना। ऐसे में सुबह भारी व्यायाम न करें। पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें।
- **हिडन बीपी :** क्लीनिक में सामान्य, घर/ऑफिस में हाई। घर पर नियमित मॉनिटरिंग करें। बीपी बढ़ने के साथ तनाव, थकान, तेज सिरदर्द, महसूस हो तो अलर्ट हो जाएं।
- **व्हाइट कोट हाई बीपी :** डॉक्टर को देख कर घबराहट में बीपी बढ़ना। ऐसे में तुरंत दवा शुरू न करें, 24 घंटे की मॉनिटरिंग करें।
- **सॉल्ट सेंसिटिव :** थोड़े नमक से भी बीपी बढ़ना। अचार, पापड़, चटनी, जंक व डिब्बाबंद चीजें न खाएं।
- **हार्मोनल हाईबीपी :** थायरॉइड या अन्य हार्मोनल गड़बडी के कारण बीपी बढ़ना। अगर उम्र कम है, तो एंडोक्राइन जांच जरूर कराएं।

बीपी बढ़ाने वाली आदतें

- **नींद की कमी :** 5 घंटे से कम नींद यानी हाइपरटेंशन का 52% ज्यादा खतरा। नींद की कमी से तनावकारी हार्मोन बढ़ता है और सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा एक्टिव रहता है।
- **लगातार बैठे रहना :** 10 घंटे से अधिक बैठे रहकर काम करना यानी 48% जोखिम अधिक। हर घंटे 5 मिनट टहलें, शरीर को स्ट्रेच करें।

- **ज्यादा नमक :** भारतीय रोजाना औसतन 10-12 ग्राम नमक खा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, जरूरत सिर्फ 5 ग्राम की है। हर अतिरिक्त 1 ग्राम नमक आपके सिस्टोलिक बीपी को 1.2 एमएम/एचजी तक तक बढ़ा सकता है।
- **अधिक स्क्रीन टाइम :** मनोरंजन के लिए 4 घंटे से ज्यादा स्क्रीन यानी 25% रक्तचाप का जोखिम अधिक। स्क्रीन टाइम सीमित करें। नींद से समझौता न करें

- **आलस :** व्यायाम की कमी धमनियों का लचीलापन खत्म कर देती है और वजन बढ़ाती है। इसके लिए हफ्ते में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करें। तेज गति से चलें।
- **धूम्रपान/वेपिंग :** निकोटीन नसों को सिकोड़ देता है, जिससे हृदय गति बढ़ जाती है।
- **प्रोसेस्ड फूड :** हफ्ते में 3 बार से अधिक बाहर खाना न खाएं। जंक फूड नसों को असमय बूढ़ा बनाते हैं।

क्या करें : 30 की उम्र के बाद साल में 2 बार बीपी जांच करवाएं। वजन कंट्रोल में रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के पेनकिलर या स्टेरॉयड न लें। अगर दवा शुरू है, तो उसे कभी बीच में न छोड़ें। रोज पैदल चलें, सक्रिय रहें।

ऑफिस के तनाव से निपटने में सीबीटी थेरेपी कारगर

सवाल-जवाब

डॉ. गगनदीप कौर
वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ

■ सवाल : मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता हूं। काम के दबाव के कारण रात में नींद नहीं आती और अक्सर सुबह उठते ही अकारण बेचैनी महसूस करता हूं। मुझे क्या करना चाहिए?

जवाब : कॉर्पोरेट जगत में 'हर समय उपलब्ध रहने' की संस्कृति बन गई है। जब कार्यक्षेत्र में ईमेल या फोन का तत्काल जवाब देने का दबाव होता है, तो मस्तिष्क हमेशा अलर्ट मोड में रहता है। यह मन को थका देता है।

अच्छी मानसिक सेहत के लिए 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। नींद की कमी बेचैनी, चिड़चिड़ापन व उग्रता का कारण बनती है। ऑफिस से घर आने के बाद अपने फोन और लैपटॉप से दूरी बनाएं। यदि आपकी कंपनी की पॉलिसी बहुत सख्त है, तो भविष्य में करियर बदलने पर विचार करें, ताकि सेहत प्रभावित न हो। खाली समय परिवार के साथ बिताएं और अपनी पसंद के काम करें, जैसे संगीत सुनना, खेलना, घूमना आदि। तनाव कम करने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज की मदद लें।

बेहतर नींद के लिए सोने से कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल का उपयोग बंद कर दें। अगले दिन की कार्य-सूची सोने से पहले ही तैयार कर लें, इससे अगले दिन के लिए स्पष्टता आएगी व बेचैनी कम होगी। ऑफिस के बाद भी अगर ऑफिस की राजनीति या अन्य चिंता बनी रहती है, तो नकारात्मक विचार रोकने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी प्रभावी है। यदि तनाव नियंत्रण से बाहर हो रहा है और आप अपने स्तर पर उसे काबू नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेने में संकोच न करें।

■ सवाल : मेरी उम्र 17 वर्ष है। मुझे पढ़ाई में ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है। फोन से दूरी होने पर घबराहट व चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अपनी एकाग्रता वापस पाने के लिए क्या करूं?

जवाब : मोबाइल फोन का अधिक उपयोग एक गंभीर लत की तरह है, जो मस्तिष्क के उन्हीं हिस्सों को प्रभावित करता है, जिन्हें शराब या किसी अन्य नशे की लत सक्रिय करती है। जिस तरह एक व्यसनी को नशा न मिलने पर बेचैनी होती है, ठीक वैसी ही तलब फोन से दूर होने पर महसूस होती है। हम बस केवल एक और रील देखने के लालच में काफी समय बेकार कर देते हैं और पढ़ाई पर एकाग्र नहीं हो पाते। शोध बताते हैं कि मात्र एक बार ध्यान भटकने पर मस्तिष्क को वापस उसी एकाग्रता स्तर पर आने में 23 मिनट का समय लगता है। मोबाइल से मिलने वाला यह कृत्रिम आनंद डोपामाइन रिसेप्टर्स को नुकसान पहुंचाता है। इससे बचने के लिए पढ़ाई के दौरान फोन को दूसरे कमरे में या पूरी तरह साइलेंट रखें। शुरुआती 15-20 मिनट की बेचैनी को धैर्य से पार करना जरूरी है, जिसके बाद दिमाग खुद स्थिर हो जाता है। अपने आनंद के लिए डिजिटल माध्यमों के बजाय दोस्तों से मिलना, एक्सरसाइज, पेंटिंग या संगीत आदि गतिविधियों को चुनें। एक अनुशासित दिनचर्या और पढ़ाई के निश्चित लक्ष्य ही आपको स्वस्थ और एकाग्र रखते हैं।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल **tanmanhindustan@gmail.com** पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं–
तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, 201301

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पिता की सेहत का ध्यान रखें। माता का साथ मिलेगा। वाणी के प्रभाव से रुके हुए काम पूरे होंगे। आय में बढ़ोतरी होगी।

वृष : संतान की सेहत में सुधार होगा। संतान से कोई अच्छी खबर मिलेगी। कारोबार में भी सुधार होगा। कारोबार के लिए यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा से लाभ के अवसर मिलेंगे।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। कारोबार में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन परेशान भी हो सकता है। माता की सेहत का ध्यान रखें। बेकार के क्रोध से बचें। खर्च का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे।

सिंह : किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। अपनी सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। पिता की सेहत में सुधार होगा। कारोबार में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी।

तुला : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार के प्रति सचेत रहें। बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

वृश्चिक : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में कुछ सुधार हो सकता है। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे।

मकर : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से करोबार में वृद्धि हो सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

कुंभ : मन परेशान हो सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। आलस्य की अधिकता भी हो सकती है। बातचीत में संतुलित रहें। परिवार के किसी बुजुर्ग से धन की प्राप्ति हो सकती है।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

15 मई, शुक्रवार, **शक संवत्** : 25 वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 01 ज्येष्ठ मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 27 जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत्** : प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रातः 08.32 बजे तक पश्चात चतुर्दशी सूर्योदय पूर्व 05.12 बजे तक तदनंतर अमावस्या तिथि, चंद्रमा मेष राशि में। **सूर्य उत्तरायण।** प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रातः 08.32 मिनट से सायं 06.52 मिनट तक। वट सावित्री व्रत का द्वितीय संयम। ज्येष्ठ संक्रांति। गंडमूल रात्रि 08.15 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारे जीवन में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव है, कोई उपाय बताएं। –राजीव वर्मा, मेरठ

- आपका घर पूर्व से दक्षिण मुखी है, जो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। आपने घर में ईशान कोण में सीढ़ियां बनवाई हैं और उसी के नीचे टॉयलेट भी बनवा रखा है। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन दोनों को तुरंत ही हटा देना चाहिए।
- आपका सेप्टिक टैंक अग्नि की दिशा में है, इसको यहां से शिफ्ट कर लें। ऊपर के फ्लोर पर आपने आगे पूर्व दिशा का फर्श ऊंचा कर रखा है। इससे धन की अस्थिरता बढ़ती है, इसको एक लेवल करवा लीजिए। मुख्य द्वार पर कॉपर कलर करवा लीजिए और वायव्य कोण में 7 बड़े गोमती चक्र रखें।

वर्ग पहेली : 8329

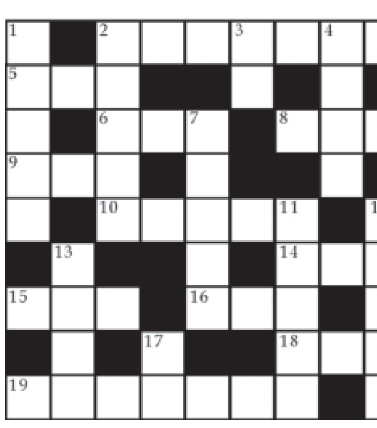

बाएं से दाएं
2. अधिकार करना; कब्जा करना; हक जमाना (4,3)
5. जिसमें जीवन हो; चेतन; जीवित; प्राणी (3)
6. कार्य सिद्धि का उपाय; बीच का; मध्यवर्ती; भाषा; साधन (3)
8. पति का छोटा भाई (3)
9. लाड़; प्यार करना (3)
10. दोषी बनाना; सिर मढ़ना (2,3)
14. उपवन; बगीचा; हरा-भरा स्थान (3)
15. ज्योतिषी; गणना करने वाला; लेखापाल (3)
16. अबोध; अनाड़ी; मूर्ख (3)
18. बिछाने का वस्त्र; बिछावन; आवरण; ओढ़नी; चद्दर (3)
19. शरीर के किसी अंग में लकवे का रोग हो जाना (3,2,2)

ऊपर से नीचे
1. एक बंगाली मिठाई; छैने और गाढ़े दूध से बनी बंगाली मिठाई (5)
2. अनादर; अपमान; मान हानि (5)
3. अनुपयोगी; अवशिष्ट; काठ कबाड़; बेकार कागज (2)
4. मनुष्यत्व; समस्त मानव समाज (4)
7. किसी काम में चित्त लगना; रमना; मनोविनोद होना (2,3)
11. इच्छानुसार काम कराना; तंग करना; हैरान करना (2,3)
12. श्रद्धापूर्वक धन या कोई सामान देना (2,3)
13. अणु संबंधी; अणु का (4)
17. स्त्री; महिला; दुर्गा; गौरी; लक्ष्मी (2

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8328

1 का	2 न	ख	ड़े	3 क	र	4 ना	■	5 सा
■	म	■	■	र	■	रि	■	ध
6 ल	क	द	7 क	■	8 आ	य	त	न
■	दा	■	थि	■	■	ल	■	ही
9 का	न	■	10 त	ड़ि	11 त	■	12 म	न
या	■	13 चु	■	■	र	■	हा	■
14 प	न	प	ना	■	15 से	मा	न	ता
ल	■	चा	■	16 भ्र	■	■	ग	■
ट	■	17 प	रा	म	र्श	क	र	ना

सुडोकू : 8311

*कठिन

5			4	9				
	3		1					4
		6					1	
		5		2				
	1	4				5	7	
				4		9		
	8					7		
7					9		5	
				6	7			2

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8310

9	1	8	6	5	4	3	7	2
6	3	2	9	1	7	8	4	5
5	4	7	3	8	2	1	9	6
4	6	3	8	7	9	2	5	1
1	7	5	2	4	6	9	8	3
8	2	9	1	3	5	7	6	4
3	8	4	5	9	1	6	2	7
2	5	1	7	6	8	4	3	9
7	9	6	4	2	3	5	1	8

देश को भ्रष्टाचार से जो नुकसान पहुंचता है, वह किसी भी नुकसान से अधिक है। - थियोडोर सी. सोरेनसेन

मौसम के रंग

मौसम का आए दिन अपने असामान्य तेवर दिखाना अब बेशक एक सामान्य प्राकृतिक घटना हो गई हो, लेकिन फिलहाल खासकर उत्तर भारत में मौसम जिस तरह से अपने रंग दिखा रहा है, वह चिंतित करने वाला है और इसके पीछे छिपी चेतावनियों को भी समझना जरूरी है। एक ओर उत्तर प्रदेश के करीब तीस जिलों में बुधवार को आए आंधी-तूफान में करीब सौ लोगों की जान चली गई, तो राजस्थान व मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने तेज गर्मी, तो बिहार, झारखंड व उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाएं वर्षों से जो चेतावनी देती रही हैं कि धरती का तापमान बढ़ रहा है और इसका असर मौसम की चरम घटनाओं के रूप में सामने आएगा, वह सही साबित होती दिख रही है। भारत जैसे विशाल और विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश पर इसका असर और भी अधिक पड़ रहा है। एक वैश्विक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण हीटवेव अधिक तेजी से पैदा हो रही हैं। शायद यही वजह है कि बीते अप्रैल महीने के आखिरी कुछ हफ्तों में दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से 90 से अधिक भारत के ही थे। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन से हीटवेव पैदा नहीं होती, लेकिन जब मौसम गर्म होता है, तब इसका असर अधिक घातक हो सकता है। शहरों में बहुमंजिला इमारतें, घनी आबादी और कम हरियाली स्थितियों को और भी खराब कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में बुधवार को आए तूफान के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटों के भीतर पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ऐसी आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति के मद्देनजर आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाए जाने के साथ मौसम संबंधी चेतावनियों को गांव-गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का यह कहना बिल्कुल वाजिब है कि चरम मौसमी घटनाएं शहरों, गांवों और अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली हकीकत है, जिसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी

पर भी पड़ रहा है। ऐसे में, मौसम पूर्वानुमान संबंधी सूचनाओं के प्रसार तंत्र को समावेशी बनाना भी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई केवल सरकारें नहीं जीत सकतीं, इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि फिलहाल जो पर्यावरण की स्थितियां हैं, वे केवल मौसमी असंतुलन का संकेत नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के उस गंभीर संकट की ओर भी इशारा करती हैं, जिसे अब नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

नीट : नई सुनवाई बनाम पुराना फैसला

नीट जैसी बड़ी परीक्षा में छोटे विवाद हमेशा रहेंगे, लेकिन पेपर लीक होकर सोशल मीडिया में नीलाम होना राष्ट्रीय शर्म की बात है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों पर ध्यान दिया जाता, तो इस कलंक से बचा जा सकता था।

नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एनटीए को सोशल मीडिया पर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी या फिर नेशनल ठगी एजेंसी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। दो साल पहले भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई थी।

पुलिस पर भरोसा कमजोर होने के बाद सीबीआई हर बड़े मर्ज की दवा बन रही है। लेकिन पेपर लीक के पुराने मामलों में सीबीआई 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर करने में विफल रही और मुख्य आरोपी को जमानत मिल गई। नकल माफिया को रोकने के लिए संसद से फरवरी 2024 में कानून बना था, जिसमें अधिकतम सजा 10 साल है। संसद से पारित वह कानून 2024 में नीट पेपर लीक कांड के बाद ही आनन-फानन में लागू किया गया था। व्यापम घोटाले से साफ है कि पुलिस और सीबीआई की लंबी जांच के बाद पीड़ित लोगों का भविष्य अंधेरी सुरंग के हवाले हो जाता है।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

जांच और न्यायिक प्रणाली पर डगमगाते भरोसे की वजह से सोशल मीडिया में कानून और प्रक्रिया को दरकिनार करके दोषियों के लिए फांसी की मांग हो रही है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम से नीट के पेपरों का खुलेआम कारोबार होने के बावजूद पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां परीक्षा माफिया को समय पर नहीं रोक पाईं।

नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के बुलंद हौसलों से साफ है कि इस धंधे में जोखिम कम और लाभ ज्यादा हैं। राज्यों के चुनावों में जिस भ्रष्ट सिंडिकेट की बात की जा रही थी, उनसे जुड़े नेताओं को नकल, कोचिंग और सॉल्वर गैंग जैसे माफिया से खुराक मिलती है। परीक्षा में धन-बल के बढ़ते प्रभाव से धांधली के चलते शैक्षणिक अराजकता बढ़ रही है। अयोग्य और धनपशुओं के मेडिकल प्रोफेशन में आने से सामाजिक व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

डॉक्टरी की प्रवेश परीक्षा में लगातार बढ़ रही धांधली, मक्कारी और पेपर लीक से लाखों परिवारों का सपना टूटने के साथ बच्चे मनोरोग और अन्य बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। छात्रों को हुई आर्थिक क्षति, मनोवैज्ञानिक

उत्पीड़न और शैक्षणिक नुकसान की भरपाई करने के बजाय एनटीए ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि नए सिरे से होने वाली परीक्षा के लिए छात्रों को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी।

भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए संस्थागत सुधार जरूरी हैं। एनटीए फिलहाल 15 छोटी-बड़ी परीक्षाएं आयोजित कर रहा है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उनमें से कई विवादों और अनियमितताओं के घेरे में रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गठित डॉ. राधाकृष्णन समिति की सिफारिश के अनुसार एनटीए को जेईई मेन, नीट-यूजी, सीयूईटी–यूजी और यूजीसी नेट जैसी चार बड़ी परीक्षाओं पर फोकस करना चाहिए। समिति के अनुसार, इंजीनियरिंग वाली जेईई की तर्ज पर नीट परीक्षा को पीपीटी (पेन एंड पेपर टेस्टिंग) के बजाय सीबीटी (कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग) से आयोजित करना चाहिए। मानवीय हस्तक्षेप कम होने से पेपर लीक की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। लेकिन एनटीए के पास फिलहाल एक चरण में सिर्फ डेढ़ लाख बच्चों के बैठने के लिए कंप्यूटर क्लासेज हैं और सभी उम्मीदवारों के लिए 15 से ज्यादा चरणों में परीक्षा आयोजित करना होगा।

केंद्र सरकार के कार्मिकी मंत्रालय ने अक्तूबर, 2023 में जारी आदेश में कंप्यूटर सेंटरों की गुणवत्ता के बारे में गाइडलाइन जारी की थी। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी महाशक्ति और इतने बड़े शिक्षा तंत्र वाले देश के 552 शहरों में हम 23 लाख बच्चों के बैठने का इंतजाम नहीं कर सकते, तो फिर नीट परीक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने का कानून क्यों बनाया गया?

केंद्रीय स्तर पर नीट परीक्षा को आयोजित करने का कई राज्यों ने विरोध किया था। अब पेपर लीक कांड के बाद तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने कक्षा 12 के नंबरों के आधार पर मेडिकल में दाखिले की बात दोहराई है। संविधान के अनुसार, मेडिकल शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्यों की आवाज को भी सुनने की जरूरत है। जेईई की तरह नीट परीक्षा को भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले चरण में स्क्रीनिंग और कक्षा 12 के अंकों के आधार पर भीड़ को कम करके सिर्फ गंभीर छात्रों को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। मुख्य परीक्षा में मेरिट वाले छात्रों का चयन होने से नीट की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ मेडिकल प्रोफेशन में अच्छे लोग आएंगे। लेकिन एनटीए के पास परीक्षा आयोजित करने का ही अधिकार है। परीक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून मंत्रालय को साथ मिलकर जरूरी कदम उठाने होंगे।

गवर्नेंस की बदहाली के अधिकांश मामलों में एक पैटर्न नजर आता है। कम पैसे और छोटे प्रयासों से प्रारंभिक स्तर पर समस्या का समाधान नहीं किया जाता। उसके बाद मामला बिगड़ने पर समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार सभी को भारी नुकसान होता है। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सिविल सेवा के उम्मीदवारों के इंटरव्यू लेने के दौरान मैंने देखा कि यदि अध्यक्ष सख्त, कुशल और ईमानदार हों, तो परीक्षा प्रणाली पूरी तरह से बेदाग रह सकती है। नीट जैसी बड़ी परीक्षा में छोटे विवाद हमेशा रहेंगे, लेकिन पेपर लीक होकर सोशल मीडिया में नीलाम होना राष्ट्रीय शर्म की बात है।

एनटीए के पास 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि है। अब लाखों युवाओं की परीक्षा दोबारा आयोजित करने, प्रश्नपत्रों की छपाई, परिवहन, परीक्षा केंद्रों का किराया और लाखों लोगों के मानदेय में सैकड़ों करोड़ रुपये व्यर्थ ही खर्च होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के अनुसार पिछले दो वर्षों में पैसे के बेहतर प्रबंधन से प्रभावी सिस्टम बनता तो पेपर लीक के इस राष्ट्रीय कलंक से बचा जा सकता था।

समिति की सिफारिशों के बावजूद, एनटीए में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के माध्यम से काम जारी रहना शर्मनाक है। 23 लाख युवाओं और उनके परिवारजनों के सपनों को रौंदने वाले माफिया से जुड़े बड़े खिलाड़ियों के यहां सरकारें निष्पक्ष होकर बुलडोजर चलाएं। नई जनहित याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट के दो साल पुराने फैसले पर अमल नहीं करने वाले अधिकारियों को अवमानना की कार्रवाई से कठोर दंड मिले। इससे आक्रोशित युवाओं को थोड़ी राहत मिलने के साथ उनके परिवारजनों और समाज का कानून के शासन पर भरोसा भी बढ़ेगा।

edit@amarujala.com

मुद्दा

महिलाएं हैं, तो समाज है, परिवार है

एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, कुल आत्महत्याओं में गृहिणियों की 13 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के बावजूद यह विषय सार्वजनिक विमर्श में अक्सर अदृश्य बना रहता है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की हालिया रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों की आत्महत्या कुल आत्महत्याओं का 6.2 प्रतिशत थी, जबकि गृहिणियों की खुदकुशी की हिस्सेदारी 13 प्रतिशत रही। इसके बावजूद सार्वजनिक विमर्श में गृहिणियों की आत्महत्या अपेक्षाकृत अदृश्य बनी रहती है। वर्ष 1995 में जब पहली बार आत्महत्या पीड़ितों का व्यवसाय आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, तो सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि देश में हो रही कुल आत्महत्याओं में गृहिणियों की हिस्सेदारी 19.8 प्रतिशत थी, जो उन्हें आत्महत्या पीड़ितों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर रखती थी। तब से लेकर वर्ष 2024 तक कमोबेश यही स्थिति रही है। गृहिणियों की आत्महत्या न तो किसी आंदोलन का आधार बनती है, और न ही किसी वैचारिक ध्रुवीकरण का। संभवतः यही कारण है कि आंकड़ों में लगातार बड़ी हिस्सेदारी होने के बावजूद गृहिणियों की आत्महत्या कभी सार्वजनिक संवेदना और राष्ट्रीय बहस के केंद्र में नहीं आ सकी।

गृहिणियों को परिवार की आधारशिला कहा जाता है, परंतु क्या उन्हें अपने ही घरों में वह महत्व, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है? यह एक गंभीर सामाजिक प्रश्न है। समाज की एक कठोर वास्तविकता यह भी है कि हम जीवन को लाभ-हानि के गणित से ऊपर उठकर देखने की क्षमता लगातार खोते जा रहे हैं। इसी मानसिकता के कारण घरेलू महिलाओं को बार-बार यह महसूस कराया जाता है कि उनका श्रम आर्थिक दृष्टि से कोई 'उत्पादक' योगदान नहीं देता। अनेक महिलाएं भी मानने लगती हैं कि वे परिवार के लिए मूल्यहीन हैं। यही आत्मग्लानि धीरे-धीरे मानसिक अवसाद का रूप ले लेती है, जो उन्हें आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने के लिए भी विवश करती है।

ऋतु सारस्वत

भारतीय महिलाएं प्रतिदिन सात घंटे से अधिक समय अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्यों में व्यतीत करती हैं, जबकि पुरुष तीन घंटे से भी कम समय इन कामों के लिए देते हैं। यानी महिलाएं पुरुषों की तुलना में लगभग 2.6 गुना अधिक घरेलू श्रम करती हैं। यदि गृहिणियों द्वारा किए जा रहे घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य बाहरी लोगों से कराए जाएं, तो उसके लिए बड़ी आर्थिक लागत वहन करनी पड़ेगी। फिर भी गृहिणियों के श्रम को अक्सर खारिज कर दिया जाता है। अक्सर गृहिणियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूछा जाता है कि 'वे करती क्या हैं?' वर्ष 1975 में आइसलैंड की महिलाओं ने वर्षों से पूछे जा रहे इस प्रश्न के प्रतिकार में एक दिन के लिए घरेलू कार्यों का बहिष्कार कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि बैंक, विद्यालय, नर्सरी और अनेक संस्थान तक प्रभावित हो गए। बड़ी संख्या में पुरुषों को बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें अपने कार्यस्थलों तक ले जाना पड़ा। उस एक दिन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जिन कार्यों को सामान्य और अदृश्य मान लिया गया है, वही परिवार और समाज की सबसे मूलभूत शक्ति हैं।

आइसलैंड की वह घटना वस्तुतः एक चेतावनी थी, जिसे आज तक हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। हम आज भी यह नहीं समझ पाए हैं कि जिन महिलाओं के श्रम पर परिवार और समाज की संरचना टिकी होती है, उन्हें उपेक्षा, तिरस्कार और शारीरिक प्रताड़ना तक का सामना करना पड़ता है। संभवतः यही कारण है कि भारत में अनेक गृहिणियां अपने जीवन को समाप्त करने के लिए विवश हो रही हैं।

बुजुर्ग घर की नींव होते हैं

बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि वे घर की जड़ें होते हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ें उसे मजबूती देती हैं, उसी प्रकार बुजुर्ग परिवार को स्थिरता, प्रेम और दिशा प्रदान करते हैं।

जीवन केवल बड़ी खुशियों के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि उन छोटे-छोटे सुखों को महसूस करने का भी नाम है, जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद रहते हैं। हमारे जीवन में बुजुर्गों का महत्व भी बहुत गहरा और अनमोल होता है, लेकिन अक्सर आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अपने माता-पिता और दादा-दादी के महत्व को भूलने लगते हैं, जबकि वही हमारे अनुभव, संस्कार और भावनात्मक शक्ति के सबसे बड़े स्रोत होते हैं।

पर्ल एस बक

बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं होते, बल्कि वे घर की जड़ें होते हैं। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ें उसे मजबूती देती हैं, उसी प्रकार बुजुर्ग परिवार को स्थिरता, प्रेम और दिशा प्रदान करते हैं। उनके पास जीवन का अनुभव होता है, जो किसी पुस्तक या विद्यालय से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने संघर्ष, कठिनाइयां, रिश्तों की अहमियत और समय की कीमत को बहुत करीब से देखा होता है। इसलिए उनकी सलाह जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देती है।

बुजुर्गों का स्नेह, धैर्य और समझ परिवार को जोड़कर रखने का काम करता है। जब एक बच्चा अपने दादा-दादी से कहानियां सुनता है या उनके साथ समय बिताता है, तब वह केवल मनोरंजन नहीं करता, बल्कि संस्कार, इतिहास और मानवीय संवेदनाएं भी सीखता है। समाज की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने कमजोर और वृद्ध लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है।

मुड़-मुड़ के देख

यदि बुजुर्ग अपने ही घर में उपेक्षित महसूस करें, तो यह केवल परिवार की नहीं, बल्कि पूरे समाज की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हमें यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार बचपन में उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर चलना सिखाया, उसी प्रकार वृद्धावस्था में उन्हें हमारे सहारे, सम्मान और प्रेम की आवश्यकता होती है। बुजुर्गों का सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि मानवता का सबसे सुंदर रूप है। उनका आशीर्वाद घर में शांति, प्रेम और सकारात्मकता लाता है। इसलिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

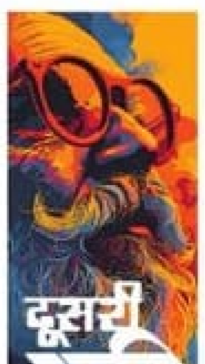

मेरे पति का देहांत हो गया। बच्चे अपने परिवारों के साथ व्यस्त हैं। अकेलेपन को काटने के लिए मैं संगीत के पुराने शौक की ओर लौटना चाहती हूं। क्या इस उम्र में यह ठीक रहेगा?

नई शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती

65 वर्षीय सुधा देवी को संगीत के उनके पुराने शौक पर मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने कुछ यों सलाह दी:

अपने छूटे हुए शौक को पूरा करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। पैंसठ की उम्र में संगीत के अपने पुराने शौक को फिर से जिंदा करना न केवल उचित है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टि से यह आपके लिए एक बेहतरीन निर्णय हो सकता है। नई शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती। खासकर तब, जब जीवनसाथी का साथ छूट गया हो और बच्चे अपनी-अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हों। ऐसे में पीड़ादायी अकेलेपन को दूर करने के लिए संगीत का साथ बहुत ही सकारात्मक कदम है। इससे घर के सूने कोने में पसरी खामोशी की जड़ता टूटेगी। संगीत अकेलेपन से उपजने वाले अवसाद को खत्म करता है, क्योंकि संगीत में मन लगाने से दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन (एंडोर्फिन) रिलीज होते हैं, जो तनाव और उदासी को कम करते हैं।

आपने वर्षों तक घर-गृहस्थी की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। यही वजह है कि आपके बच्चे अपने-अपने जीवन में व्यस्त हैं और आपके ऊपर बोझ नहीं बने हैं। अब यह समय आपके 'स्वयं' से फिर से जुड़ने का है। संगीत से जुड़ाव आपको एक नई पहचान और जीने का मकसद देगा। संगीत का अभ्यास शुरू करने से मानसिक व आध्यात्मिक शांति तो मिलेगी ही, आपकी याददाश्त भी तेज होगी। संगीत भावनाओं की अभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम है, जिससे दुख और अकेलेपन की भावना कम होती है। अब जबकि आपने अपने पुराने शौक यानी संगीत का अभ्यास करने का मन बनाया है, तो इसे आनंददायक गतिविधि के रूप में शुरू करें। चूंकि आपको किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, इसलिए आप जो भी गाएं या बजाएं, उसमें खुशी व आनंद की तलाश करें। इंटरनेट के मौजूदा दौर में संगीत सीखने के लिए आप यूट्यूब पर संगीत ट्यूटोरियल देख सकती हैं। कई वेबसाइट ऑनलाइन संगीत शिक्षा उपलब्ध कराती हैं, आप उनसे भी मदद ले सकती हैं। अगर संभव हो सके, तो आसपास के बुजुर्गों के साथ किसी संगीत मंडली से भी जुड़ सकती हैं। इससे सामाजिक मेल-जोल बढ़ेगा और आपका अकेलापन दूर होगा। यदि आप कोई वाद्ययंत्र बजाना सीखना चाहती हैं, तो गिटार, कीबोर्ड जैसे किसी छोटे वाद्ययंत्र से शुरुआत कर सकती हैं। इसमें आपके बच्चे भी आपका सहयोग कर सकते हैं। इस नई पहल से आपके बच्चों को भी प्रेरणा मिल सकती है। साठ-सत्तर की उम्र में आजकल लोग तंदुरुस्त जीवन जीते हैं और जीवन की हर गतिविधि में उत्साहपूर्वक हिस्सा लेते हैं। अगर आपके मन में कहीं यह आशंका हो कि पति के गुजरने के बाद संगीत सीखने को लोग किस रूप में लेंगे, तो इसे मन से निकाल दीजिए।

चार लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए और आपको जो अच्छा लगता है, वह काम अवश्य कीजिए। उम्र महज एक संख्या है। कई शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि संगीत या कलाएं सीखना मानसिक स्वास्थ्य से बेहद फायदेमंद होता है। आप बिना किसी हिचकिचाहट के इस नई शुरुआत को अपना सकती हैं और अपने शौक को पूरा कर सकती हैं।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं **edit@amarujala.com** पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

82 वर्ष की उम्र और अल्ट्रा मैराथन

जब दुनिया रिटायरमेंट के बाद आराम करने की सोचती है, तब स्पेन के टोलेडो शहर के एक बुजुर्ग ने अपने दौड़ने वाले जूते पहने और इतिहास रच दिया। हुआन लोपेज गार्सिया, जो पहले कार मैकेनिक थे, ने 66 वर्ष की उम्र में दौड़ना शुरू किया। उस समय वह एक मील भी मुश्किल से दौड़ पाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज 82 वर्ष की उम्र में वह 80 से 84 वर्ष आयु वर्ग की 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। जब वैज्ञानिकों ने उनके शरीर की जांच की, तो वे हैरान रह गए। उनकी शारीरिक क्षमता किसी 20 वर्ष के युवा जैसी पाई गई। सामान्यतः यह क्षमता हर दस वर्ष में लगभग 10 प्रतिशत कम हो जाती है, लेकिन उनमें प्रशिक्षण शुरू करने के बाद यह बढ़ गई। हुआन कहते हैं, 'मैंने केवल स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए थोड़ा दौड़ना शुरू किया था। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं यहां तक पहुंचूंगा।' आज भी वह हर सप्ताह लगभग 40 मील दौड़ते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- अंशु लव एंड लाइफ लाइन फाउंडेशन- यह संस्था बुजुर्गों की जरूरतों जैसे चिकित्सा सहायता, पौष्टिक भोजन व वस्त्र उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही संस्था समाजसेवा के कई अन्य कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाती है। संस्था पौधारोपण अभियान चलाती है तथा रक्तदान शिविरों का आयोजन भी करती है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट anshuloveandlifelinefoundation.org.in पर या anshuloveandlifelinefoundation@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।
- *मां गुप्तेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट* - यह बेसहारा बुजुर्गों, बाल कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा गरीबी उन्मूलन के माध्यम से वंचितों का उत्थान करता है। यह ट्रस्ट जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र तथा चिकित्सा सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://maagngo.org.in/index.html पर या Maagngo@gmail.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

न्यूज डायरी

सुनील मित्तल बच्चों को सौंप सकते हैं बागडोर

नई दिल्ली। सुनील भारती मित्तल अगले दशक में भारती एयरटेल लि. की कमान बच्चों को सौंपने की योजना बना रहे हैं। उनकी इच्छा प्रवर्तक कंपनी भारती टेलीकॉम में फिर से 50 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी हासिल करने की भी है। मित्तल का मौजूदा कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होना था, जिसे 30 सितंबर, 2031 तक पांच वर्ष के लिए फिर बढ़ाया गया है। एजेंसी

आकाश अंबानी जियो प्लेटफॉर्म्स के एमडी

नई दिल्ली। जियो प्लेटफॉर्म्स ने आकाश अंबानी को कंपनी का प्रबंध निदेशक (एमडी) नियुक्त किया है। कंपनी ने आईपीओ से पहले यह नियुक्ति की है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने बताया, आकाश अंबानी को 9 अप्रैल, 2026 से प्रभावी पांच वर्ष के लिए एमडी बनाया गया है। वह अक्तूबर, 2014 से जियो प्लेटफॉर्म्स की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड में शामिल हैं। एजेंसी

सोना 650 रुपये महंगा चांदी की कीमत घटी

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में तनाव और रुपये में गिरावट से बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 650 रुपये महंगा होकर 1.66 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पहुंच गया। हालांकि, चांदी 900 रुपये सस्ती होकर 2,96,600 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई। वैश्विक बाजार में सोना बढ़त के साथ 4,704.30 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। एजेंसी

इस्पात उत्पादन 11% बढ़कर 1.53 करोड़ टन

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर सुस्ती के बावजूद भारत का इस्पात क्षेत्र लगातार मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। सेंट्रम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 में भारत का कच्चा इस्पात उत्पादन सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़कर 1.53 करोड़ टन पहुंच गया। इसके उलट, चीन सहित कई बड़े उत्पादक देशों में गिरावट जारी रही। मार्च में वैश्विक उत्पादन 4 फीसदी घट गया। एजेंसी

पश्चिम एशिया संकट के कारण अप्रैल में अप्रत्याशित रूप से बढ़ी थोक महंगाई

ईंधन की कीमतों में तेज उछाल ने बढ़ाई मुश्किल, बड़े झटकों के लिए रहें तैयार

बोनस डेस्क/ब्यूरो

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में तेज उछाल ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका दिया है। लगातार कमजोर होते रुपये के बीच अब थोक महंगाई भी अप्रैल में बढ़कर 42 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। महंगाई को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाने में ईंधन-बिजली, पेट्रोलियम और रसोई गैस की ऊंची कीमतों की बड़ी भूमिका रही।

वाणिज्य मंत्रालय के बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में ईंधन एवं बिजली की महंगाई दर बढ़कर 24.71 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई, जो 42 माह में सबसे ज्यादा है। कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई भी बढ़कर साढ़े चार साल के उच्चतम स्तर 88.06 फीसदी पर पहुंच गई। इससे पहले कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई सबसे ज्यादा अक्तूबर, 2021 में रही थी।

आंकड़ों के मुताबिक, बिजली-ईंधन श्रेणी में एलपीजी की महंगाई भी एक महीने में तेजी से बढ़कर अप्रैल में 10.92 फीसदी पहुंच गई। मार्च में यह शून्य से 1.54 फीसदी नीचे रही थी। पेट्रोल की महंगाई दर 32.40 फीसदी पहुंच गई, जो मार्च 2.50 फीसदी थी। डीजल की महंगाई 3.26 फीसदी से बढ़कर 25.19 फीसदी रही। कच्चे तेल की कीमतों में 50 फीसदी वृद्धि के बावजूद सरकार ने अब तक पेट्रोल और घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखा है, ताकि उपभोक्ताओं को कीमतों वृद्धि के असर से बचाया जा सके। हालांकि, पेट्रोलियम कंपनियों के बढ़ते घाटे को देखते हुए सरकार के लिए पेट्रोल-डीजल की कीमतों को अधिक समय तक स्थिर रखा पाना संभव नहीं है। ऐसे में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी और अल-नीनो के प्रतिकूल प्रभाव के बीच अर्थव्यवस्था के सामने अब महंगाई को काबू करना सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है।

आलू-प्याज समेत सब्जियों की महंगाई घटी

सब्जियों की मुद्रास्फीति दर घटकर 0.53 फीसदी रह गई, जो मार्च में 1.45 फीसदी रही थी। प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर 26.45 फीसदी की गिरावट रही। आलू की मुद्रास्फीति भी घटकर शून्य से 30.04 फीसदी नीचे आ गई। दालों की महंगाई शून्य से 4.03 फीसदी नीचे रही।

■ **फल, अंडे, मांस एवं मछली की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई। दूध की महंगाई दर 2.56 फीसदी और गेहूं की 0.38 फीसदी रही।**

■ **गैर-खाद्य पदार्थों में** मुद्रास्फीति मार्च के 11.5 फीसदी से बढ़कर 12.18 पहुंच गई। विनिर्मित उत्पादों में महंगाई 4.62 फीसदी रही, जबकि मार्च में यह 3.39 फीसदी थी। रसायनों की महंगाई दर मार्च के 2.19 फीसदी से बढ़कर 5.09 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई।

अनुमान और हकीकत

आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए औसतन 4.6 फीसदी महंगाई का अनुमान लगाया है, लेकिन हालिया आंकड़ों ने इस गणित को उलझा दिया है। वर्तमान में थोक महंगाई 8.3 फीसदी है, जबकि खुदरा महंगाई का अनुमान 4.6 फीसदी है। जब थोक कीमतों में इतना बड़ा उछाल आता है, तो कंपनियों के लिए लागत बढ़ जाती है। देर-सबेर वे इसका बोझ ग्राहकों पर डालती हैं, जिससे खुदरा महंगाई आरबीआई के 4.6 फीसदी के अनुमान को जल्द पार कर सकती है।

■ **आरबीआई के लिए अब अग्निपरीक्षा :** रेपो रेट अभी 5.25 फीसदी है। यदि महंगाई तीसरी तिमाही में अनुमान के मुताबिक 5.2 फीसदी या उससे ऊपर जाती है, तो आरबीआई के पास ब्याज दरें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। यानी आपके होम लोन और पर्सनल लोन की किस्तें बढ़ेंगी।

सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, पूंजी 4.52 लाख करोड़ बढ़ी

नई दिल्ली। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच घरेलू शेयर बाजारों में बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। दूरसंचार और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से सेंसेक्स 789.74 अंक की बढ़त के साथ 75,398.72 पर बंद हुआ। एक समय यह 1,000 अंक से अधिक चढ़कर 75,681.88 के स्तर तक पहुंच गया था। निफ्टी 277 अंक की बढ़ोतरी के साथ 23,689.60 पर बंद हुआ।

सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 4.52 लाख करोड़ बढ़ गई। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर बढ़त में रहे। भारती एयरटेल सर्वाधिक 5.32 फीसदी लाभ में बंद हुआ। दूरसंचार इंडेक्स सबसे ज्यादा 2.87 फीसदी बढ़त में रहा। ब्यूरो

रुपये ने फिर छुआ रिकॉर्ड निचला स्तर

मुंबई। डॉलर के मुकाबले रुपया बृहस्पतिवार को दो पैसे की बढ़त के साथ 95.64 पर बंद हुआ। दिन में यह 95.96 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था। मजबूत डॉलर और ऊंची ऊर्जा कीमतों के कारण बढ़ती महंगाई की चिंता के बीच रुपये में गिरावट आई।

रुपया इस वर्ष एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है। इस साल अब तक यह छह फीसदी से अधिक टूट चुका है। मिरै एसेट शेयरखान के अनुज चौधरी ने कहा, रुपये का हाजिर भाव 95.50 से 96.10 के दायरे में रह सकता है। एजेंसी

एक्सप्लेनर

बढ़ता चालू खाता घाटा क्यों है खतरा?

क्या रुपया डॉलर के मुकाबले 100 तक पहुंच सकता है?

■ **सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद क्या अब सरकार को कोटा भी तय करना होगा?** ■ **पेट्रोल-डीजल के केवल दाम बढ़ेंगे या इसकी राशनिंग भी होगी?**

इन सभी सवालों के जवाब छिपे हैं सिर्फ एक आंकड़े में और यह है...भारत का चालू खाता घाटा यानी कैड।

690 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार पर बैठा आरबीआई रुपये को गिरने से नहीं रोक पा रहा है। कई वर्षों बाद भारत में भुगतान संतुलन दबाव में है। खुद मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं।

मॉर्गन स्टेनली ने चालू खाता घाटा को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। उसका कहना है, अगर ब्रेंट क्रूड पूरे एक तिमाही के लिए 150 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर रहता है, तो कैड बढ़कर जीडीपी का करीब 3% पहुंच जाएगा, जो अक्तूबर-दिसंबर 2025 तिमाही में 1.3 फीसदी था।

तेल और कैड का क्या है कनेक्शन?

भारत 88% कच्चा तेल आयात करता है। तेल जब भी महंगा होता है, तो भारत को डॉलर में अधिक भुगतान करना पड़ता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2025-26 में कच्चे तेल का आयात 123 अरब डॉलर से अधिक रहा। अगर तेल की कीमतें ऊंची बनी रहीं, तो आयात बिल इस वर्ष 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

यह चिंता का विषय क्यों... आप पर क्या होगा असर?

■ कैड जब बढ़ता है, तो अर्थव्यवस्था पर एक चेन रिएक्शन होता है। डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे रुपया कमजोर होता है।

■ रुपया जब कमजोर होता है, तो आयातित सामान महंगे हो जाते हैं।

■ विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव अर्थव्यवस्था की बाहरी झटकों को झेलने की क्षमता कम करता है और आयातित महंगाई बढ़ती है।

विदेशी लेनदेन का लेखा-जोखा होता है कैड

■ यह देश के विदेशी लेनदेन का लेखा-जोखा है। कोई देश जब विदेश से सामान और सेवाएं खरीदने (आयात) पर उतना खर्च करता है, जितना वह बेचकर (निर्यात) कमा नहीं पाता, तो इस अंतर को चालू खाता घाटा कहते हैं।

इसमें क्या-क्या शामिल?

■ कच्चा तेल, सोना, मोबाइल का आयात और आईटी सेवाओं का निर्यात।

■ विदेश में निवेश से प्राप्त होने वाला ब्याज या लाभांश।

■ विदेश में रहने वाले भारतीयों की ओर से घर भेजा गया पैसा।

कितना कैड सुरक्षित है?

आमतौर पर माना जाता है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए जीडीपी का 2 फीसदी तक कैड संभलने लायक है। अगर यह 3 फीसदी या उससे ऊपर जाता है, तो विदेशी निवेशकों में डर पैदा होगा और देश की आर्थिक रेटिंग पर खतरा और बढ़ेगा।

यात्री वाहनों की थोक बिक्री 25 फीसदी बढ़ी, इलेक्ट्रिक दोपहिया में 58% उछाल

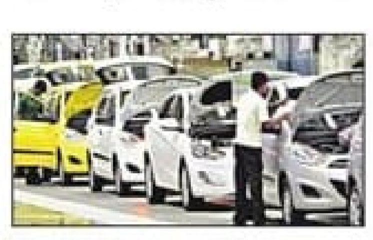

नई दिल्ली। घरेलू वाहन उद्योग ने नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की है। सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल, 2026 में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 25.4 फीसदी 4,37,312 इकाई पर पहुंच गई। पिछले साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 3,48,847 इकाई था।

जीएसटी दरों में कटौती के बाद मांग बढ़ने और यूटिलिटी गाड़ियों के प्रति बढ़ते आकर्षण ने बाजार को मजबूत सहारा दिया है। आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 250 वॉट से अधिक पावर वाले ई-दोपहिया वाहनों की बिक्री 1,12,676 इकाई पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 58 फीसदी वृद्धि है।

आंकड़ों के मुताबिक, दोपहिया वाहनों की बिक्री अप्रैल में 28.4 फीसदी बढ़कर 18.72 लाख से ज्यादा पहुंच गई। तिपहिया वाहनों की बिक्री में 32.8 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, युद्ध के कारण कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के बावजूद घरेलू बाजार में मांग मजबूत है। ■ बोनस डेस्क

अब यूरोपीय बाजारों में भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात का रास्ता साफ

नई दिल्ली। भारत अब यूरोपीय संघ के बाजारों में समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात जारी रख सकेगा। यूरोपीय संघ ने संशोधित मसौदा सूची में भारत को शामिल कर लिया है। भारत अभी तक सितंबर, 2026 से मानव उपभोग के लिए पशु मूल के उत्पादों के निर्यात की अनुमति वाले देशों की सूची में नहीं था।

असल में भारत ने यह सुनिश्चित किया कि यूरोपीय संघ को भेजे जा रहे पशु और उनके उत्पाद रोगाणुरोधी औषधीय उत्पादों एवं मानव चिकित्सा के लिए संरक्षित रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग से मुक्त हैं। इसके बाद यूरोपीय संघ ने यह संशोधित मसौदा सूची जारी की। इसमें कहा गया है, संशोधित सूची में सिर्फ उन्हीं देशों को शामिल किया गया है, जिन्होंने खाद्य उत्पादन में उपयोग होने वाले जानवरों पर रोगाणुरोधी उपयोग का यूरोपीय प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू किया है। इन देशों ने यूरोपीय संघ के नियमों के तहत आवश्यक गारंटी और भरोसेमंद आश्वासन भी प्रदान किए हैं।

यूरोपीय संघ भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात के लिए प्रमुख गंतव्यों में से एक है। 2025-26 में यह भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जिसमें कुल निर्यात मूल्य 1.593 अरब डॉलर दर्ज किया गया। इसमें यूरोपीय संघ का हिस्सा 18.94 फीसदी रहा। ब्यूरो

अमर उजाला Job Alert

Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

कोल इंडिया लिमिटेड

मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर निकली भर्ती

276 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 07 जून, 2026
पात्रताएं : इंजीनियरिंग व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : coalindia.in

आईक्लास में मौके ■ 158 पद

सुरक्षा जांचकर्ता के पदों पर करें आवेदन
आवेदन की अंतिम तिथि : 08 जून, 2026
पात्रताएं : ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : aaiclas.aero

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ■ 122 पद

अधिनायक अनुदेशक के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 01 जून, 2026
पात्रताएं : बारहवीं व अन्य निर्धारित योग्यताएं
यहां आवेदन करें : bpssc.bihar.gov.in

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ■ 100 पद

स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 02 जून, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 23 वर्ष व अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : sbi.bank.in

बिहार लोक सेवा आयोग ■ 44 पद

शुगर केन ऑफिसर के पदों पर मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष व अधिकतम 42 वर्ष
यहां आवेदन करें : bpsc.bihar.gov.in

एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया ■ 34 पद

कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट आदि पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 मई, 2026
योग्यताएं : ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : edcilindia.co.in

यहां भी हैं रोजगार के अवसर...

पर्यावरण विज्ञान संभाग, नई दिल्ली : प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट व यंग प्रोफेशनल के पद खाली।
■ आवेदन करने की अंतिम तिथि : 25 मई, 2026
■ iari.res.in

कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नई : सलाहकार के पदों पर आवेदन आमंत्रित।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 23 मई, 2026
■ kamarajarport.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

इस दुनिया में आजाद वही है, जो खुद पर नियंत्रण रखता है।

एग्जाम टिप्स : यूपीएसएसएससी लेखपाल परीक्षा-2026

छह दिन बाकी, कमजोर विषयों को रोज दोहराएं

दुर्गेश पांडेय
एग्जाम एक्सपर्ट

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती परीक्षा 21 मई, 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत लगभग 7,994 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। परीक्षा में अब केवल छह दिन शेष हैं। ऐसे में घबराने के बजाय सही रणनीति अपनाना सबसे अधिक जरूरी है। अंतिम दिनों की तैयारी ही सफलता और असफलता के बीच बड़ा अंतर तय करती है। अभ्यर्थियों को इस समय नई चीजें पढ़ने के बजाय पहले से तैयार किए गए विषयों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से रिवीजन करें, महत्वपूर्ण टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स दोहराएं तथा पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और मॉक टेस्ट का अभ्यास करें।

■ **गलतियों का विश्लेषण करें**

सबसे पहले अभ्यर्थी पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन करें। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम समाज एवं विकास जैसे विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को दोहराना बेहद जरूरी है। रोजाना कम से कम एक मॉक टेस्ट का अभ्यास जरूर करें। इससे समय-प्रबंधन बेहतर होगा और परीक्षा का वास्तविक अनुभव भी मिलेगा। मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण करना न भूलें, क्योंकि सुधार का यही सबसे अच्छा तरीका है।

■ **यूपी से जुड़े तथ्यों पर विशेष ध्यान दें**

गणित और रीजनिंग के सूत्र तथा ट्रिक्स की छोटी नोटबुक तैयार रखें। अंतिम दिनों में इन्हीं शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करने में आसानी होगी। उदाहरण के लिए प्रतिशत, लाभ-हानि, समय और कार्य जैसे अध्यायों के महत्वपूर्ण सूत्र बार-बार देखें। सामान्य ज्ञान के लिए पिछले एक वर्ष की प्रमुख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं, सरकारी योजनाओं, खेल, पुरस्कार और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों पर विशेष ध्यान दें। ग्राम समाज एवं विकास विषय में पंचायती राज, ग्रामीण विकास योजनाएं और कृषि आधारित प्रश्नों की अच्छी तैयारी करें।

■ **सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें**

अभ्यर्थियों को अपनी दिनचर्या भी संतुलित रखनी चाहिए। देर रात तक पढ़ाई करने के बजाय पर्याप्त नींद लें, क्योंकि मानसिक एकाग्रता परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होती है। खानपान हल्का और संतुलित रखें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। सोशल मीडिया और अनावश्यक मोबाइल उपयोग से दूरी बनाए रखें।

■ **अनुशासन है जरूरी**

परीक्षा से एक दिन पहले कोई नया विषय बिल्कुल न पढ़ें। केवल महत्वपूर्ण नोट्स, फॉर्मूले और पहले से तैयार किए गए टॉपिक्स का हल्का रिवीजन करें। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने के लिए पहले से योजना बना लें। साथ ही एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज एक दिन पहले ही तैयार करके रख लें, ताकि अंतिम समय में किसी प्रकार की परेशानी न हो। अभ्यर्थी सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा दें।

- *पूरे सिलेबस का तेजी से रिवीजन करें।*
- *नई चीजें पढ़ने के बजाय पुराने टॉपिक्स मजबूत करें।*
- *रोज कम से कम एक मॉक टेस्ट दें।*
- *गणित और रीजनिंग के फॉर्मूले बार-बार दोहराएं।*
- *शॉर्ट नोट्स और महत्वपूर्ण ट्रिक्स तैयार रखें।*

आवेदन आमंत्रित

एएमएस फोटो प्रतियोगिता

- **आयु-सीमा :** 13 वर्ष या उससे अधिक
- **मानदंड :** प्रति व्यक्ति अधिकतम एक फोटो और प्रत्येक सबमिशन पांच एमबी से कम होना चाहिए।
- **पुरस्कार :** प्रथम स्थान : 500 डॉलर, दूसरा स्थान : 300 डॉलर, तीसरा स्थान : 200 डॉलर और सदस्य की पसंद : 500 डॉलर।
- **आवेदन की अंतिम तिथि :** 30 जून, 2026
- **आधिकारिक लिंक :** tinyurl.com/y79dk669

फेलोशिप प्रोग्राम

वांग गुंगवू फेलोशिप

- **संस्थान :** यूसुफ इशाक संस्थान
- **पात्रताएं :** आप पोस्ट-डॉक्टोरल शोधकर्ता या मध्य-कॅरिअर नीति निर्माता हों।
- **अवधि :** दो से तीन माह
- **आवेदन की अंतिम तिथि :** 04 अगस्त, 2026
- **आधिकारिक लिंक :** tinyurl.com/37z7dyz7

एग्जाम अलर्ट

आईआईटी जेईई एडवांस्ड परीक्षा-2026

- **परीक्षा की तिथि :** 17 मई, 2026
- यह परीक्षा दो पेपर के लिए आयोजित की जाएगी। पेपर-I व पेपर-II में तीन अलग-अलग खंड (भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित) होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** tinyurl.com/4wt4crtw

जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (बैकलॉग)

- **परीक्षा की तिथि :** 17 मई, 2026
- यह परीक्षा दो पेपर (सामान्य ज्ञान पेपर-I व सामान्य ज्ञान पेपर-II) के लिए आयोजित की जाएगी। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। प्रत्येक पेपर की अवधि दो-दो घंटे निर्धारित की गई है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** jpsc.gov.in

सामान्य ज्ञान

साइकी स्पेसक्राफ्ट

■ **क्या है :** नासा का साइकी अंतरिक्ष यान एक ऐतिहासिक मिशन है, जिसे 13 अक्तूबर, 2023 को मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक दुर्लभ धातु-समृद्ध क्षुद्रग्रह '16 साइकी' का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था।

■ **चर्चा में क्यों :** हाल ही में, साइकी अंतरिक्ष यान ने करीब 50 लाख किलोमीटर की दूरी से मंगल ग्रह की एक बेहद खूबसूरत अर्धचंद्राकार तस्वीर ली है।

मर्कोसुर

■ **क्या है :** दक्षिणी साझा बाजार (स्पेनिश संक्षिप्त नाम मर्कोसुर) दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1991 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना है। इसकी आधिकारिक कार्यकारी भाषाएं स्पेनिश और पुर्तगाली हैं।

■ **चर्चा में क्यों :** हाल ही में, भारत और ब्राजील ने भारत और मर्कोसुर के बीच व्यापार समझौते को और बड़ा करने पर सहमति जताई है।

आज का दिन

भारतीय मूल की मंजुला सूद ब्रिटेन की पहली एशियाई महिला मेयर बनीं थी। उनकी यह सफलता महिलाओं के लिए प्रेरणा और गर्व का प्रतीक है।

■ 1907 : भारतीय क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म हुआ था।
■ 1928 : पहली मिकी माउस फिल्म 'प्लेन क्रेजी' की टेस्ट स्क्रीनिंग की गई थी।
■ 1940 : मैकडॉनल्ड्स का पहला फास्ट फूड रेस्त्रां खुला था।
■ 1993 : भारत के प्रथम आर्मी कमांडर इन चीफ के.एम. करिअप्पा का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी/चतुर्दशी।
कल : वट् सावित्री व्रत, शनि जयंती शिंगनापुर ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 09.00 से 10.30 तक।

■ सूर्योदय : 05.34
■ सूर्यास्त : 19.01
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 26 वैशाख मास शक 1948, ज्येष्ठ मास 02 प्रविष्टे, 28 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ अमावस्या 25.30 तक उपरांत प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, भरणी नक्षत्र 17.29 तक उपरांत कृतिका नक्षत्र, सौभाग्य योग 10.25 तक उपरांत शोभन योग, चतुष्पाद करण 15.20 तक उपरांत नाग करण, चंद्रमा वृष राशि में 22.44 बजे।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : मानसिक उत्तेजना से बचें। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। अचानक अर्थ प्राप्ति संभव है।

वृष : मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। व्यय की अधिकता रहेगी।

मिथुन : लोकप्रियता बनी रहेगी। मित्र सहायक रहेंगे। चल-अचल संपत्ति बढ़ सकती है। विरोधी परास्त होंगे।

कर्क : राजकाज में सफलता मिलेगी। नौकरी में उन्नति के संकेत मिलेंगे। अटका धन मिल सकता है।

सिंह : भाग्य सहायक रहेगा। सरकारी क्षेत्र में अटका कार्य बनेगा। नौकरी में सम्मान बढ़ेगा। धर्म कर्म में आस्था रहेगी।

कन्या : मानसिक उथल-पुथल बनी रहेगी। स्वजनों से मतभेद रहेंगे। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें।

तुला : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में नए प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति यथावत रहेगी।

वृश्चिक : नौकरी में कार्यभार बढ़ सकता है। विरोधी पक्ष से सावधानी बरतें। व्यक्तिगत संबंध सहायक रहेंगे।

धनु : दिनमान अनुकूल रहेगा। नौकरी में कार्य कुशलता का लाभ मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी।

मकर : स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी आ सकती है। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा।

कुंभ : दिनमान अनुकूल रहेगा। नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। भू-संपत्ति से अर्थ प्राप्ति संभव है।

मीन : भाग्य सहायक रहेगा। अटका कार्य बन सकता है। नौकरी में सम्मान बना रहेगा।

सुडोकू

	1			5			3	8
7						2		
5			3			9		
6			9		3	1		
3								9
		9	1		2			4
		5			4			7
		8						3
1	3			8			4	

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

9	1	6	2	5	7	4	3	8
7	8	3	4	9	6	2	5	1
5	2	4	3	1	8	9	7	6
6	7	2	9	4	3	1	8	5
3	4	1	8	6	5	7	2	9
8	5	9	1	7	2	3	6	4
2	9	5	6	3	4	8	1	7
4	6	8	7	2	1	5	9	3
1	3	7	5	8	9	6	4	2

संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 15 मई, 2026 : ज्येष्ठ कृष्ण - 13 वि. 2083

भावनाओं के संतुलन से ही जीवन में स्थिरता संभव है

समय रहते चेतें

इस तथ्य पर हैरानी नहीं कि पेट्रोलियम पदार्थों के स्रोत कच्चे तेल के साथ-साथ खाद्य तेलों के आयात में भी अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा की खपत हो रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने खाद्य तेलों के सेवन में कमी लाने की भी अपील की। उनका यह कहना सही है कि इससे सेहत सुधारने के साथ विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहायता मिलेगी, लेकिन प्रश्न यह है कि भारत अपनी जरूरत भर का तिलहन क्यों नहीं पैदा कर पा रहा है? यह सामान्य बात नहीं कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 58 प्रतिशत खाद्य तेल आयात करता है। पिछले वर्ष खाद्य तेल आयात बिल करीब 20 अरब डालर का था। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि कृषि प्रधान देश होने और आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी पर बल देने के बाद भी देश में तिलहन फसलों का उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है, जितना अपेक्षित है। यह ठीक है कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके चलते उनके उत्पादन में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिली है, लेकिन इसी के साथ खाद्य तेल की मांग और खपत भी बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं, उनके खानपान में तेलों की खपत बढ़ रही है। स्पष्ट है कि केंद्र और राज्य सरकारों को तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर देना होगा। अपने देश की समस्या यह है कि जब संकट सामने आ खड़ा होता है, तब उससे बचने के उपायों पर ध्यान दिया जाता है। खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर होने का सघन अभियान तो बहुत पहले चलाया जाना चाहिए था और उसकी लगातार समीक्षा भी की जानी चाहिए थी।

बात केवल खाद्य तेलों की ही नहीं है, भारत को बड़ी मात्रा में दालों का भी आयात करना पड़ता है। इसमें भी विदेशी मुद्रा की खपत होती है। कहना कठिन है कि दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चलाई गईं, उनके कितने सकारात्मक परिणाम सामने आए? जो भी हो, यह सही समय है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य आयातित वस्तुओं में कमी लाने के ठोस एवं दीर्घकालिक उपाय करे। यह सही है कि भारत में कच्चे तेल के अपेक्षित भंडार नहीं, इसलिए उसका आयात करना ही होगा, लेकिन आखिर हर तरह के ईवी वाहनों की खरीद बढ़ाने के लिए कोई आकर्षक प्रोत्साहन योजना क्यों नहीं लाई जा पा रही है और उनके लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार द्रुत गति से क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी तरह क्या कारण है कि किसी का ध्यान इस ओर क्यों नहीं जा रहा है कि छोटे-बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम के कारण बड़े पैमाने पर पेट्रोल एवं डीजल की जो बर्बादी होती है, उसे कैसे रोका जाए?

पैनी नजर की दरकार

दिल्ली में लाल किले के सामने विगत नवंबर में हुए आतंकी हमले के गुनाहगारों को सजा दिलाने की दिशा में जांच एजेंसी एनआइए आगे बढ़ रही है, जो स्वागत योग्य है। बृहस्पतिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में एनआइए द्वारा दाखिल 7500 पन्नों के आरोप पत्र में यह बात सामने आई है कि लाल किला धमाके की साजिश अल कायदा के भारतीय माड्यूल की शाखा 'अंसार गजवत उल हिंद' ने रची थी और इसके आतंकियों का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकना और यहां शरिया कानून लागू करना था। इनमें से कई आतंकी मेडिकल पेशेवर थे और देश में और भी घातक हमलों की साजिश रच रहे थे।

> दिल्ली पुलिस को एनआइए के साथ मिलकर लगातार काम करना चाहिए, ताकि राजधानी को सुरक्षित बनाने में किसी भी तरह की कमी न होने पाए

यह गनीमत रही कि सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पनप रहे आतंक के गढ़ को ध्वस्त कर कई आतंकियों को धर दबोचा, अन्यथा देश में ये किस तरह आतंक फैलाते, ये आसानी से समझा जा सकता था। आतंक के इस माड्यूल पर सुरक्षा एजेंसियों को पैनी नजर रखनी चाहिए, ताकि कहीं से भी इसके पनपने की जरा सी भी शुरुआत हो तो उसे ध्वस्त किया जा सके। दिल्ली पुलिस को एनआइए के साथ मिलकर काम करना चाहिए, ताकि राजधानी को सुरक्षित बनाने में किसी भी तरह की कमी न हो।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या सोना-चांदी पर आयात शुल्क बढ़ाने से उनकी मांग और उपभोग में कमी देखने को मिलेगी?

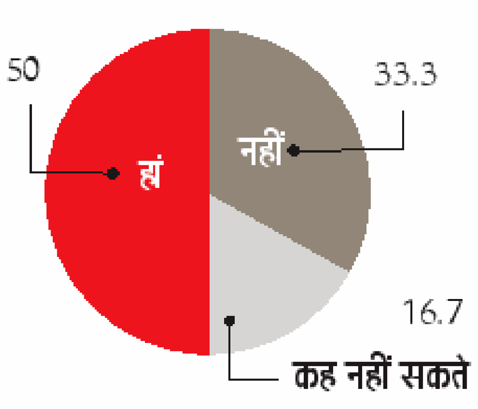

आज का सवाल

क्या कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल की जगह वीडी सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री बनाकर सही फैसला लिया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

कमजोर पड़ती क्षेत्रीयता की राजनीति

विकास सारस्वत

हालिया विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति का कमजोर पड़ना दर्शाता है कि राष्ट्रवादी विचारों का विस्तार हो रहा है

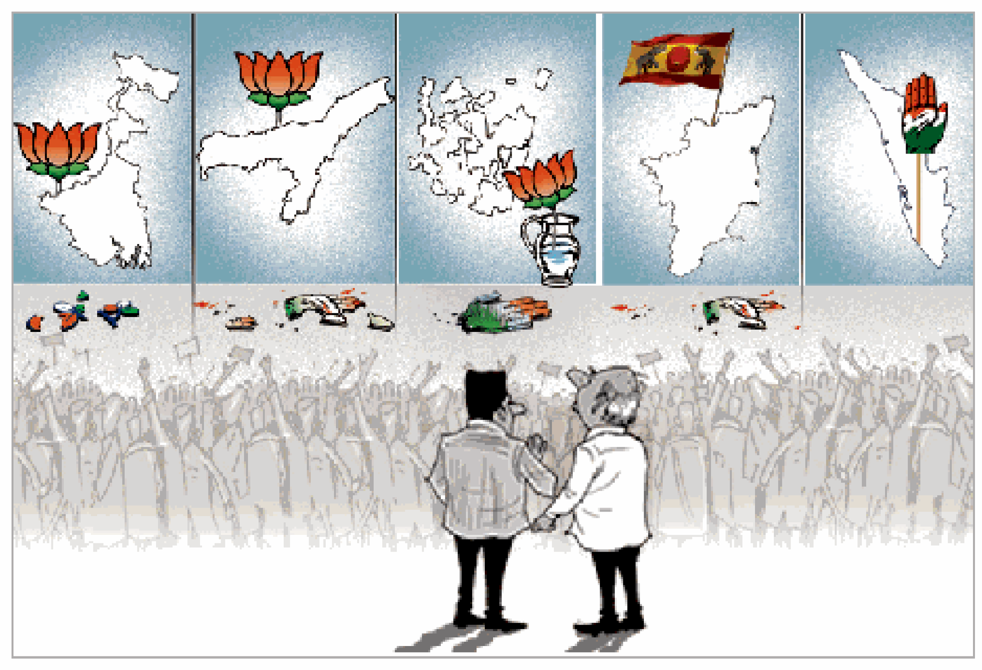

अवधेश राजपूत

चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के बाद असम और बंगाल में प्रचंड बहुमत वाली सरकारों ने कमान संभाल ली है तो पुडुचेरी में चुनाव पूर्व गठबंधन वाली राजग सरकार ने कामकाज शुरू कर दिया है। त्रिशंकु विधानसभा वाले तमिलनाडु में भी विजय सरकार का आगाज हो चुका है। गत दिवस केरलम के मुख्यमंत्री का चयन भी हो गया। चुनाव परिणाम की बात करें तो असम, केरलम और पुडुचेरी में नतीजे आशा के अनुरूप ही रहे। असम में भाजपा के सामने कांग्रेस इस कदर साफ हुई, जैसे ब्रह्मपुत्र के सैलाब में नदी के बीच बालू से बने द्वीप बह जाते हैं। राज्य में कांग्रेस केवल निचले असम की मुस्लिम बहुल सीटों तक ही सिमट कर रह गई है। जबकि उत्तर असम के असमिया बहुल जिलों में उसका सूपड़ा पूरी तरह साफ हो गया, जहां कभी पार्टी का अच्छा प्रभाव होता था। यह परिणाम पूरी तरह अपेक्षित भी था। राज्य में न केवल भाजपा सरकार द्वारा किया गया विकास साफ-साफ दिखाई देता है, बल्कि पार्टी असमिया अस्मिता और जनसांख्यिकीय परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति संवेदनशील भी दिखाई देती है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की निजी लोकप्रियता भी पार्टी के लिए कारगर साबित रही। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की स्थिति पर चुनाव से पहले ही एक असमिया बुद्धिजीवी ने टिप्पणी की थी कि "भंग नौकात निदिबा भोरी" यानी टूटी नौका में आखिर कौन बैठता है?

केरलम के नतीजों में भी आश्चर्य सिर्फ इतना है कि यह परिवर्तन दस वर्ष बाद हुआ है, अन्यथा यहां हर पांच साल बाद मार्क्सवादी नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और कांग्रेस नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे यानी यूडीएफ के बीच ही बारी-बारी से सत्ता बदलती रही है। यहां के नतीजों में महत्वपूर्ण बात यह रही कि यूडीएफ ने कोझीकोड, तिरुअनंतपुरम और कोल्लम जैसे वामपंथ के गढ़ भी ढहा दिए। मुस्लिम लीग के साथ हुए गठजोड़ ने कांग्रेस को विशेषकर उत्तरी केरलम में मदद पहुंचाई। इस गठबंधन से कांग्रेस को करीब छह प्रतिशत मतों का लाभ मिला। हालांकि यह परिणाम भी अनपेक्षित नहीं थे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में यूडीएफ को राज्य में 20 में से 18 सीटें मिली थीं। इसी तरह पुडुचेरी ने भी उसी परिपाटी का पालन किया है, जिसमें केंद्र पर निर्भरता होने के कारण केंद्रशासित प्रदेश के चुनाव का झुकाव स्वाभाविक रूप से उस दल या गठबंधन की तरफ होता है, जिसकी केंद्र में सत्ता होती है।

जो दो नतीजे सर्वाधिक चौंकाने वाले रहे, वे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से आए। तमिलनाडु के नतीजे इस मायने में ऐतिहासिक हैं कि 50 वर्ष बाद द्रमुक और अन्नाद्रमुक के बीच घूम रही सत्ता पर विराम लगा। सत्ताधारी द्रमुक को इन चुनावों में गहरा झटका लगा। बड़ा सवाल यही है कि इसे कितना व्यापक परिवर्तन माना जाए, क्योंकि इन चुनावों के माध्यम से तमिलनाडु की राजनीति में फिर से विजय के रूप में एक सिने स्टार का उदय हुआ। वहीं सर्वाधिक चर्चा में रहे राज्य बंगाल में सत्ता परिवर्तन के मायने शायद सबसे अधिक महत्व रखते हैं। बंगाल में लंबे समय बाद पूरी तरह हिंसा मुक्त चुनाव हुए। चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कड़े कदमों ने भय मुक्त वातावरण का निर्माण किया। इसके चलते हुए रिकार्ड मतदान ने भय और भ्रष्टाचार के सहारे बनाई गई सत्ता को उखाड़ फेंका। स्पष्ट है कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया। बंगाल के नतीजों में एक बड़ी बात यह भी रही कि आम बंगाली मतदाताओं ने कुछ बांग्ला बुद्धिजीवियों द्वारा संस्कृति और क्षेत्रीयता के नाम पर निर्मित श्रेष्ठता और विशिष्टता के भाव से ऊपर उठकर भारतीयता को महत्व दिया।

निजी अनुभव से कहूं तो कभी सीबीआइ तो कभी ईडी और केंद्रीय बलों के ममता विरोध से खिन्न, परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध बंगाली मतदाताओं में एक प्रबल भाव था कि आखिर वे भी मूलतः हैं तो भारतीय ही। स्कूलों के उन्नयन के लिए लाई गई पीएमश्री और आयुष्मान जैसी योजनाओं का विरोध समझ से परे था। खस्ताहाल उद्योग और व्यापार, रोजगार की कमी और महिला सुरक्षा के अभाव ने बंगाली अस्मिता कार्ड नहीं चलने दिया। राजकीय सीमाओं से परे राज्यों के नतीजों के कुछ व्यापक निहितार्थ भी हैं। जैसे कि एक पहलू पार्टी पोषित भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा रहा। तमिलनाडु और बंगाल दोनों ही राज्यों में एक ऐसी राजकीय व्यवस्था देखने को मिली, जहां पार्टी काडर को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ने के संस्थागत प्रयास हुए। बंगाल में नौकरियों के एवज में भ्रष्टाचार के अलावा निजी निर्माण से लेकर बिजली लाइन खिंचवाने के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को कट मनी देनी पड़ती थी। सरकारी योजनाओं में भी यह व्यवस्था इतनी संस्थागत हो चली थी कि गरीब लोगों के अंतिम संस्कार के लिए शुरू की गई समब्याथि योजना के अंतर्गत मिलने वाले 2,000 में से 200 स्थानीय कार्यकर्ताओं को देने की खबरें बहुत आम थीं। तमिलनाडु की बात करें तो मंत्रियों में एन. नेहरू, आइ. पेरियसामी और वीएस बालाजी पर भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज हुए।

दूसरा महत्वपूर्ण निहितार्थ यह कि हिंदू विरोध की राजनीति सिमटती जा रही है। जहां द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन और के. पोन्मुड़ी ने सनातन को मिटाने की बात कही, वहीं ममता बनर्जी ने काफिर जैसे इस्लामपरस्त शब्दों द्वारा मुस्लिम वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। ममता की जय श्रीराम के आह्वान से खीझ कैमरों के सामने भी स्पष्ट दिखी। जनता ने मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोध की राजनीति को सिरे से नकारा है। तीसरा निहितार्थ सीमावर्ती राज्यों असम और बंगाल में घुसपैठ से जुड़ा है। चौथा, देश में सर्वाधिक क्षेत्रीयता का भाव लिए हुए तमिलनाडु और बंगाल में मतदाताओं ने भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता को नकारा है। कुल मिलाकर ये नतीजे दर्शाते हैं कि देश की राजनीति में क्षेत्रीयता की राजनीति कमजोर पड़ रही है और राष्ट्रवादी विचार का विस्तार हो रहा है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

विकास के नए युग में पूर्वोत्तर

लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

पूर्वोत्तर की सामरिक स्थिति, संसाधन और ऊर्जावान जनसंख्या विकास की अपार संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं

बेहतर होते बुनियादी ढांचे से प्रगति को लगे पंख ● फाइल

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि के कारण राष्ट्र की अमूल्य धरोहर रहा है। विविध जनजातीय परंपराएं, मनमोहक प्राकृतिक सौंदर्य, अद्वितीय लोक-संस्कृति और अपार संभावनाओं से परिपूर्ण यह क्षेत्र लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहा। किंतु बीते एक दशक के दौरान पूर्वोत्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। असम सहित समूचा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संपर्क, शांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नए युग में प्रवेश कर चुका है। दशकों तक पूर्वोत्तर क्षेत्र संपर्क, आधारभूत संरचना की कमी तथा देश के अन्य हिस्सों से अलगाव जैसी चुनौतियों से जूझता रहा, किंतु क्षेत्र के सामरिक महत्व और अपार संभावनाओं को पहचानते हुए मोदी सरकार ने इसके विकास के लिए सक्रिय और समग्र दृष्टिकोण अपनाया। इस परिवर्तन के केंद्र में 'एक्ट ईस्ट नीति' रही है, जिसने पूर्वोत्तर को केवल सीमांत क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए भारत के प्रवेश द्वार के रूप में पुनर्परिभाषित किया है।

'एक्ट ईस्ट नीति' ने पड़ोसी देशों के साथ भौतिक और आर्थिक संपर्क को सुदृढ़ करने के साथ-साथ पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी नई मजबूती प्रदान की है। राजमार्गों, रेलमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्गों और हवाई संपर्क जैसी प्रमुख आधारभूत परियोजनाओं में तीव्र गति से प्रगति हुई है। पुलों के निर्माण और सीमा व्यापार अवसंरचना के विकास से लाजिस्टिक्स में सुधार हुआ है तथा क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों तक बेहतर रेल संपर्क और उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विस्तार जैसी पहलों ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर और अधिक निकट ला दिया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के लिए संसाधनों के प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। विभिन्न मंत्रालयों को अपने सकल बजटीय समर्थन का एक निश्चित प्रतिशत पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में प्रमुख योजनाएं दूरदराज के इलाकों तक पहुंची हैं। क्षेत्र में डिजिटल संपर्क को भी व्यापक बढ़ावा मिला है। इससे समावेशन को बढ़ावा मिला है तथा असमानता में कमी आई है। इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण आधार शांति और स्थिरता पर दिया गया विशेष बल रहा है।

सरकार ने विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय संवाद स्थापित कर लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान और उग्रवादी समूहों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया है। ऐतिहासिक शांति समझौतों और निरंतर संवाद ने अधिक सुरक्षित वातावरण तैयार किया है, जिससे निवेश और पर्यटन को प्रोत्साहन मिला है। कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में लक्षित निवेश के माध्यम से आधुनिक तकनीकों, बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप और उद्यमिता को नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग प्रदान कर क्षेत्र के युवाओं की नवाचार क्षमता को नई दिशा दी जा रही है। सरकार ने आधारभूत संरचना सुधार, पर्यटन स्थलों के प्रचार और यात्रा प्रक्रियाओं को सरल बनाकर इस क्षेत्र को देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक और सुलभ बनाया है।

यद्यपि आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास महत्वपूर्ण हैं, किंतु पूर्वोत्तर की वास्तविक शक्ति उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में निहित है। गुवाहाटी में बिहू, झुमुर और बागुरुंबा नृत्य के भव्य आयोजनों द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड स्थापित करना केवल क्षेत्र की जीवंत परंपराओं का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र की संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। इसने पूर्वोत्तर और देश के अन्य हिस्सों के बीच भावनात्मक एकता को और अधिक मजबूत बनाया है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है। जोरहाट में महान आहोम सेनापति वीर लासित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की स्थापना क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास और देशभक्ति की भावना को समर्पित एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। बटद्रवा थान सांस्कृतिक परिसर के विकास तथा महत्वाकांक्षी कामाख्या कारिडोर परियोजना जैसी पहलें असम और पूर्वोत्तर में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को नई गति दे रही हैं। साथ ही चराइदेव के मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त होना असम की ऐतिहासिक विरासत की वैश्विक पहचान है। कौशल विकास कार्यक्रमों, उच्च शिक्षा संस्थानों और खेल अवसंरचना के विस्तार ने युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर प्रदान किए हैं। 'लखपति दीदी', जिसे क्षेत्र में 'लखपति बाइदेउ' के नाम से जाना जाता है, समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर वास्तव में 'अष्ट लक्ष्मी' के रूप में उभरा है। अलगाव से एकीकरण और उपेक्षा से सशक्तीकरण तक की यह यात्रा प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है। यह सिद्ध करती है कि दूरदृष्टि, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास किस प्रकार एक उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं

(लेखक असम के राज्यपाल हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

निंदा से करें परहेज

जिस प्रकार व्यसन इंसान के सोच और जीवन दोनों को प्रभावित करता है, उसी प्रकार निंदा भी मनुष्य के चरित्र को कमजोर बना देती है। धीरे-धीरे यह उसके व्यक्तित्व को भीतर से खोखला करने लगती है। निंदा करने वाला व्यक्ति खुद को चतुर समझता है, लेकिन सुनने वाला व्यक्ति हमेशा उसे संदेह की नजर से देखता है, क्योंकि जो व्यक्ति आज किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, वह कल उसकी भी बुराई कर सकता है। इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। बाहर से भले ही लोग उसकी बातों पर मुस्कुरा दें, लेकिन भीतर ही भीतर उसके प्रति सम्मान कम होने लगता है।

मानव जीवन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। जो शब्द हम भेजते हैं, वही शब्द लौटकर आता है। यदि हम दूसरों के लिए कटुता, ईर्ष्या और नकारात्मकता भेजेंगे, तो वही माहौल हमारे आसपास भी बनेगा। इसके विपरीत यदि हम प्रेम, सम्मान और प्रेरणा की बातें करेंगे, तो समाज में सकारात्मकता बढ़ेगी। शब्द केवल आवाज नहीं होते, वे हमारे संस्कार और सोच का परिचय भी देते हैं। आज के समय में बहुत से लोग दूसरों की गलतियां खोजने में लगे रहते हैं।

किसी की सफलता देखकर उसकी मेहनत की सराहना करने के बजाय लोग उसकी आलोचना करने लगते हैं। यह आदत धीरे-धीरे मनुष्य को भीतर से असंतुष्ट बना देती है। हम दूसरों की बुराई करके खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश में अपना ही स्तर खुद गिरा लेते हैं। वास्तविक महानता दूसरों को नीचे दिखाने में नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। एक समझदार व्यक्ति वही होता है, जो दूसरों की कमियों पर चर्चा करने के बजाय उनके गुणों को देखने का प्रयास करे। निंदा से रिश्ते टूटते हैं, विश्वास समाप्त होता है और मन में कड़वाहट पैदा होती है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। मधुर वाणी, अच्छे विचार और सम्मानपूर्ण व्यवहार ही मनुष्य को सच्चा सम्मान दिलाते हैं।

समराज चौहान

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

जिम्मेदार शासन आवश्यक

'पहले सरकारी तंत्र बरते किफायत' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में राजीव शुक्ला ने सरकारी फिजूलखर्ची और मुफ्त योजनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वास्तव में समस्या केवल योजनाओं की नहीं, बल्कि उस मानसिकता की है जिसमें शासन विकास से अधिक दिखावे पर केंद्रित होता जा रहा है। सरकारी विज्ञापन, भव्य आयोजन, अनावश्यक यात्राएं और स्वागत संस्कृति पर खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। चुनावी राजनीति ने मुफ्त सुविधाओं को एक आसान हथियार बना दिया है। जनता को तात्कालिक राहत तो मिलती है, पर दीर्घकाल में यही योजनाएं सरकारी कर्ज, कर वृद्धि और आर्थिक असंतुलन का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक पक्ष यह है कि योजनाओं की सफलता का आकलन वास्तविक सुधार से नहीं, बल्कि प्रचार और भीड़ से किया जाने लगा है। इससे प्रशासनिक जवाबदेही कमजोर पड़ती है। एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सरकारी सहायता और निर्भरता के बीच की रेखा धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही है। यदि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर देने के बजाय केवल राहत आधारित राजनीति की जाएगी, तो आत्मनिर्भर समाज का निर्माण संभव नहीं होगा। लोकतंत्र में कल्याणकारी योजनाएं आवश्यक हैं, लेकिन उनका उद्देश्य नागरिकों को सक्षम बनाना होना चाहिए, स्थायी आश्रित नहीं। समाधान स्पष्ट है-सरकारी खर्च का सामाजिक आडिट अनिवार्य हो, गैरजरूरी सुविधाओं और प्रचार व्यय पर सीमा तय हो तथा बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा, कृषि, स्थानीय उद्योग और रोजगार सृजन पर लगाया जाए। आर्थिक अनुशासन की शुरुआत सत्ता से होगी, तभी जनता में विश्वास पैदा होगा।

awanishg30@gmail.com

नई पीढ़ी के नेता

कभी नारा लगता था, भारत मां की तीन धरोहर-अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। 2004 के बाद वह त्रिमूर्ति मंद हो गई। जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता से दस साल बाहर रही। उसके बाद नई त्रिमूर्ति का उदय हुआ। मोदी, राजनाथ व शाह। इस पीढ़ी ने पिछले वालों को मीलों पीछे छोड़ दिया। 15 वर्ष के शासन के पश्चात अगले दस वर्षों में कोई नई त्रिमूर्ति खोजी जाती और भाजपा सत्ता से बाहर रहती, इससे पहले अगली पीढ़ी की त्रिमूर्ति खोज ली गई। योगी, हेमंत व सुवेंदु। अटल वाली पीढ़ी श्रीराम वाली पीढ़ी थी, जो सनातन संस्कृति के पोषक थे, मोदी वाली पीढ़ी श्रीकृष्ण वाली पीढ़ी है, जो श्री मद्भागवत गीता के प्रति निष्ठावान हैं, जो जैसे को तैसा पद्धति में विश्वास रखते हैं। योगी वाली पीढ़ी हिंदुत्व के प्रति समर्पित है। कांग्रेस के लिए अब कोई स्थान बचने वाला नहीं है। कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है। जिसमें भारत बोध हो, संस्कृति के प्रति निष्ठा हो। हमें आशा एवं अटूट विश्वास है कि 2035 से 2050 तक यह त्रिमूर्ति भारत के भविष्य की निर्माता बनेगी।

सुधीर गोयल, सेवा भारती पिलखुवा

विपक्ष की निंदनीय राजनीति

पिछले कुछ दिनों में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिससे हर देशभक्त और हिंदू आहत हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र उदयनिधि सटालिन ने विधानसभा में खुलकर बोला कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए। उदयनिधि ने तो पहले इससे भी बहुत बढ़चढ़ कर बोला था। उनसे भी ज्यादा आहत पूरे सदन, मुख्यमंत्री विजय और स्पीकर ने किया, जिन्होंने एक शब्द भी आपत्ति में नहीं बोला। यह उस तमिलनाडु की विधानसभा में हुआ जहां 85 प्रतिशत से अधिक हिंदू हैं। इससे अधिक विडंबना व नफरती राजनीति पूरे देश में नहीं हो सकती। समझ से बाहर है कि तमिलनाडु के राजनेताओं में हिंदी व सनातन के लिए इतना जहर क्यों भरा है। कल्पना करो कि कोई विधायक ईसाई, मुस्लिम या अन्य धर्म के विरुद्ध एक शब्द भी बोल देता, तो पूरे देश में कितना हंगामा होता। दूसरा प्रधानमंत्री दी ने ईरान और अमेरिका-इजरायल युद्ध के दो मास बाद भावी आर्थिक आपदा की संभावना को देखते हुए सुझाव दे दिए। इनमें डीजल, पेट्रोल, खाद्य तेल की बचत, विदेश भ्रमण पर अंकुश, सोना खरीदने से बचना है। तर्क व तथ्यों के आधार पर इनमें कुछ भी बुरा नहीं है। आपदा न भी हो, तो भी ये सुझाव परिवार, राज्य और देश की आर्थिकी को अत्यधिक बढ़ाने वाले हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार भरकर, रुपये को मजबूत करने वाले हैं। ये आर्थिक संकट में तो बेहद जरूरी हैं। कांग्रेस व विपक्ष ने तो एकदम अंधविरोध और चरित्रहरण तक की ठान रखी है।

cpbansal3@gmail.com

पोस्ट

वीडी सतीशन को केरलम का मुख्यमंत्री बनाकर राजस्थान की गलती दोहराने से बची कांग्रेस। वहां विधायकों की नहीं, बल्कि जनता की पसंद के मुख्यमंत्री बने हैं।

शरत@sharatjpr

केरलम में वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनाना यही रेखांकित करता है कि कांग्रेस में मुस्लिम वीटो ही सर्वोपरि है।

राहुल कौशक@kaushkrahul

कुछ प्रतीकात्मक संदेशों को लेकर तमाम लोगों की अपनी शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री के विदेश दौरे की तुलना उनकी उस हिदायत से नहीं की जा सकती, जिसमें उन्होंने लोगों से विदेशी पर्यटन को लेकर संयम बरतने की अपील की।

संकेत उपाध्याय@sanket

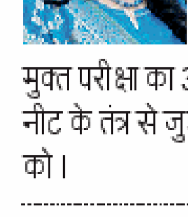

कितना दुखद है लाखों विद्यार्थियों की साल भर की मेहनत को यूं बर्बाद होते देखना। इससे भी दुखद है यह सच कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। क्या हम अपने देश के बच्चों को एक भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा का अधिकार नहीं दे सकते? शर्म आनी चाहिए नीट के तंत्र से जुड़े हर व्यक्ति को और हर एक परीक्षा एजेंसी को।

ऋचा अनिरुद्ध@richaanirudh

जनपथ

समय बिताने के लिए करना है कुछ काम,
चलो 'वकालत' ही करें मिल जाएगा दाम।
मिल जाएगा दाम लगेगा मन भी थोड़ा,
जज का खाय दिमाग खूब दौड़ेगा घोड़ा।
दीदी बेरोजगार ढूंढ नित नए बहाने,
पहने काला कोट चली हैं समय बिताने!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित
संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 300

खाद्य तेल का अधिक उपयोग: सेहत के साथ विदेशी मुद्रा का भी नुकसान

अरविंद शर्मा • जागरण

- प्रतिवर्ष औसतन 20 किलोग्राम तेल खा रहे भारतीय, मानक सिर्फ 12-13 किलोग्राम
- जरूरत का 57 प्रतिशत तेल हो रहा आयात, डेढ़ लाख करोड़ रुपये हो रहे खर्च

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की खाद्य तेल कम खाने की अपील सिर्फ फिटनेस मंत्र नहीं, बल्कि देश को दोहरे नुकसान से बचाने का प्रयास है। देश में प्रत्येक व्यक्ति औसतन प्रतिवर्ष 20 किलोग्राम खाद्य तेल का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन 12-13 किलोग्राम के भीतर खपत को सुरक्षित मानता है। जाहिर है, ज्यादा तेल खाने का असर लोगों की सेहत के साथ-साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हार्ट अटैक, मोटापा एवं ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं, वहीं खाद्य तेल के आयात पर प्रतिवर्ष लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने पड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा आयात पाम आयल का है, जिसे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं माना जाता।

प्रधानमंत्री बार-बार लोगों से खाद्य तेल के इस्तेमाल में कटौती की अपील इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि देश में इसकी खपत पिछले छह दशक में कई गुना बढ़ी है। वर्ष 1960-61 में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष तेल खपत सिर्फ 3.2 किलोग्राम थी। वर्ष 2000-01 तक यह बढ़कर 8.2 किलोग्राम हुई व अब 20 किलोग्राम के पार पहुंच गई है। यही रफ्तार रही तो 2028 तक प्रति व्यक्ति खपत 25 किलोग्राम और 2038 तक 40 किलोग्राम तक पहुंच सकती है।

स्थिति इसलिए और चिंताजनक है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 57% खाद्य तेल आयात करता है। 2022-23 में देश में खाद्य तेल की कुल खपत 292 लाख टन थी, जबकि घरेलू उत्पादन 126.9 लाख टन था। इसे पूरा करने के लिए 165 लाख टन तेल आयात करना पड़ा। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में 103.9 लाख टन पाम आयल का आयात किया गया। 39.6 लाख टन सोयाबीन का तेल और 21.45 लाख टन सूरजमुखी का तेल खरीदा गया। पाम आयल में वसा की मात्रा अधिक होने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

बढ़ती चुनौती को देखते हुए सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन को तेजी से बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य खाद्य तेल के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने, किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने और परती जमीन पर तिलहन खेती को बढ़ावा देने पर काम शुरू किया गया है। आयात पर नियंत्रण के लिए सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाया है। कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क 5.5% से बढ़ाकर 16.5% कर दिया गया है। रिफाइंड तेलों पर शुल्क 35.75% तक पहुंच गया है। इससे किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। समस्या के समाधान के लिए सरकारी योजनाओं के साथ-साथ खानपान की आदतों में बदलाव जरूरी है। पारंपरिक खानपान और संतुलित आहार बढ़ती बीमारियों और भारी आयात बिल से बचा सकता है।

वाहनों के काफिले के साथ भिंड पहुंचे जिलाध्यक्ष को भाजपा ने पद से हटाया

नईदुनिया प्रतिनिधि, भिंड : प्रधानमंत्री की पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील की अवहेलना मध्य प्रदेश के भिंड में भाजपा किसान मोर्चा को नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव को भारी पड़ गई। वह 120 वाहनों के काफिले के साथ नगर में पहुंचे थे। पार्टी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। भाजपा के किसी पदाधिकारी पर इस मामले में कार्रवाई का यह पहला मामला है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह ने सज्जन को पत्र लिखकर नियुक्ति निरस्त करने की जानकारी दी। इससे पहले निगम-मंडलों के नवनियुक्त पदाधिकारी भी चर्चा में रहे। पाठ्यपुस्तक निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष सौभाग्य सिंह करीब ढाई सौ वाहनों के काफिले के साथ उज्जैन से भोपाल पहुंचे थे।

सज्जन सिंह यादव • फाइल फोटो

ई-रिक्शा में निकले भाजपा नेता, पीछे चला 200 वाहनों का काफिला : नईदुनिया, जबलपुर के मुताबिक भाजपा नेता व सिंगरौली विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल चर्चा में हैं। वह कार्यभार ग्रहण करने खुद तो ई-रिक्शा में निकले लेकिन उनके पीछे 200 वाहनों का काफिला चला।

कृषि मंत्री शिवराज ने भी घटाया अपना काफिला

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ईंधन बचत और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बचत की पहल कर दी है। अपने वाहनों के काफिले को घटाकर तीन गाड़ियों तक सीमित कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को ऐसा वर्क फ्राम होम माडल तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे काम प्रभावित हुए बिना ईंधन की बचत हो सके।

रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर नियंत्रण को खेत बचाओ अभियान : रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल पर नियंत्रण के लिए खेत बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। गांव-गांव में खेत बचाओ समितियां बनेंगी। किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग तथा प्राकृतिक खेती के लिए जागरूक किया जाएगा।

10 से 12 लाख रुपये में हुई थी डील : सीबीआइ

नीट पेपर लीक मामले में अदालत ने पांच आरोपितों को सात दिन की रिमांड पर भेजा

- सीबीआइ एनटीए के कुछ अधिकारियों की संभावित भूमिका की भी कर रही है जांच
- एजेंसी ने कहा- प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले टेलीग्राम व वाट्सएप के जरिये पीडीएफ में प्रसारित किया गया

<< नई दिल्ली में गुरुवार को नीट यूजी पेपर लीक मामले में एक आरोपित (मध्य) को राउज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआइ अदालत ले जाते अधिकारी • एएनआइ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत में नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पांच आरोपितों को सात दिन की सीबीआइ रिमांड में भेजा गया। सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने आरोपितों को पेश कर दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले टेलीग्राम और वाट्सएप के जरिये पीडीएफ फार्मेट में प्रसारित किया गया था और इसके पीछे एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा था। सीबीआइ ने मामले को गहरी साजिश बताते हुए आरोपितों की सात दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान नासिक निवासी शुभम खैरनार, जयपुर निवासी मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल व दिनेश बिवाल और गुरुग्राम निवासी यश यादव के रूप में हुई है। इन्हें अलग-अलग राज्यों से ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक, पेपर लीक के बदले 10 से 12 लाख रुपये तक की डील की गई थी।

सीबीआइ ने अदालत को बताया कि अप्रैल 2026 में नासिक निवासी शुभम ने यश यादव को जानकारी दी थी कि मांगीलाल अपने छोटे बेटे को मेडिकल कालेज में दाखिला दिलाने के लिए लीक हुआ पेपर खरीदना चाहता है। इसके बाद 29 अप्रैल को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र पीडीएफ फार्मेट में टेलीग्राम के जरिये साझा किए गए थे। एजेंसी के अनुसार, मांगीलाल ने 10 लाख रुपये में पेपर हासिल किए और फिर उनकी प्रिंट कापियां अपने बेटे अमन बिवाल समेत रिश्तेदारों और परिचितों तक पहुंचाई। वहीं, विकास बिवाल पर आरोप है कि उसने कई अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनकी जानकारी वाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिये यश यादव को भेजी, ताकि पेपर आगे सर्कुलेट किए जा सकें।

सीबीआइ का दावा है कि आरोपितों के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक चैट, लीक पेपर और अन्य डिजिटल सुबूत मिले हैं। एजेंसी ने कहा कि कई अहम डाटा डिलीट किए गए थे, जिन्हें फारेंसिक जांच के जरिये रिकवर किया जाएगा। सीबीआइ ने अदालत को बताया कि एनटीए ने तीन मई को आयोजित नीट-यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद कर दिया था। आरोपितों से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि पेपर लीक के असली स्रोत, लेनदेन, डिजिटल नेटवर्क और संभावित मिलीभगत का पर्दाफाश किया जा सके। एजेंसी एनटीए के कुछ अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

एक हजार से अधिक छात्रों को मिला था लीक पेपर

- एसओजी की जांच में राजफाश, प्राइवेट माफिया नाम के वाट्सएप ग्रुप से प्रसारित हुआ था पेपर
- सीकर के करियर काउंसलर राकेश ने टेलीग्राम के जरिये 700 छात्रों को भेजा था गेस पेपर

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एसओजी) का दावा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) 2026 का लीक पेपर करीब एक हजार से अधिक छात्रों को मिला था। सीकर के करियर काउंसलर राकेश मंडवारिया ने टेलीग्राम के जरिये 700 से अधिक छात्रों को 410 सवालों का अभ्यास करवाया था। राकेश को सीबीआइ ने बुधवार रात तीन अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया है। एसओजी ने करीब डेढ़ सौ से अधिक छात्रों के नामों की सूची सीबीआइ को सौंपी है, जो टेलीग्राम के जरिये पहले खुद राकेश के संपर्क में आए और फिर उन्होंने अन्य छात्रों को जोड़ा।

एसओजी की छह दिन की जांच में सामने आया कि टेलीग्राम के अतिरिक्त पेपर लीक माफियाओं ने कई वाट्सएप ग्रुप बनाए थे। इनमें से एक वाट्सएप ग्रुप प्राइवेट माफिया के नाम से सामने आया है। इस ग्रुप में करीब चार सौ से अधिक छात्र जुड़े थे। ग्रुप के कैप्शन में लिखा है कि यह ग्रुप सिर्फ परीक्षा पेपर अपलोड करने के लिए बनाया गया है। एसओजी ने हिरासत में लिए गए 24 लोगों के मोबाइल बरामद किए हैं। मोबाइल फोन में मिले गेस पेपर और परीक्षा में आए पेपर के 120 सवाल पूरी तरह से समान हैं। जांच एजेंसी की नजर से बचने के लिए मूल पेपर को गेस पेपर का नाम दिया गया था।

बिवाल परिवार के पांच बच्चे कर रहे एमबीबीएस : राजस्थान में नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड मांगीलाल और दिनेश बिंवाल का परिवार पहले पांच बच्चों के एमबीबीएस में चयन को लेकर चर्चा में आया था। दिनेश बिंवाल ने वर्ष 2025 में सोशल मीडिया पर इसे परिवार के लिए गर्व की बात बताया था। एसओजी की जांच में सामने आया है कि आरोपितों ने गुरुग्राम के यश यादव से करीब 45 लाख रुपये में पेपर का सौदा किया और 30 लाख अग्रिम दिए। दिनेश ने सबसे पहले यह गेस पेपर अपने पुत्र विकास को टेलीग्राम पर भेजा था। विकास ने सीकर में छात्रों को दो से 10 लाख रुपये में यह पेपर 29 अप्रैल से एक मई तक बेचा था। इस बीच दिनेश ने 29 अप्रैल को सीकर पहुंचकर अपने परिचितों के माध्यम से बेचा था। सीकर के कुछ छात्रों के पास जब पेपर पहुंचा तो करियर काउंसलर राकेश को इस बारे में जानकारी मिली और उसने सीधे दिनेश को पैसे देकर पेपर ले लिया। सीकर के एक ई-मित्र संचालक की दुकान से पेपर की बड़ी मात्रा में फोटो स्टेट करवाई गई थी। परीक्षा से एक दिन पहले दो मई की रात को पेपर दो से पांच हजार रुपये तक में बेचा गया। सीबीआइ ने 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद पांच को गिरफ्तार किया है।

जून के पहले या दूसरे रविवार को हो सकती है नीट-यूजी की परीक्षा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट-यूजी का पेपर लीक होने एवं परीक्षा रद होने से परेशान छात्रों और अभिभावकों की निगाहें अब दोबारा होने वाली परीक्षा पर टिकी हैं। यानी यह परीक्षा कब और कैसे होगी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उसके तहत छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक महीने तक का समय दिया जा सकता है। ऐसे में यह परीक्षा जून के पहले या दूसरे रविवार को कराई जा सकती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) अगले हफ्ते तक अधिकारिक रूप से परीक्षा की नई तिथि घोषित कर सकती है।

शिक्षा मंत्रालय एवं एनटीए से जुड़े सूत्रों की मानें तो नीट-यूजी की दोबारा परीक्षा इससे पहले नहीं कराई जा सकती क्योंकि विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी सीयूईटी-यूजी की परीक्षा 31 मई तक होनी है। इस दौरान किसी परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आई, तो उन्हें जून के पहले हफ्ते में कराया जा सकता है। इसके बाद ही नीट-यूजी को कराया जा सकता है।

प्रधान ने की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर गुरुवार शाम नीट-यूजी के दोबारा आयोजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हुई। इस बैठक में परीक्षा के आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी, स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह, सीबीएसई के चेयरपर्सन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ-साथ अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

गुरुग्राम का यश निकला राजस्थान में नीट पेपर लीक कांड का सबसे बड़ा सूत्रधार

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: नीट पेपर लीक कांड के बड़े सूत्रधार के रूप में यश यादव का नाम सामने आ रहा है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक यदि जयपुर के रहने वाले दिनेश एवं मांगीलाल से यश ने डील न की होती तो यह पूरे राजस्थान में लीक न होता। यह भी सामने आ रहा है कि राजस्थान से ही अन्य राज्यों में पेपर बेचे गए। जयपुर के रहने वाले आरोपितों ने सीधे तौर पर यश का नाम लिया है। राजस्थान एसओजी ने फिलहाल अपनी रिपोर्ट सीबीआइ को सौंप दी है। आगे की जांच अब सीबीआइ करेगी।

जिले के गांव खेड़ा के रहने वाला यश यादव उत्तरकाशी के मंजीरा देवी आयुर्वेदिक कालेज में द्वितीय वर्ष का छात्र है। उसने सीकर में रहकर कोचिंग ली थी। राजस्थान आने-जाने के दौरान ही नासिक से पकड़े गए मुख्य आरोपित शुभम खैरनार व जयपुर से पकड़े गए आरोपित दिनेश एवं मांगीलाल से उसकी जान-पहचान हुई थी। दिनेश एवं मांगीलाल भाई हैं। शुभम ने 15 लाख रुपये में पेपर यश से बेचा। यश ने आगे दिनेश एवं मांगीलाल से 45 लाख रुपये में डील की। दोनों भाइयों ने आगे अन्य लोगों से डील की। शुभम के पास पेपर कहां से पहुंचा, इस बारे में सही जानकारी सामने नहीं आई है। यश ने भी अपने स्तर पर हरियाणा, उत्तराखंड एवं राजस्थान के कई इलाकों में अपने नेटवर्क के माध्यम से पेपर पहुंचाया। अब सीबीआइ के रडार पर वे सभी विद्यार्थी आएंगे, जिनके पास पेपर पहुंचे। इस मामले के साथ ही नीट 2024 पेपर लीक कांड में भी यही ग्रुप तो शामिल नहीं था, इसकी भी छानबीन की जा रही है। उस समय भी इसी तरह पेपर लीक हुआ था। तरीका समान होने की वजह से आरोपितों पर 2024 पेपर लीक कांड में शामिल होने का अंदेशा है।

फरुखनगर के खेड़ा गांव स्थित यश यादव का घर • जागरण

बच्चों की पढ़ाई में बिक गई जमीन : गांव में इस बात की चर्चा है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पिता हरबीर यादव ने अपनी पूरी जमीन बेच दी। हरबीर यादव के तीन बच्चे हैं। बड़ा बेटा होटल मैनेजमेंट कर एक होटल में नौकरी कर रहा है। बेटी जीएसटी में ला की पढ़ाई कर रही है। यश मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। हरबीर के पास डेढ़ किला जमीन थी। डेढ़ साल पहले एक किला जमीन बेच दी थी। आधा किला जमीन छह महीने पहले बेच दी। गांव के लोगों का कहना है कि परिवार के किसी सदस्य के बारे में कोई शिकायत सामने नहीं आई। पेपर लीक मामले में यश का नाम सामने आने से वे हैरान हैं। बच्चे बाहर रहते हैं। वे क्या करते हैं, किसके संपर्क में हैं, स्वजन को भी नहीं पता होता है। गांव के पूरण यादव कहते हैं कि सीबीआइ की जांच से पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी।

उत्तराखंड में बीएएमएस की पढ़ाई कर रहा था यश यादव

जासं, उत्तरकाशी : नीट-यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार गुरुग्राम हरियाणा निवासी यश यादव उत्तरकाशी के श्रीमती मंजीरा देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज से बीएएमएस की पढ़ाई कर रहा था। वह बीएएमएस प्रथम वर्ष का छात्र था। पिछले चार-पांच माह से लगातार अनुपस्थिति के चलते संस्थान ने पहले उसे कई बार नोटिस दिए, फिर अर्थदंड लगाया। जब वह उपस्थित नहीं हुआ तो अप्रैल में संस्थान ने उसे डिबार घोषित कर दिया। यश ने वर्ष 2023-24 बैच में नीट यूजी के माध्यम से तीसरी काउंसलिंग में कालेज में प्रवेश लिया था। यश ने नीट यूजी में 1220510 रैंक हासिल की थी।

भाजपा ने कहा- परीक्षा माफिया का सफाया किया जाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को गंभीरता और संवेदनशीलता से लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने छात्रों एवं अभिभावकों को इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। पात्रा ने कहा, "किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, खासकर इस परीक्षा माफिया को जो हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है।"

प्रवेश परीक्षा रद होने से 22 लाख से अधिक मेडिकल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में अनिश्चितता का माहौल है। इस मुद्दे को "संवेदनशील और दुखद" बताते हुए पात्रा ने कहा कि यह न केवल 22 लाख छात्रों से संबंधित है, बल्कि उनके अभिभावकों की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। उन्होंने कहा, "इस सरकार ने इस मामले को न केवल गंभीरता से बल्कि अत्यंत संवेदनशीलता के साथ लिया है।"

वकील की ड्रेस में हाई कोर्ट पहुंचीं ममता के खिलाफ लगे 'चोर-चोर' के नारे

- धक्का-मुक्की व अशालीन भाषा का प्रयोग, ममता ने कुछ वकीलों पर लगाया उन्हें मारने का आरोप
- ममता ने चुनाव बाद हिंसा मामले में खुद रखीं दलीलें, कहा-बंगाल कोई 'बुलडोजर स्टेट' नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट परिसर में भारी विरोध और नारेबाजी का सामना करना पड़ा। चुनाव बाद हिंसा से संबंधित एक मामले में पैरवी करने पहुंचीं ममता बनर्जी जब कोर्ट रूम से बाहर निकल रही थीं, तब वकीलों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनके खिलाफ 'चोर-चोर' के नारे लगाए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नारेबाजी के दौरान अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। ममता ने वकीलों के एक समूह पर उन्हें मारने का आरोप लगाया है।

दूसरी तरफ भाजपा ने कहा कि इसके पीछे तृणमूल के ही लोग शामिल हैं। बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि यह भाजपा की संस्कृति नहीं है। मालूम हो कि वकील शीर्षान्य बनर्जी द्वारा चुनाव बाद हिंसा को लेकर मामला दायर किया गया है, जिसमें ममता अधिवक्ता के रूप में जिरह करने हाई कोर्ट पहुंची थीं।

राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से न हो कार्रवाई- ममता : अदालत में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल कोई 'बुलडोजर स्टेट' नहीं है। कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए न कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से। उन्होंने कहा कि करीब 160 तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई हैं। चुनाव बाद हिंसा की करीब दो हजार घटनाएं हो चुकी हैं।

कानून-व्यवस्था की स्थिति पर आगामी तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी: पुलिस ने कोर्ट में कहा कि सभी घटनाएं चुनाव बाद हिंसा की नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल ने प्रशासन से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर आगामी तीन सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव बाद हिंसा में अगर किसी के घर या दुकान पर कब्जा किया गया है तो उसे लौटाने का निर्देश दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ममता बनर्जी ने एक बार फिर साबित किया है कि वह बंगाल के लोगों को कठिन समय में कभी अकेला नहीं छोड़तीं। आम लोगों के लिए लड़ाई जारी रहेगी।

कोलकाता में हाई कोर्ट से बाहर निकलतीं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी • प्रेट्र

ममता की वकालत पर बीसीआइ ने बार काउंसिल से मांगी रिपोर्ट

बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) ने बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के अंदर ममता बनर्जी की वकालत और पेशेवर स्थिति को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह कार्रवाई तब सामने आई जब ममता गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील की वेशभूषा में एक मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुईं। यह मामला चुनाव बाद हिंसा और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से जुड़ा हुआ था। बीसीआइ ने काउंसिल को भेजे पत्र में कहा है कि ममता के नामांकन, वकालत की स्थिति और कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार के निलंबन या पुन: बहाली से जुड़े सभी रिकार्ड उपलब्ध कराए जाएं। स्पष्ट किया कि यह जानकारी उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल (2011 से 2026) के दौरान उनकी पेशेवर स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर कार्यरत होता है या किसी अन्य लाभकारी पद पर रहता है तो उसे वकालत का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित करना होता है। सेवा समाप्त होने के बाद ही इसे पुन: सक्रिय किया जा सकता है। इसी संदर्भ में बार काउंसिल आफ इंडिया ने ममता के मामले में यह जांच शुरू की है कि क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस के डीसीपी को ईडी ने किया गिरफ्तार

सोना पप्पू केस में घिरे है पुलिस अधिकारी, लुकआउट नोटिस के बाद सीजीओ कांप्लेक्स में हुई गिरफ्तारी, अदालत में पेशी आज

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: ईडी ने गुरुवार की रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (डीसीपी) शांतनु सिन्हा बिश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। जमीन हड़पने, जबरन वसूली और वित्तीय हेराफेरी के हाई-प्रोफाइल मामले में 10.30 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया। शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी।

शातिर अपराधी बिश्वजीत पोद्दार उर्फ सोना पप्पू से जुड़े मामलों में ईडी शांतनु से लंबे समय से जवाब मांग रही थी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब शांतनु साल्टलेक स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे तो अधिकारियों ने सवालों की झड़ी लगा दी। सूत्रों के अनुसार, शांतनु जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। अंततः रात करीब 9.30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

समन की अनदेखी और लुकआउट नोटिस : शांतनु की मुश्किलें तब और बढ़ गई थीं जब उन्होंने ईडी के कई समन को नजरअंदाज किया। कालीघाट थाने के पूर्व प्रभारी रहे अधिकारी के खिलाफ एजेंसी ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, ताकि देश छोड़कर न भाग सकें।

यह है मामला : यह गिरफ्तारी मुख्य रूप से सोना पप्पू और उसके गिरोह द्वारा की गई अवैध वसूली और जमीन कब्जाने के मामले से जुड़ी है। जांच में सामने आया है कि शांतनु के इस गिरोह के साथ संदिग्ध आर्थिक संबंध थे।

टीवीके ने भी छेड़ा सनातन विरोधी राग

चेन्नई, आइएएनएस : टीवीके के विधायक वीएमएस मुस्तफा ने गुरुवार को द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन की सनातन विरोधी विवादित टिप्पणियों का समर्थन किया, जिससे राज्य में एक नया राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर भाजपा नेता के. अन्नामलाई ने सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर द्रमुक और टीवीके पर तीखा हमला किया। दोनों पार्टियों पर हिंदू विश्वासों और परंपराओं के प्रति नफरत रखने का आरोप लगाया। यह आलोचना तब की गई जब द्रमुक के विधायक उदयनिधि स्टालिन ने तमिलनाडु विधानसभा में "सनातनम" पर अपने विवादास्पद बयान को दोहराया।

टीवीके विधायक मदर बदरुद्दीन ने तमिलनाडु के विपक्ष के नेता स्टालिन के सनातन को समाप्त करने संबंधी टिप्पणियों का समर्थन करने के बाद विवाद को जन्म दिया, लेकिन बाद में अपनी टिप्पणी वापस ले ली। जब उनसे स्टालिन की सनातन धर्म को समाप्त करने संबंधी टिप्पणियों के बारे में पूछा गया, तो मुस्तफा ने कहा, "हम टीवीके में पेरियार ईवी रामासामी व बीआर आंबेडकर के विचारधाराओं का पालन करते हैं। हम सनातन का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

बंगाल में खुले में गोवंशी सहित अन्य पशुओं के काटने पर 'फुल स्टाप'

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर अब पशु जिबह (काटना) गुजरे जमाने की बात होने वाली है। राज्य की नई भाजपा सरकार ने 'पश्चिम बंगाल पशु जिबह नियंत्रण अधिनियम, 1950' को पूरी सख्ती से धरातल पर उतारने का जो फैसला लिया है, उसने पूरे प्रशासनिक तंत्र में हलचल मचा दी है। पूर्ववर्ती ममता सरकार में इस कानून को लेकर ऐसी सक्रियता कभी नहीं दिखी थी। अब मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के निर्देश के बाद कोलकाता से लेकर मालदा और मुर्शिदाबाद तक, फाइलों की धूल झाड़ी जा रही है और नए नियमों का खाका खींचा जा रहा है।

2018 के आदेश से 2026 की सख्ती तक : प्रशासनिक सक्रियता की जड़ें कलकत्ता हाई कोर्ट के छह अगस्त 2018 के उस ऐतिहासिक आदेश में छिपी हैं, जिसे 2022 के दिशा-निर्देशों ने और मजबूती दी। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि सार्वजनिक स्थानों पर जिबह न केवल कानून-व्यवस्था बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चुनौती है। सरकार ने इसे 'गंभीर अपराध' की श्रेणी में रखते हुए छह महीने की जेल, एक हजार जुर्माना या फिर दोनों का प्रविधान कर साफ कर दिया है कि कोताही की जगह नहीं है। उत्तर 24 परगना और हावड़ा जैसे जिलों में अब बिना लाइसेंस वाले मांस विक्रेताओं पर गाज गिरनी तय है। मांस विक्रेताओं के बीच चिंता है कि 'प्रमाणपत्र' की प्रक्रिया और अधिकृत बूचड़खानों की कमी उनके व्यवसाय की रफ्तार धीमी कर सकती है।

पहली बार के भाजपा विधायक रथिंद्र बोस होंगे बंगाल विस के नए अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: उत्तर बंगाल की कूचबिहार दक्षिण सीट से भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए रथिंद्र बोस बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष (स्पीकर) होंगे। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनके पहले प्रस्तावक खुद मुख्यमंत्री सुवेंदु बने जबकि दूसरे प्रस्तावक मंत्री दिलीप घोष हैं।

बंगाल के स्कूलों में अब 'वंदे मातरम्' अनिवार्य, ममता के बनाए 'ब' लोगो वाले यूनिफार्म पर रोक

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की कवायद तेज हो गई है। राज्य की नई भाजपा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के बाद अब राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की सुबह की प्रार्थना सभा का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। नए सर्कुलर के अनुसार, अब स्कूलों में 'वंदे मातरम्' का गायन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान वितरित किए जाने वाले स्कूल बैग और यूनिफार्म के वितरण पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि यह रोक इसीलिए लगाई गई है, क्योंकि बैग और यूनिफार्म पर ममता बनर्जी द्वारा तैयार कराया गया बिस्वा बांग्ला का लोगो 'ब' है। मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले सरकारी वेबसाइटों पर लेटर हेड से लोगो को हटाने का निर्देश दिया था।

प्रार्थना सभा में अब गूंजेंगे तीन गीत : राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी ताजा नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अब हर स्कूल को अपनी सुबह की प्रार्थना सभा में 'वंदे मातरम्' को शामिल करना होगा। मालूम हो कि इससे पहले स्कूलों में केवल राष्ट्रगान 'जन गण मन' और 'बांग्लार माटी, बांग्लार जल' (राज्य गान) गाया जाता था। अब इन दोनों के साथ 'वंदे मातरम्' का गायन भी अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में कहा कि आगामी सोमवार से यह नियम लागू हो जाएगा। सीएम के इस स्पष्ट संदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इसे लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हालांकि, कई स्कूल प्रमुखों ने इस पर चिंता जताई है कि तीन गीतों के गायन से प्रार्थना सभा का समय बढ़ जाएगा, जिससे कक्षाओं के संचालन में देरी हो सकती है।

सीएम सुवेंदु अधिकारी • फाइल फोटो

- नई सरकार के फैसलों से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव
- स्कूल बैग और यूनिफार्म पर बिस्वा बांग्ला के लोगो पर रोक

'बिस्वा बांग्ला' लोगो पर चला हथौड़ा : शिक्षा विभाग ने केवल गीतों तक ही सीमित न रहते हुए, पिछली सरकार के सबसे मजबूत ब्रांड 'बिस्वा बांग्ला' पर भी कड़ा प्रहार किया है। सभी जिला स्कूल निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि नीले-सफेद रंग की यूनिफार्म और 'बिस्वा बांग्ला' लोगो वाले स्कूल बैग का वितरण रोक दिया जाए।

शिक्षा क्षेत्र में हलचल : शिक्षा क्षेत्र में मची इस हलचल की धमक कालेजों तक पहुंची है। उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य सहायता प्राप्त कालेजों की गवर्निंग बाडी के अध्यक्षों और नामित सदस्यों की नियुक्तियां रद कर दी हैं। साथ ही, सेवानिवृत्ति के बाद सेवा विस्तार पर टिके अधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है।

चिंतन

मतदाता सूची शुद्ध है ये दिखना भी जरूरी

लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत निष्पक्ष और भरोसेमंद चुनाव होते हैं। चुनाव तभी विश्वसनीय माने जाते हैं, जब मतदाता सूची पूरी तरह पारदर्शी, सटीक और संदेह से परे हो। यही वजह है कि चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास को मजबूत करने का अभियान है। अब जब आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में तीसरे चरण की घोषणा कर दी है, तो यह जरूरी हो जाता है कि मतदाता सूची न केवल शुद्ध हो, बल्कि जनता को यह स्पष्ट रूप से दिखे भी कि प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है। एसआईआर का तीसरा चरण 1 जुलाई से शुरू होगा। पिछले एसआईआर में मतदाता सूची को लेकर कई विवाद सामने आए। कर्नाटक में हजारों वोटर आईडी में मकान नंबर "0", "00", "77777" या "9999" दर्ज पाए गए। बिहार में भी करीब 2.92 लाख मतदाताओं के पते इसी तरह दर्ज होने का मामला सामने आया। विपक्ष ने इसे फर्जी मतदाताओं और चुनावी धांधली से जोड़कर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने सफाई दी कि बेघर, अनधिकृत कॉलोनियों या बिना नंबर वाले मकानों में रहने वाले लोगों को मतदाता सूची से बाहर न करने के लिए ऐसे "नोशनल नंबर" दिए जाते हैं। यह तर्क मानवीय और समावेशी जरूर है, लेकिन सवाल यह है कि यदि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से नहीं होगी तो संदेह की गुंजाइश बनी रहेगी। यदि मतदाता सूची में एक ही पते पर दर्जनों नाम दिखाई दें या हजारों घरों का नंबर "0" हो, तो आम मतदाता के मन में शंका पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि चुनाव आयोग को अब तकनीकी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर सुधार की जरूरत है। आयोग द्वारा मकान नंबर की अनिवार्यता खत्म करने या नए फॉर्मेट पर विचार करना एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसके साथ मजबूत ग्राउंड वेरिफिकेशन और जवाबदेही भी जरूरी होगी। तीसरे चरण में 3.94 लाख बीएलओ और 3.42 लाख बीएलए को लगाया गया है, जो घर-घर जाकर लगभग 36.73 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बीएलओ द्वारा की गई एंट्री का डिजिटल ऑडिट, जीपीएस आधारित सत्यापन और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। एसआईआर में पिछली जो गलतियां सामने आईं, उन्हें भी इस बार ठीक करना होगा। वहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों को भी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। बीएलओ और अन्य कर्मचारियों की भी सुरक्षा देना प्राथमिकता होना चाहिए ताकि वे निष्पक्षता से काम कर सकें। इसके अलावा गर्मी का मौसम भी चुनौती बढ़ा सकता है। विपक्ष के आरोपों, सुप्रीम कोर्ट के सवालों और चुनाव आयोग के जवाबों के बीच राजनीतिक टकराव भी तेज हुआ है। इस मुद्दे को केवल राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मतदाता सूची किसी एक दल की नहीं, पूरे लोकतंत्र की नींव है। हालांकि पिछली बार पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो बाकी राज्यों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगले साल मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, यूपी और गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। अंततः, एसआईआर केवल मतदाता सूची सुधारने की कवायद नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास की परीक्षा भी है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी पात्र मतदाता वंचित न रहे और कोई भी फर्जी नाम सूची में न बचे। मतदाता सूची शुद्ध होना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यह दिखना भी है कि प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद है। यही लोकतंत्र की असली मजबूती होगी।

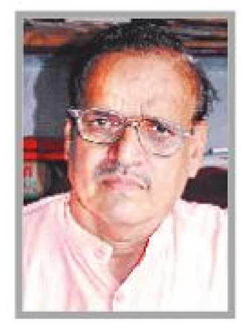

मुद्दा
प्रमोद भार्गव

ईरान-अमेरिका युद्ध में तेल की बर्बादी

अमेरिका-ईरान के बीच जंग के मैदान बने समुद्र में तेल खेल का औजार बन गया है। अमेरिकी नाकाबंदी के चलते एक महीने के भीतर ईरान के 58 तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य पार नहीं कर पाए। इस कारण प्रतिदिन 30 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल समुद्र में बहा रहा है। हर दिन नष्ट किए जा रहे इस तेल की कीमत 2800 करोड़ रुपये है। ईरान को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी तीन करोड़ बैरल तेल भंडारण की क्षमता पूरी हो चुकी है। मध्य एशिया में जल रहा यह तेल हिंद महासागर के तापमान को अप्रत्याशित रूप में बढ़ाएगा। इसका सीधा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, धूल भरे अंधड़ की घटनाएं कालांतर में देखने को मिल सकती हैं।

अमेरिका-ईरान के बीच जंग के मैदान बने समुद्र में तेल खेल का औजार बन गया है। अमेरिकी नाकाबंदी के चलते एक महीने के भीतर ईरान के 58 तेल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य पार नहीं कर पाए। इस कारण प्रतिदिन 30 लाख बैरल से ज्यादा कच्चा तेल समुद्र में बहा रहा है। हर दिन नष्ट किए जा रहे इस तेल की कीमत 2800 करोड़ रुपये है। ईरान को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी तीन करोड़ बैरल तेल भंडारण की क्षमता पूरी हो चुकी है। ईरान के पास 3500 ऐसे तेल के कुएं हैं, जिनसे निरंतर तेल का उत्पादन जरूरी है। यदि तेल निकालना बंद कर दिया गया तो इन कुओं से तेल का उत्पादन हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग बंद कर देने से कुएं के भीतर डाली गई पाइपलाइनों में पानी-गैस भर जाते है।

इन्हीं पाइपों से कच्चा तेल रिस-रिसकर आता है। तेल की चट्टानों के छेदों में वैक्स की परत जम जाने से तेल रिसना बंद हो जाता है। यह मोम जैसा प्राकृतिक या रासायनिक ठोस पदार्थ होता है। ईरान कच्चे तेल का 90 प्रतिशत निर्यात खार्ग द्वीप से करता है। यहीं ईरान के तेलों के भंडार गृह हैं। तेल की यह बर्बादी पश्चिम एशिया के देशों के लिए, ऊर्जा का संकट तो बन ही रही है, समुद्री पर्यावरण भी तेजी से बिगड़ रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से अपील करनी पड़ी है कि इस संकट के दौरान पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग कम से कम करें। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सेंटिनल सैटेलाइट डेटा और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खार्ग की खाड़ी एवं होर्मुज स्ट्रेट के आसपास समुद्री पानी की सतह पर तेल की परतें देखी गई हैं। ये परतें कुवैत के लावन द्वीप, केशम द्वीप और खार्ग द्वीप के समुद्र में बड़े-बड़े धब्बों के आकार में देखी गई हैं। इनमें से एक धब्बा करीब 120 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। विशेषज्ञों ने रडार डेटा की मदद से इसका विश्लेषण करते हुए कहा है कि सतह पर तैरता तेल लहरों को शांत कर देता है, जिससे रडार से ली गई तस्वीरों में काले और चिकने धब्बे दिखाई देते हैं। इस कारण यह आशंका बनी है कि ईरान समुद्र में तेल बर्बाद कर रहा है। यदि यह तेल लगातार छोड़ा जाता रहा तो इससे समुद्री जीवन और पर्यावरण को भारी नुकसान हो सकता है। फारस की खाड़ी के समुद्री क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मछुआरे, कोरल रीफ और अन्य समुद्री जीव रहते हैं, जिन पर लाखों लोगों की आजीविका निर्भर है। यह तेल मछलियों के लिए जहर का काम कर सकता है। समुद्री पक्षियों को नुकसान पहुंचाता है और संवेदनशील समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर देता है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और अनेक समुद्री जीव बेमौत मर जाते हैं। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़ी जंग समुद्री पर्यावरण के लिए भारी संकट के रूप में पेश आ रही है। यह संकट धरती से लेकर आसमान तक कहर ढा रहा है। होर्मुज के संकरे मार्ग पर तेल की इस बर्बादी से पहले पेट्रोलियम पदार्थों से भरे करीब 20 जहाज नष्ट कर दिए गए गए थे। एक अनुमान के अनुसार इन टैंकरों में तीन लाख मीट्रिक टन तरल एलपीजी भरी हुई थी। एक बड़े गैस टैंकर में लगभग 45 हजार मीट्रिक टन एलपीजी होती है और एक बड़े गैस टैंकर से करीब 31 से 32 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे

जा सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ एक साथ मिट्टी, पानी और हवा को दूषित करते हुए मानव जीवन के लिए वरदान की बजाय अभिशाप साबित होने लग जाते हैं। तेल के रिसाव, तेल टैंकों के टूटने व धोने से भी समुद्र का पर्यावरणीय पारिस्थितिकी-तंत्र (इकोसिस्टम) प्रभावित हो रहा है। कुछ साल पहले जापान में टोकियों के तट पर 317 किमी की पट्टी पर तेल के फैलाव से जापान के तटवर्ती शहरों में हाहाकार मच गया था। रूस में बेलाय नदी के किनारे बिछी तेल पाइप लाइन से 150 मीट्रिक टन के रिसाव ने यूराल पर्वत पर बसे ग्रामवासियों को पेय जल का संकट खड़ा कर दिया था। सैनजुआन जहाज के कोरल चट्टानों से टकरा जाने के कारण अटलांटिक तट पर करीब तीस लाख लीटर तेल का रिसाव होने से समुद्री जीव प्रभावित हुए थे। मुंबई हाई से लगभग 1600 मीट्रिक टन तेल का रिसाव हुआ। इसी तरह बंगाल की खाड़ी में क्षतिग्रस्त तेल से फैले टैंकर ने निकोबार द्वीप समूह में तबाही मचा दी थी। जिससे यहां रहने वाली जनजातियों और समुद्री जीवों को भारी हानि हुई थी। लाइबेरिया के एक टैंकर से 85000 मीट्रिक टन रिसे तेल ने स्कॉटलैण्ड में पक्षी-समूहों को बड़ी तादात में हानि पहुंचाई दी थी।

सबसे भयंकर तेल का फैलाव यूएसए के अलास्का में हुआ था। यह रिसाव प्रिंस विलियम साउण्ड टैंकर से हुआ था। इस तेल के फैलाव का असर छह माह तक रहा। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 35000 पक्षी, 10000 ओस्टर शेलफिस और 15 व्हेल मछली मर गईं थीं। बावजूद इस घटना का असर इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन द्वारा समुद्र में छोड़े तेल से कम था। यह तेल इसलिए छोड़ा गया था कि कहीं यह अमेरिका के हाथ न लग जाए। अमेरिका द्वारा इराक के तेल टैंकरों पर की गई बमबारी से भी लाखों टन तेल समुद्री सतह पर फैला था। एक अनुमान के मुताबिक इस कच्चे तेल की मात्रा 110 लाख बैरल थी। इस तेल के बहाव ने फारस की खाड़ी में घुसकर जीव जगत के लिए भारी हानि पहुंचाई थी। इस प्रदूषण का असर मिट्टी, पानी और हवा तीनों पर पड़ा था। जानकारों का मानना है कि इराक युद्ध का पर्यावरण पर पड़ा दुष्प्रभाव हिरोशिमा-नागासाकी पर हुए परमाणु हमले, भोपाल गैस त्रासदी और चेरनोबिल दुर्घटना से भी ज्यादा था। इस कारण इराक का एक क्षेत्र जहरीले रेगिस्तान में तब्दील हो गया और वहां महामारी का प्रकोप भी अर्से तक रहा। समुद्री सतह पर ये तरल द्रव्य बड़ी मात्रा में फैलते हैं तो इससे जल की सतह पर एक मोटी परत बन जाती है, सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन को नीचे जाने में बाधा बन जाती है। इससे जल के भीतर स्वाभाविक रूप में जीवन व्यतीत कर रहे जीव दम घुटने से मर जाते हैं। जो जीव किसी कारण से बचे भी रहते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। तेल के कुओं और भंडार गृहों में आग लगने से तीव्र एवं जहरीली रोशनी निकलती है। यह रोशनी मधुमक्खियों जैसे परा-गणकों को प्रभावित कर उनके जीवन चक्र को बाधित कर देती है। समुद्र में जल रहा तेल पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन तेजी से बिगाड़ने का काम कर रहा है। इससे भविष्य में वैश्विक जलवायु आपातकाल की स्थिति निर्मित हो रही है। ऊर्जा असंतुलन बढ़ता रहा तो वायुमंडल का तापमान गरम होगा, जो एक साथ पृथ्वी, वायु और पानी की नमी को सोखने का काम करेगा। यह हिमनदों के बड़ी मात्रा में पिघलने का कारण बनने के साथ भारी बारिश का सबब बनेगा। जंगलों में आग लगने की घटनाएं बड़ी संख्या में देखने में आएंगी। मध्य एशिया में जल रहा यह तेल हिंद महासागर के तापमान को अप्रत्याशित रूप में बढ़ाएगा। इसका सीधा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ेगा। परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, धूल भरे अंधड़ की घटनाएं कालांतर में देखने को मिल सकती हैं।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **haribhoomi@gmail.com** पर दे सकते हैं।

सारा संसार

जम्मू कश्मीर राज्य में त्रिकुटा पहाड़ियों में समुद्रतल से 15 किमी की ऊंचाई पर स्थित माता वैष्णोदेवी मंदिर भारत के प्रसिद्ध चमत्कारी मंदिर में से एक है, जो हिंदू धर्म के लोगों के लिए आध्यात्मिकता और श्रद्धा से भरपूर है। इतनी कठिनाई पर स्थित होने के बावजूद भी यहां हर साल लाखो की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन और फरियादे लेकर आते है। वैष्णो देवी एक धार्मिक ट्रेकिंग डेस्टिनेशन है।

ज्ञान का अभिषेक

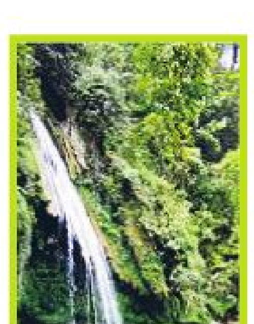

संकलित
दर्शन

अखिल ब्रह्मांड ईश्वर का स्वरूप है। श्रावण मास में बरस रही जलधारा ही ऐसी प्रतीत होती है मानो प्रकृति इस धरा का अभिषेक कर रही है। प्रकृति के इसी कृत्य का अनुकरण हम मानव भी करते हैं। श्रावण मास में हम भी शिवलिंग पर जल चढ़ा कर अपने आपको ईश्वर के उसी कृत्य के साथ जोड़ लेते हैं। ईश्वर अथवा प्रकृति के गुणों को अपनाना सदाचार है। श्रावण मास हमें यह अवसर देता है। जल जीवन है और यह धरती को पुनर्जीवित करता है। वर्षा से प्रकृति पनपती है। तपती हुई धरती पर जब वर्षा होती है तो उसे शीतलता का आभास होता है। वनस्पतियां उगने लगती हैं। पेड़ों पर नए पत्ते लगने लगते हैं। जैसे श्रावण में लोगों को गर्मी से राहत मिलती है, वैसे ही ज्ञान के श्रवण से मन को पीड़ा और बेचैनी से राहत मिलती है। श्रावण में लोग एकत्रित होकर ज्ञान-श्रवण करते हैं। दिव्य कथाएं सुनते हैं। ईश्वर का गुणगान करते हैं, जिससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। जब मन पर ज्ञान का अभिषेक होता है, तो मन शांत और शीतल हो जाता है। श्रावण को सबसे पवित्र महीना माना जाता है, क्योंकि यह अनेक धार्मिक उत्सवों और पर्वों को अपने साथ लाता है। हिंदू कैलेंडर में श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है। शिव परिवर्तन के लिए उत्तरदायी ऊर्जा हैं। शिव जीवन के मार्ग की बाधाओं को दूर करने वाले हैं। वह पुरातन को विनष्ट कर नूतन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव कल्याणकारी हैं। शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं।

आइसक्रीम की एक डिश

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक छोटा सा लड़का एक होटल में गया। कुछ ही देर में वहां वेटर आया और उसने पूछा आपको क्या चाहिए सर? छोटे बच्चे ने उल्टा पुछा! वैनिला आइसक्रीम कितने रुपए का है ? उस वेटर वाले ने जवाब दिया 50 रुपए का । यह सुन कर उस छोटे लड़के ने अपने जेब में हाँथ डाल कर कुछ निकाला और हिसाब किया । उसने दूबारा पूछा कि संतरा फ्लेवर आइसक्रीम कितने का है। वेटर ने दूबारा जवाब दिया और कहा 35 रुपए का सर। यह सुनने के बाद उस लड़के ने कहा! मेरे लिए एक संतरा फ्लेवर आइसक्रीम ले आईये। कुछ ही देर में वेटर आइसक्रीम की प्लेट और साथ में बिल लेकर आया और उस बच्चे के टेबल पर रखकर चले गया। उस लड़के ने उस आइसक्रीम को खाने के बाद पैसे दिए और वह चले गया। जब वह वेटर वापस आया तो वह दंग रहे गया यह देखकर कि उस लड़के नें खाए हुए आइसक्रीम प्लेट के बगल में आइस-क्रीम के 35 रुपए के साथ उसके लिए 15 रुपए का टिप छोड़ गया था। उस लड़के पास 50 रुपए होने पर भी उसने उस वेटर के टिप के बारे में पहले सोचा न की अपने आइसक्रीम के बारे में । उसी प्रकार हमें अपने फायदे के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा ध्यान कभी दूसरो के भलाई की और नहीं जाता। हम पहले अपनी भलाई में ही लगे रहते हैं।

संदेश
डॉ. कविता सिंधु खरीटा

पीएम का आह्वान आत्मनिर्भर भारत की ओर जागरूक कदम

आज का समय केवल विकास की दौड़ का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रहित को समझने का समय है। वैश्विक परिस्थितियों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और बदलते अंतरराष्ट्रीय समीकरणों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया "राष्ट्रहित का आह्वान" केवल एक राजनीतिक संदेश नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए जिम्मेदारी का संदेश है। यह आह्वान हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों से नहीं होता, बल्कि आम नागरिकों की छोटी-छोटी आदतों और निर्णयों से भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार "वोकल फॉर लोकल", "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" जैसे अभियानों के माध्यम से देशवासियों को स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और विदेशी निर्भरता कम करने का संदेश दिया है। उनका मानना है कि जब भारत का नागरिक अपने ही देश में बने उत्पादों पर विश्वास करेगा, तभी भारत आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेगा। यह केवल व्यापार का विषय नहीं, बल्कि देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत जैसे विशाल देश में यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में थोड़ी जागरूकता दिखाए, तो इसका प्रभाव पूरे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम स्थानीय उत्पाद खरीदते हैं, तो उससे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश का पैसा देश में ही रहता है। इसके विपरीत विदेशी वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता देश की आर्थिक शक्ति को कमजोर करती है। प्रधानमंत्री का यह आह्वान केवल आर्थिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संस्कृति सदैव आत्मसम्मान, श्रम और स्वदेशी भावना को महत्व देती रही है। महात्मा गांधी ने भी स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से यही संदेश दिया था कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची स्वतंत्रता का आधार है। आज वही भावना आधुनिक रूप में फिर से देश के सामने प्रस्तुत की जा रही है। हालांकि केवल सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं होते। नागरिकों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें यह विचार करना होगा कि क्या हम अपने निर्णयों से देशहित को प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या हम पर्यावरण, स्थानीय रोजगार और भारतीय उद्योगों के प्रति संवेदनशील हैं? यदि प्रत्येक नागरिक इन प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करे, तो भारत को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज आवश्यकता केवल नारों की नहीं, बल्कि व्यवहारिक परिवर्तन की है। राष्ट्रहित का अर्थ केवल सीमा पर देश की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे निर्णय लेना भी है जो देश को मजबूत बनाएं। स्वदेशी अपनाना, स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देना, संसाधनों का संयमित उपयोग करना और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना ,यही सच्चा राष्ट्रधर्म है। अंततः प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रहित आह्वान हमें यह सिखाता है कि देश का भविष्य केवल नीतियों से नहीं, बल्कि नागरिकों की सोच और सहभागिता से तय होता है। यदि भारत का हर नागरिक राष्ट्रहित को अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर रखना सीख जाए, तो आत्मनिर्भर, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का सपना अवश्य साकार होगा।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अंतर्मन

आज की पाती

बच्चों की पहली शिक्षक होती है मां

मां केवल एक शब्द नहीं, बल्कि जीवन की सबसे गहरी अनुभूति है। संसार में बच्चे की पहली पहचान, पहला स्पर्श, पहला भरोसा और पहली शिक्षा मां से ही शुरू होती है। किसी भी समाज की सभ्यता और संवेदनशीलता इस बात से आंकी जा सकती है कि वहां मातृत्व को कितना सम्मान और महत्व दिया जाता है। आधुनिक समय में भले ही शिक्षा के बड़े-बड़े संस्थान, डिजिटल तकनीक और करियर की दौड़ ने जीवन की दिशा बदल दी हो, लेकिन आज भी यह सत्य उतना ही मजबूत है कि बच्चे की पहली शिक्षक उसकी मां ही होती है। बच्चा जब जन्म लेता है, तब वह इस दुनिया की भाषा नहीं जानता।

-मनोज शुक्ला, जगदलपुर

X ट्रेंड

राहुल की विदेश यात्रा

2004 से 2026 के बीच राहुल गांधी की 54 विदेश यात्राओं पर लगभग 60 करोड़ रुपये खर्च हुए, जबकि घोषित आय 11 करोड़ रुपये है। यदि यह खर्च विदेशी स्रोतों से हुआ है, तो एफसीआरए की अनुमति कहां है? यदि यह निजी स्रोतों से हुआ है, तो इसका उल्लेख कर रिटर्न में क्यों नहीं है?
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

आरक्षित वन घोषित

दिल्ली के सेंट्रल रिज के 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित कर दिया है। यह निर्णय जैव विविधता के संरक्षण, पर्यावरणीय लचीलेपन में सुधार और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
- रेखा गुप्ता, सीएम, नई दिल्ली

अनावश्यक खर्चों से परहेज

मैं पिछले तीन वर्षों से इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर रहा हूं, जिसमें डीजल या पेट्रोल का उपयोग नहीं होता है। हमने हमेशा अनावश्यक खर्चों से परहेज किया है, और यही कारण है कि हमारा राज्य आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।
-सुखविंदर सिंह सुखु, सीएम, हिमाचल प्रदेश

जनता के पास अवसर

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तीन साल पहले जनता को झूठे वादे देकर सरकार बनाई थी, लेकिन आज तक वे वादे पूरे नहीं हुए हैं। इन चुनावों में जनता के पास सबक सिखाने का सुनहरा अवसर है।
-अनुराग ठाकुर, सांसद, भाजपा

करंट अफेयर

भारत ने आतंकी शेरा के प्रत्यर्पण पर पुर्तगाल का जताया आभार

लिस्बन। भारत ने मादक पदार्थ से संबद्ध वांछित आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा के पुर्तगाल से प्रत्यर्पण में समर्थन और सहयोग के लिए वहां की सरकार और उसकी एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। बुधवार को, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने पुर्तगाल से सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण के बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुर्तगाल से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही एनआईए के एक दल ने उसे हिरासत में ले लिया। वह 2020 में फरार हो गया था और पुर्तगाल चला गया था। लिस्बन स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, /"लिस्बन में भारत का दूतावास इकबाल सिंह के भारत प्रत्यर्पण में समर्थन और सहयोग के लिए पुर्तगाली अधिकारियों को धन्यवाद देता है।/" दूतावास द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पुर्तगाल से इकबाल सिंह उर्फ शेरा को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। सिंह पर मादक पदार्थ तस्करी और आतंकवाद के लिए वित्तपोषण करने सहित कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं। अब भारत में उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। बयान में कहा गया, /"भारत सरकार इकबाल सिंह के सफल प्रत्यर्पण में सहयोग और समर्थन के लिए पुर्तगाल सरकार और उसकी एजेंसियों को धन्यवाद देती है।

ऑफ बीट

क्या कॉफी वाकई कैफीन मुक्त होती है

डिकैफ़िनेटेड या 'कैफीन मुक्त' कॉफ़ी व्यापक रूप से उपलब्ध है, और इसकी खपत में वृद्धि होने की सूचना है। यहां आपको कैफीन मुक्त कॉफ़ी के बारे में जानने की आवश्यकता है: यह कैसे बनाई जाती है, स्वाद, लाभ - और क्या यह वास्तव में कैफीन मुक्त है। डिकैफ़ कैसे बनता है? कॉफ़ी बीन की सुगंध और स्वाद को बरकरार रखते हुए कैफीन को हटाना कोई आसान काम नहीं है। डिकैफ़ कॉफ़ी हरे, बिना भुने कॉफ़ी बीन्स से उनकी कैफीन सामग्री को हटाकर बनाई जाती है और इस तथ्य पर निर्भर करती है कि कैफीन पानी में घुल जाता है। कैफीन को हटाने के लिए तीन मुख्य तरीकों का उपयोग किया जाता है: रासायनिक सॉल्वैंट्स, तरल कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2), या विशेष फिल्टर वाला सादा पानी। इन सभी प्रसंस्करण विधियों में आवश्यक अतिरिक्त कदमों के कारण डिकैफ़ कॉफ़ी अक्सर अधिक महंगी होती है। अधिकांश डिकैफ़ कॉफ़ी विलायक-आधारित तरीकों का उपयोग करके बनाई जाती है क्योंकि यह सबसे सस्ती प्रक्रिया है। यह विधि दो और प्रकारों में विभाजित है: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि में कॉफ़ी बीन्स को भाप में पकाना और फिर उन्हें बार-बार एक रासायनिक विलायक (आमतौर पर मेथिलीन क्लोराइड या एथिल एसीटेट) में भिगोना शामिल है जो कैफीन से बंध जाता है और इसे बीन्स से निकालता है।

अपने विचार

हरिभूमि कायार्लय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई बैठक अभियान के समय तालमेल, एक-दूसरे की प्रणाली के साथ मिलकर काम करने की क्षमता प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और भविष्य के एयरोस्पेस सहयोग पर केंद्रित थी

भारत-ऑस्ट्रेलिया की वायु सेनाओं की अहम बैठक

दोनों देशों के बीच एयरोस्पेस और रक्षा सहयोग मजबूत करने पर बनी सहमति

एजेंसी ▶▶ कैनबरा

भारतीय वायु सेना (आईएएफ) और रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने 'भविष्य के एयरोस्पेस सहयोग' पर चर्चा की है। यह चर्चा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते रक्षा संबंधों के बीच हुई है। दोनों वायु सेनाओं के बीच हाल ही में 12वीं एयर स्टाफ वार्ता कैनबरा में हुई। यह वार्ता दोनों देशों के बीच अभियान के समय तालमेल, एक-दूसरे की प्रणाली के साथ मिलकर काम करने की क्षमता (इंटरऑपरेबिलिटी), प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और भविष्य के एयरोस्पेस सहयोग पर केंद्रित थी।

दोनों देशों के बीच 12वीं एयर स्टाफ वार्ता ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में हुई

12वीं एयर स्टाफ वार्ता के दौरान दोनों देशों के एयर वाइस मार्शल

हिंद-प्रशांत महासागर में साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध

आईएएफ ने बयान में कहा है कि 12वीं एयर स्टाफ वार्ता में दोनों वायु सेनाओं ने ऑपरेशनल तालमेल बढ़ाने, संयुक्त अभ्यास, एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग समझौते, प्रशिक्षण और भविष्य के एयरोस्पेस सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय स्थिरता और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने और भविष्य के लिए तैयार हिंद-प्रशांत साझेदारी के प्रति अपनी

वायु शक्ति संवाद को आगे बढ़ाएंगे

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वायु सेना के उप प्रमुख एयर वाइस मार्शल स्टीवन पेस ने कैनबरा और ब्रिस्बेन में भारतीय वायु सेना के एयर वाइस मार्शल संजीव तालियान की मेजबानी की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और पेशेवर वायु शक्ति संवाद को आगे बढ़ाया गया।

एयर वाइस मार्शल संजीव तालियान और एयर वाइस मार्शल स्टीवन पेस

एमक्यू-28 घोस्ट बैट क्यों खास है?

एमक्यू-28 घोस्ट बैट एक 'फोर्स मल्टीप्लायर' है, यानी यह आधुनिक वायु शक्ति प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाता है। इसकी खुली प्रणाली (ओपन सिस्टम) डिजाइन से मिशन में लचीलापन आता है।

40 फीट की ऊंचाई पर काम करने में सक्षम

एमक्यू-28 की एक खासियत इसका टुकड़ों में बनने वाला (मॉड्यूलर) डिजाइन है, जिससे मिशन वाला आगे का हिस्सा (नोज सेक्शन) बदलकर उसमें अलग-अलग उपकरण तेजी से लगाए जा सकते हैं। बोइंग के अनुसार यह 2,000 नॉटिकल मील से ज्यादा दूरी तक उड़ान भर सकता है, मैक 0.9 तक की गति से उड़ सकता है और 40 हजार फीट से अधिक ऊंचाई पर काम कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले आठ वर्षों में विकसित इस प्रणाली को बोइंग ने 'दुनिया का सबसे परिपक्व सहयोगी लड़ाकू विमान' बताया है।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक में 'राष्ट्रीय बयान' के जरिए जयशंकर ने दुनिया के सामने साफ किया नई दिल्ली का रुख

पश्चिम-एशिया संकट, गाजा, एकतरफा प्रतिबंधों, फिलिस्तीन, आतंकवाद और यूएन में सुधार जैसे मामलों पर खुलकर रखे विचार

ब्रिक्स के मंच से भारत का दुनिया को बड़ा संदेश बातचीत और कूटनीति से ही हल होंगे विवाद

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

अमेरिका-इजरायल और ईरान से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से लगातार बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बीच गुरुवार को राजधानी के भारत मंडपम में ब्रिक्स समूह के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक की शुरुआत हुई। विदेश मंत्री डॉ.एस.जयशंकर ने 'राष्ट्रीय बयान' के जरिए पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ देश का पक्ष रखा। जिसमें पश्चिम-एशिया, गाजा संकट, एकतरफा प्रतिबंधों, फिलिस्तीन का मुद्दा, आतंकवाद और संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में अनिवार्य सुधार जैसे मामलों को शामिल किया गया है।

बैठक में ईरान, दक्षिण-अफ्रीका, ब्राजील और रूस समेत समूह के अन्य देशों के विदेश मंत्री मौजूद रहे। इस वर्ष भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता की जिम्मेदारी है। इसलिए वह इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। आगामी समय में सितंबर महीने में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। उसके पूर्व में इस बैठक का होना काफी महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने डॉ.जयशंकर के बयान को मीडिया के साथ साझा किया है।

होर्मुज से चाहिए सुरक्षित समुद्री आवाजाही: जयशंकर ने कहा, वर्तमान में हमारे द्वारा महसूस की जा रही घटनाएं छिटपुट रूप से हो नहीं हो रही हैं। बल्कि यह चुनौतियों का एकजुट होना है। जो बहुआयामी सिस्टम के लचीलेपन की परीक्षा ले रही हैं। खासकर पश्चिम-एशिया विवाद, जिससे लगातार तनाव के साथ सुरक्षित समुद्री आवाजाही के लिए खतरा बढ़ रहा है। वहीं, ऊर्जा ढांचों के समक्ष आ रही बाधाओं से हालात और तनावपूर्ण हो रहे हैं। ऐसे में वैश्विक आर्थिक भलाई के लिए होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की गति को बनाए रखने की नितांत

आवश्यकता है। आज की हमारी मुलाकात और उससे इतर दुनिया एक असाधारण भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता से दो-चार हो रही है। जिसमें संघर्षों, जलवायु घटनाओं और कोरोना महामारी के बाद पड़े प्रभावों की मुख्य भूमिका है। ये घटनाक्रम विकास के क्रम को कमजोर करते हुए असुरक्षा की भावना को बढ़ाते हैं। लेकिन भारत तनाव को कम करने और मौजूदा चुनौतियों से निपटने में एक रचनात्मक और स्थिर भूमिका निभाएगा।

बातचीत-कूटनीति से निकले समाधान: उन्होंने कहा कि कई मामले ऐसे हैं, जिनका प्रभाव संबंधित क्षेत्र से बाहर भी बड़े पैमाने पर पड़ रहा है। जिसमें भी ऊर्जा, खाद्य-उर्वरक सुरक्षा, सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों, कीमतों में बढ़ते ट्रेंड और प्रभावित होते विकास के चलते उभरते हुए बाजार और विकासशील देश बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जिसे देखते हुए ब्रिक्स की एकजुटता, सद्भावना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है।

सामूहिक कदम और संकल्प स्थिरता, सतत विकास और समृद्धि के लिए बेहद जरूरी हैं। समूह इन विषयों पर केवल विचार-विमर्श नहीं करेगा। बल्कि प्रभावी-समन्वित प्रतिक्रिया की दिशा में भी काम करेगा। भारत यूएन के उद्देश्यों, सिद्धांतों को लेकर मजबूती के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बुनियाद होनी चाहिए। साथ ही विवादों का समाधान निकालने का एकमात्र उपाय बातचीत और कूटनीति पर ही आधारित होना चाहिए।

अमेरिकी टैरिफ, प्रतिबंधों पर खरी-खरी: जयशंकर ने अमेरिका का नाम सहित उल्लेख किए बिना दो टूक अंदाज में कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों और यूएन सिद्धांतों के विरूद्ध लगाए गए एकतरफा प्रतिबंधों, दंडात्मक उपाय विकासशील देशों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दबाव की राजनीति का विकल्प संवाद कभी भी नहीं बन सकता है। मौजूदा चुनौतियों के चलते बढ़ती विषमताओं के साथ विकास बाधित हो रहा है। कई विकासशील देशों के लिए प्राथमिकता महज विकास नहीं है। बल्कि तेजी से बढ़ती वैश्विक परिस्थितियों से उत्पन्न होती असुरक्षा को संभालना है। स्थिरता चयनात्मक नहीं हो सकती और शांति कभी टुकड़ों में नहीं आ सकती है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों की स्थापना, नागरिकों की सुरक्षा, असैन्य ढांचों पर हमलों को रोकने की आवश्यकता है।

फिलिस्तीन मामला:द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को समर्थन: उन्होंने गाजा संकट को लेकर कहा कि गाजा में जारी संघर्ष का बड़े पैमाने पर मानवीय प्रभाव पड़ा है। इसलिए सतत संघर्षविराम, बेरोकटोक ढंग से मानवीय सहायता की आपूर्ति को बरकरार रखने और समस्या के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर भरोसेमंद मार्ग के जरिए आगे बढ़ना नितांत रूप से आवश्यक है। जहां तक फिलिस्तीन के मामले का सवाल है, तो भारत इसे लेकर द्वि-राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। लीबिया, सीरिया भी लगातार चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। सुडान संघर्ष ने भारी मानवीय कीमत चुकाई है। यमन से मानवीय चिंताएं, समुद्री जोखिम बढ़ा है। जबकि लीबिया में स्थिरता महत्वपूर्ण है। इन सभी मामलों को लेकर अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों और समन्वित कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है।

आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता: विदेश मंत्री ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा, इस लगातार बने हुए खतरे की किसी भी प्रकार से कोई सफाई या स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। सीमापार आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस वैश्विक बुराई को लेकर बिना किसी समझौते के साथ शून्य सहिष्णुता का नियम लागू होना चाहिए। तकनीकी उन्नति वैश्विक परिदृश्य को पुनः आकार दे रही है। जिसमें वह अवसरों को प्रदान कर रही है। लेकिन उसमें विश्वास, पारदर्शिता और समानता आधारित पहुंच जैसी चिंताएं बनी हुई हैं। डिजिटल खाई को साझा प्राथमिकता के तहत भरा जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन लगातार एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। जिसके साथ जलवायु न्याय, भरोसेमंद प्रतिबद्धता, पर्याप्त वित्त की व्यवस्था और पहुंच आधारित सहयोग भी शामिल होने चाहिए।

चुनौतियों से कमजोर होता सिस्टम: चुनौतियों के बढ़ने के साथ ही यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुपक्षीय सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। जिसके केंद्र में यूएन का सिस्टम है और इसे लेकर चिंताएं काफी बढ़ गई हैं। अब हर गुजरते दिन के साथ बहुपक्षवाद में जरूरी सुधार ही एकमात्र विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसमें यूएन की स्थायी और अस्थायी जैसी दोनों श्रेणियों में सुधार का मसला शामिल है। मामले में हो रही देरी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

ब्रिक्स का यही साफ संदेश: उन्होंने कहा कि सहयोग जरूरी है, संवाद की आवश्यकता है और सुधार बाकी है। ब्रिक्स देशों को एक अधिक स्थिर, समानता आधारित समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लेकर एकजुटता का कार्य करने की दरकार है। भारत इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी साझेदारों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ तैयार है।

फर्जी खाते और जाली दस्तावेजों के जरिए बैंक ऑफ इंडिया को लगाया चूना, कई राज्यों में तलाश के बाद गिरफ्तारी

यूपी वन निगम के नाम पर 64.82 करोड़ की ठगी, सीबीआई ने दो आरोपियों को दबोचा

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तर प्रदेश वन निगम (यूपीएफसी) के नाम पर करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में दीपक सुर्वना और दीपक यादव नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर 15 जनवरी को केस दर्ज किया गया था।

सीबीआई के अनुसार, आरोपियों ने अज्ञात लोकसेवकों और अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए बैंक ऑफ इंडिया की सदर शाखा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश वन निगम के नाम पर फर्जी बैंक खाता खुलवाया। इसके लिए जाली केवाईसी दस्तावेज, फर्जी प्राधिकरण पत्र और नकली बोर्ड प्रस्तावों का इस्तेमाल किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपियों ने फर्जी

दस्तावेजों के आधार पर बैंक को यह विश्वास दिलाया कि यूपीएफसी की ओर से सावधि जमा (एफडीआर) बनाई जानी है।

इसके बाद बैंक से 64.82 करोड़ रुपये उक्त खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। बाद में आरोपियों ने इनमें से 6.95 करोड़ रुपये आरटीजीएस के माध्यम से कोलकाता और नई दिल्ली स्थित छह फर्मों के खातों में भेज दिए। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश वन निगम के अधिकारियों ने बैंक को सूचित किया कि इस तरह का कोई प्राधिकरण जारी नहीं किया गया था और गिरफ्तार आरोपियों का निगम से कोई संबंध नहीं है।

मामले की जांच के दौरान सीबीआई टीम ने फरार आरोपियों की तलाश में कई राज्यों में व्यापक अभियान चलाया। लगातार निगरानी, समन्वित छापेमारी और फील्ड ऑपरेशन के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अदालत (पश्चिम), लखनऊ के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 16 मई तक हिरासत में भेज दिया।

अगले साल होने हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, हर हाल में अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि यूपी में जल्द ही पार्टी संगठन, निगमों और आयोगों में जो नियुक्तियां होने जा रही हैं उनमें सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और सहयोगी दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। हाल ही में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद यह योगी की पहली दिल्ली यात्रा थी।

ज्ञात हो कि हाल ही में पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनावों में शानदार प्रदर्शन के साथ पूर्वी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने के बाद भाजपा की नजर अब 2027 में होने वाले सात राज्यों के विधानसभा चुनावों पर है, जिनमें गुजरात, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश प्रमुख हैं।

बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भाजपा की गतिविधियों का केंद्र रहने वाला है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री,

तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अब लगातार यूपी के दौरे होते रहेंगे जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान उठाना पड़ा था इसलिए भाजपा नेतृत्व उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को लेकर खासा सतर्क है। माना जा रहा है कि यूपी के मामलों को सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देखेंगे ताकि राज्य विधानसभा चुनावों में भाजपा की हैट्रिक में कोई कमी नहीं रह जाये। सूत्रों के अनुसार योगी और शाह की मुलाकात आधे घंटे से ज्यादा समय तक चली। इस दौरान नये बनाये गये मंत्रियों के विभागों को लेकर भी चर्चा हुई। पार्टी सूत्रों का कहना है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा संगठन की सारी कमजोरियों को दूर कर लेना चाहती है और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी दूर करना चाहती है जिसके लिए आने वाले दिनों में तमाम कदम उठाए जाएंगे।

पार्टी ने इन राज्यों में चुनाव की तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अगले वर्ष के चुनावी अभियान के लिए जमीनी स्तर पर काम प्रारंभ कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का दौरा कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इस दौरान उन्होंने पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों व नेताओं के साथ बैठकें कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। वह जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करेंगे, जहां अगले वर्ष गोवा, गुजरात, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव होने हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भाजपा की सरकार है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में है।

दिल्ली लाल किला ब्लास्टः एनआईए ने कोर्ट में दाखिल की 7500 पन्नों में चार्जशीट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को नई दिल्ली की एक विशेष अदालत में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 की शाम को हुए कार बम धमाके के मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एजेंसी ने इस हमले में कथित संलिप्तता के लिए 10 लोगों को नामजद किया है। इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। एनआईए के अनुसार, सहित सभी 10 आरोपी संगठन 'अंसार गजवत-उल-हिंद (एजीयूएच)' से जुड़े थे, जिसे अल-कायदा से प्रेरित संगठन बताया गया है। मुख्य आरोपी उमर उन नबी की इस धमाके में मौत हो गई थी। उसके अलावा नौ अन्य आरोपियों के नाम भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं जिनमें आमिर मीर, जसीर वानी, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील राथर, डॉ. शाहीन सईद मुफ्ती इरफान अहमद वागे, सोयाब, डॉ. बिलाल नसीर मल्ला और यासिर अहमद डार शामिल हैं।

हरिभूमि कम्यूनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक देवेन्द्र सिंह बाल्यान द्वारा हरिभूमि पब्लिकेशंस, चुलियाना मोड़, दिल्ली रोड, रोहतक-124517 से मुद्रित एवं हरिभूमि कार्यालय, 129, ट्रांसपोर्ट सैंटर, पंजाबी बाग, पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : डॉ.हिमांशु द्विवेदी। आरएनआई नं 69631/1998, फोन : 011-40451115/16, 40451109